हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

25 मार्च, 2008

खण्ड-1, अंक-12

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

विषय सूची

मंगलवार, 25 मार्च, 2008

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(12)1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(12)24
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना	(12)25
वाक-आऊट	(12)28
एक किसान की मौत के कारण आन्दोलन सम्बन्धी मामला उठाना	(12)30
वर्ष 2008-2009 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(12)31
बैठक का समय बढ़ाना	(12)73
वर्ष 2008-2009 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(12)73
विधान कार्य—	
दि पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्किटस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2008	(12)74
दि हरियाणा कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजज बिल, 2008	(12)76
बैठक का समय बढ़ाना	(12)79
दि हरियाणा कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजज बिल, 2008 (पुनरारम्भ)	(12)79
बैठक का समय बढ़ाना	(12)81
दि हरियाणा कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजज बिल, 2008 (पुनरारम्भ)	(12)81

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 25 मार्च, 2008

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात: 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री रघुबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, Question hour.

Illegal Recruitment of Deputy Director (A.H.)

***878. Sh. Karan Singh Dalal :** Will the Animal Husbandry & Dairying Minister be pleased to state :—

(a) whether the State Govt. had amended the Haryana Veterinary (group A) Service Rules, 1995 vide its notification dated 6.9.2002 thereby taking away the provision of direct recruitment to the post of Deputy Director (A.H.) or equivalent, if so, the details thereof ;

(b) whether even after the amendment in (a) above vide its notification dated 6.9.2002, the Haryana Pubic Service Commission advertised four posts of Deputy Director (A.H.) vide advertisement dated 18.9.2002 in spite of the abolition of provision of direct recruitment ;

(c) whether selection and recruitment of above advertised posts of Deputy Directors (A.H.) was challenged in the Hon'ble High Court ; and

(d) the action taken by the Government against these illegal recruitment ?

Agriculture Minister (Sardar H.S. Chatha) : Sir, a statement is placed on the Table of the House.

Statement

(a) Yes Sir. In Haryana Veterinary (Group A) Service Rules, 1995 there was provision to fill up the 25% posts of Deputy Directors by direct recruitment and 75% by promotion. Vide notification dated

[Sardar H.S. Chatha]

6.9.2002 an amendment was made to the rules 1995 wherein the provision of direct recruitment to the post of Deputy Directors was abolished thereby making all the posts of Deputy Directors promotional posts.

(b) Yes Sir. However, the requisition to fill up 4 posts of Deputy Directors was sent to Haryana Public Service Commission before the amendment in the said rules vide letter dated 20.8.02.

(c) Yes Sir. However, the writs vide which appointments were challenged were withdrawn.

(d) Sir the matter is under consideration of the Govt. and appropriate action will be taken shortly.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो पिछली सरकार के दौरान यह भद्दा मज़ाक किया गया कि एक तरफ खुद सरकार ने वैटेनरी डिपार्टमैंट ग्रुप-ए के सर्विस रूल्ज़ को अमैंड कर दिया। यह माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में भी माना है। अध्यक्ष महोदय, उसमें तत्कालीन सरकार द्वारा रूल्ज़ में अमैंडमैंट करके कृषि उप निदेशक के पदों को डायरैक्ट रिक्रूटमैंट के माध्यम से भर्ती करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा जो सदन को जानकारी दी गई है इसके बावजूद भी इन डी०डी०ए० जैसे महत्त्वपूर्ण पदों पर जो उन दिनों हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे उन्होंने अपने चहेतों को और अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि उप निदेशक के पदों को डायरैक्ट रिक्रूटमैंट के माध्यम से भर लिया। अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पैसिफिक सवाल यह है कि क्या माननीय मंत्री जी यह मानते हैं कि ये नियुक्तियां गलत और गैर कानूनी हैं और अगर हैं तो उनके खिलाफ ये क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

सरदार एच०एस० चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि पहले कृषि उप निदेशक के पदों को 25 प्रतिशत डायरैक्ट रिक्रूटमैंट के जरिए भरा जाता था और 75 प्रतिशत पदों को बाई प्रोमोशन भरा जाता था। लेकिन 9.2.2002 को यह अमैंडमैंट कर दी गई कि इन पदों पर कोई भर्ती डायरैक्ट रिक्रूटमैंट से नहीं की जायेगी। लेकिन अनफॉरचूनेटली इसके केवल 12 दिन बाद हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने डायरैक्ट रिक्रूटमैंट के लिए पोस्टें एडवरटाईज़ कर दी और स्पीकर सर, उसके बाद 9.12.2004 को गवर्नमैंट को इनकी सिलैक्शन लिस्ट भेज दी गई और 12.12.2004 को इनको अप्वायंटमैंट मिल गई। जहां तक माननीय सदस्य के दूसरे सवाल का सम्बन्ध है, उसमें मैं एक बात और एड कर देता हूं कि दलाल साहब के पास पूरी इन्फर्मेशन नहीं थी। सवाल तो इन्होंने पुट किया लेकिन इसमें एक और बात थी इसमें पांच पोस्टें और थी जो उन्होंने लिस्ट दी है उसके अलावा एक लिस्ट और भी है और उसकी कहानी और भी अजीब है। उसकी रिक्वीजीशन 17.1.2003 को भेजी गई और

हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा 16.5.2003 को ये पोस्टें एडवरटाईज्ड कर दी गई और 16.1.2003 को रिकमैंडेशन की गई और डेढ़ साल बाद 23.1.2004 को उनकी रिक्रूटमैंट हो गई। जहां तक इनके सवाल की बात है तो मैं सर्विस मैटर का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन मोटे तौर पर मैं यह समझता हूँ कि ये नियुक्तियां गलत हैं। इसके साथ-साथ मैंने इनके मुतल्लिक एल०आर०, हरियाणा से भी ऑपिनियम ली है। एल०आर० द्वारा इस केस में दिया गया ऑपिनियन कुल मिलाकर पांच लाईनों में ही है अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसे पढ़कर सुनाना चाहूंगा।

"The quota of direct recruitments for the post of Deputy Director (Animal Husbandry) was abolished vide amendment in Haryana (Group-A) Service Rules, 1995 on 6.9.2002. The posts of Deputy Director Veterinary (Animal Husbandry) by way of direct recruitment were subsequently advertised by the Haryana Public Service Commission on 18.9.2002. Therefore, after the amendment of the said Rules, the appointments in question by way of direct recruitment are not in order, being in contravention to the amended Rules."

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जब एल०आर० भी इस बात को मानता है और उस समय के आयुक्त, पशुपालन विभाग ने भी एच०पी०एस०सी० को लिखकर सूचना दी थी कि रूल्ज संशोधित हो चुके हैं। उन्होंने यह प्रोसैस इसलिए जारी रखा कि उसमें एच०पी०एस०सी० के चेयरमैन, मैम्बर्स के रिश्तेदार मुख्यमंत्री और उनके बेटों के चहेते थे जिन्होंने रिश्वत देकर इन पदों को प्राप्त किया। क्या यह भी सही है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री या उनके बेटे अजय सिंह चौटाला के नोट पर यह सारा प्रोसैस पूरा हुआ है? क्या डिपार्टमैंट ने मुख्यमंत्री के बेटे द्वारा लिखे गये नोट को ग्राऊंड बनाकर फाईल चला दी? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस बारे में किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की है?

सरदार एच०एस० चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह नहीं पूछा कि यह सही है या सही नहीं है लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि अगर यह बात सही है तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इस केस में हेरा-फेरी नहीं होगी और इस केस का पूरा फैसला किया जायेगा। यह बात नहीं है कि इसमें ज्यादा देर लगेगी हम 30 दिन के अन्दर ही इसका फैसला कर देंगे।

Shri Phool Chand Mullana : Mr. Speaker Sir, it stands proved that the decision was faulty and no public interest was involved in it. Only personal interest was involved in it. I would like to know what criminal action is being initiated by the Government and in how much time ?

श्री अध्यक्ष : मुलाना साहब, यह बात मंत्री जी ने बता दी है कि हम एक महीने के अन्दर ही इसका फैसला कर देंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी इस बात से वाकिफ हैं कि पिछली सरकार की गलत नियुक्तियों की वजह से हरियाणा के सारे पशु, जिनकी

[श्री कर्ण सिंह दलाल]
आपका विभाग देखभाल करता है, रो रहे हैं क्या उनका कोई इलाज मंत्री जी करेंगे?

Deaths Due to Electrocution

***818. Sh. Radhey Shyam Sharma Amar :** Will the Power Minister be pleased to state :—

(a) whether it is fact that a number of persons and cattles have died from electrocution due to the iron poles of electricity in Narnaul constituency ;

(b) if so, the details thereof together with the time by which these iron poles are likely to be replaced with cemented poles ; and

(c) the time by which the Power Sub-Stations constructed in village Dholera, Tehsil Narnaul will be commissioned ?

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

(a) Sir. No person has died from electrocution due to iron poles in Narnaul constituency in the last 3 years. However, 3 nos. cattle died of electrocution due to iron poles.

(b) Out of 460 iron nos. poles existing in Narnaul constituency, 80 nos. iron poles have been replaced with cemented/PCC poles up to 29.2.08. The work of replacing the remaining iron poles is going on and the work is likely to be completed in 2008-09.

(c) The work for the new 33 KV Sub-Station at Dholera is in progress and is likely to be completed by 31.3.2008. Cost of construction of this substation is Rs. 170 lacs approximately.

श्री राधे श्याम शर्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक आदमी के दोनों हाथ कट गये, which is worst than death. उसके लिए क्या महकमा कुछ करेगा? इसके साथ ही साथ एक प्रश्न मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के 18 गाँव हैं जहां पर 33 के०वी० सब-स्टेशन बनाने के लिए सर्वे किया गया है, उस पर कब तक कार्यवाही शुरू करेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो प्रश्न पूछे हैं वे बिल्कुल अलग-अलग प्रश्न हैं। ए० और बी० पृथक विषय के प्रश्न हैं और सी० तो बिल्कुल ही अलग है लेकिन फिर भी जिस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है, हम सबकी सहानुभूति भी उनके साथ है। मैं माननीय साथी से कहना चाहूंगा कि वे पूरे तथ्य लिख कर मुझे भिजवा दें तो हमारा जो सम्बन्धित दक्षिण हरियाणा

बिजली वितरण निगम है, मैं उनसे कहूंगा कि उचित कार्रवाई करके उचित मुआवजा दिलवा दें। जहां तक दूसरे सब-स्टेशन की कम्पलीशन का प्रश्न है, यह लिखकर मुझे भिजवा दें तो मैं उसका जवाब भिजवा दूंगा।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष जी, इस प्रकार के एक्सीडैंट्स हो रहे हैं और बिजली की चोरियां भी हुई हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि क्या सरकार ऐसा कोई प्रोविज़न करने जा रही है कि जो बिजली की तारें हैं उनको अण्डरग्राउंड कर दें? अगर इसका जवाब नहीं में है तो मैं यह रिक्वैस्ट भी करूंगी कि सरकार को ऐसा प्रोविजन करना चाहिए, क्या सरकार इस बारे में विचार करेगी?

श्री अध्यक्ष : वह एडवान्समैंट के साथ हो जाएगा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जी का प्रश्न वाजिब है और इनकी चिन्ता भी वाजिब है, इन दोनों बातों से अपने आपको जोड़ते हुये मैं आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूंगा कि इलैक्ट्रिसिटी थैफ्ट को रोकने के लिये, इलैक्ट्रिसिटी लाईन लॉसिज को कम करने के लिये और हमारी वितरण प्रणाली सुदृढ़ बने इसके लिये हमने एक कम्प्रिहैन्सिव प्रोग्राम बनाया है। ए०बी०सी० केबल PVC coated होती है और उस तार पर स्पैशल कोटिंग होती है। गलती से अगर हाथ भी लग जाये तो उससे करण्ट नहीं लगता है। बहुत से गाँवों में हमने इसको चालू किया है और इनके जिला करनाल के अन्दर भी हमने इसकी शुरुआत की है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ एच०वी०डी०एस० प्रोग्राम हमने शुरू किया है जिसके तहत ग्यारह हजार के०वी० की लाईन सीधे गाँव में आएगी और हर तीन या चार घरों में लोड के मुताबिक ट्रांसफारमर्ज रखे जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा कॉम्प्रिहैंसिव प्रोग्राम है। इसके तहत बिजली की वोल्टेज और बिजली की सुचारू सप्लाई दोनों के अन्दर मदद मिलती है। अध्यक्ष महोदय, सरकार को इसके लिये काफी खर्चा वहन करना होगा लेकिन लाँग रन में इससे प्रान्त के लोगों को काफी लाभ होगा और इलैक्ट्रिसिटी कम्पनियों को भी इसका लाभ होगा क्योंकि इससे लाईन लॉसिज कम हो जाते हैं और ट्रांसफारमर्ज भी नहीं जलते। इसका यह भी लाभ है कि आप हर रोज ट्रिपिंग देखते हैं और कई बार आपने गांवों में देखा होगा कि लाईट तो जलती है लेकिन वह बहुत ज्यादा डिम या न के बराबर ही होती है। एच.वी.डी.एस. जहां-जहां होती है वहां ये समस्याएं नहीं रहेंगी। हमने कहा है कि हम पूरे हरियाणा में इसको करने को तैयार हैं। हमारे पास इसके लिए संसाधन भी उपलब्ध हैं परन्तु गांवों के सभी लोगों को इसके लिए कनैक्शन्ज़ लेने पड़ेंगे क्योंकि उसके बाद गांव के अन्दर कुण्डी कनैक्शन बन्द हो जाते हैं लेकिन सप्लाई सुचारू हो जाती है। ट्रिपिंग नहीं होती। बैटरी वोल्टेज और बैटर इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई उन्हें मिलती है। अध्यक्ष महोदय, हमने जो तीसरा कार्यक्रम शुरू किया है वह segregation of feeders है। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने मुख्यमन्त्री बनने के बाद हमें स्पष्ट रूप से यह आदेश दिये थे कि इलैक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज को गांवों में सुचारू सप्लाई देकर प्रभावी बनाएं। गांवों और शहरों में बिजली की अतिरिक्त सप्लाई हम दे सकें इसलिए हमने यह सोचा है कि जो हमारे रूरल डोमैस्टिक फीडर्ज हैं और उनके ऊपर जो ट्यूबवैल्ज के फीडर्ज हैं उन्हें सैग्रिगेटिड

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
कर दिया जाए। यह नेशनवाईड प्रोग्राम है और इसमें हमारा प्रान्त पूरे देश में सबसे अग्रणी है। हमें उम्मीद है कि इस साल के अन्दर दिसम्बर, 2008 तक हम हर गांव के अन्दर segregation of feeders का कार्यक्रम पूरा कर लेंगे इससे आप पाएंगे कि गांवों के अन्दर बिजली सप्लाई की समस्या समाप्त हो जाएगी। हम टयूबवैल्ज से जुड़े हुए हैं और कई बार ओवर लोडिंग की वजह से ट्रिपिंग और दूसरी समस्याएं आती है। अध्यक्ष महोदय, यह समस्या लगातार चलती रहने वाली समस्या है। यह इस सरकार की समस्या नहीं है बल्कि हर सरकार के समय में यह समस्या रही है। हमें उम्मीद है कि दिसम्बर, 2008 तक जब segregation of feeders complete हो जाएगा तो हम हरियाणा के गांवों को इस समस्या से निजात दिला पाएंगे। स्पीकर सर, जहां तक अण्डरग्राउंड वायरिंग का प्रश्न है, इस प्रकार का कोई विचार हमारे पास पैंडिंग नहीं है। इसके कारण रैस्ट ऑफ बैनिफिट रेशो इतनी ज्यादा है कि यह हमारे कंसिडिरेशन में नहीं है अब यही तीन different measures हम ले रहे हैं।

श्री फूल चन्द मुलाना : स्पीकर सर, सरकार का यह बहुत ही अच्छा निर्णय है कि आयरन पोल्ज सीमैंट वाले पोल्ज से रिप्लेस कर दिए जाएंगे। नारनौल के बारे में तो यह उत्तर आ गया है लेकिन सारे प्रान्त में यह आयरन पोल्ज कब तक रिप्लेस कर दिए जाएंगे और दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि जैसे सुमिता सिंह जी ने कहा है कि गांवों में या शहरों के मुहल्लों में बहुत सारी तारें नीचे लटकी हुई हैं और कई बार उनके कारण हादसे भी होते हैं। कई बार छतों पर करण्ट लगने के कारण लोगों की मौतें भी होती हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन तारों को कब तक ठीक कर दिया जाएगा?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मुलाना साहब की बात वाजिब है। जहां तक replacement of iron poles की बात है, इसके लिए हमने एक प्रोग्राम चलाया है। हर जिले में आप यह पाएंगे कि number of poles is very large, Sir, it is very difficult to give a date at this point of time by which this programme will be completed. But in every district we are replacing hundreds of poles with PVC and RCC poles every month. यह हमारा एक समयबद्ध टारगेट है लेकिन मेरे लिए इन्होंने जो कहा है उसके लिए इनको समय सीमा बताना मुश्किल होगा। जहां तक इन्होंने बिजली की तारों की बात कही है इसमें दो किस्म की समस्याएं हैं और मुलाना साहब इससे वाकिफ हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने पहले इलैक्ट्रीसिटी लाईन खींच ली, मगर बाद में पॉपुलेशन के प्रैशर की वजह से शहरों में नई कालोनीज बनने लग गई। अध्यक्ष महोदय, पॉपुलेशन के प्रैशर की वजह से लोगों ने तारों के नीचे भी मकान बना लिए हैं जिसकी वजह से यह दिक्कत आ रही है। अध्यक्ष महोदय, यह एक समस्या है। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि कई बार ये लाईन्ज बदली जा सकती हैं लेकिन उसके लिए पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। जहां-जहां पर भी यह संभव हो सकता है हम वहां पर जरूर चेंज करते हैं लेकिन उसके लिए पैसे जमा करवाने आवश्यक हैं। दूसरे इन्होंने तारें खींचने

के बारे में प्रश्न पूछा है। अध्यक्ष महोदय, जहां इस किस्म की ढिलाई है और जैसे ही इस बारे में कोई सम्मानित सदस्य बताता है या पब्लिक का नुमाइंदा जानकारी देता है तो हमारा इस बारे में प्रयास रहता है कि वह भी जल्दी से जल्दी हो जाए।

श्री सोमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से इन्होंने नारनौल के बारे में आश्वासन दिया है, उसी तरह से मेरी कांस्टीचुएंसी लौहारू के अन्दर प्रोपर बहल में भी और दूसरे गांवों में भी लोहे के बहुत ज्यादा खंभे लगे हुए हैं। क्या वहां पर भी मंत्री जी उनको इस साल के अन्दर बदलवाने का आश्वासन देंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी जी को और सदन को यह बताना चाहूँगा कि पूरे प्रान्त में एक साथ खंभे बदलवाना संभव नहीं होगा। इस समय पूरे प्रान्त की रेडी फिगर मेरे पास नहीं है। जहां तक माननीय सदस्य ने सवाल किया है तो ये इस बारे में हमें लिखित में भिजवा दें। मैं इस बारे में माननीय सदस्य को आश्वासन दूंगा कि उन गांवों में खंभे बदलने का हमारा प्रयास रहेगा और उनको इसी साल में बदलवाने की भी कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये जो पोल हैं ये चार दशक पहले के लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, हम मानते हैं कि जब भी बारिश होती है तो वहां पर पशुओं और व्यक्तियों को शार्ट सर्किट की वजह से करंट लगने का भय रहता है। इसलिए हमने इन पोलों को बदलने का कार्यक्रम शुरू किया है और हम बदलते जा रहे हैं। आप हमें लिखकर भिजवाएं हम उनको जल्दी से जल्दी बदलवाने का काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस साल में यह कार्य पूरा हो जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए इनके महकमें के द्वारा क्या कोई कदम उठाये जा रहे हैं। क्योंकि जैसे विदेशों में होता है कि वहां पर तारें नंगी पड़ी होती हैं लेकिन किसी को करंट का भय नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, हमने कई देशों में देखा है कि वहां पर रेल के नीचे सरेआम नंगी तारें ट्रैक पर होती हैं और उस पर ट्रेनें चलती हैं, लेकिन किसी को भी करंट नहीं लगता है। वहां जो 120 ए०सी०/डी०सी० या 220 ए०सी०/डी०सी० का उनका प्रोसैस है, क्या उस तकनीक को अपने प्रदेश में लागू करवाएंगे ताकि उससे किसी को नुकसान न हो सके?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दलाल साहब को बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही काबिल आदमी हैं। इनको मालूम भी होगा और अगर मालूम नहीं है तो मैं इनको बता दूं कि हिन्दुस्तान की इलैक्ट्रीसिटी लाईन्ज़ 220 की वोल्टेज पर हैं न कि 110 या 120 की वोल्टेज पर हैं। अध्यक्ष महोदय, असैंशियली अमेरिका, इंग्लैंड और दूसरे मुल्कों में डिफरैंट वोल्टेज है। बट लार्जली पूरी दुनिया की इलैक्ट्रीसिटी लाईन्ज़ 220 वोल्टेज के सिस्टम पर हैं इनको 110 पर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, न ही 220 को 110 पर कन्वर्ट करने का कोई विशेष

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
लाभ है। अध्यक्ष महोदय, जब मैं बिजली मंत्री बना था तो मैंने एक स्पैसिफिक प्रश्न बिजली अधिकारियों से पूछा था। अध्यक्ष महोदय, इस वोल्टेज प्रणाली की जिस समय में अडॉप्शन की गई थी, उस समय कुछ देशों ने किसी दूसरी प्रणाली के तहत इसकी अडॉप्शन कर ली थी। अध्यक्ष महोदय, आपने यह भी देखा है कि अमेरिका में बाईं तरफ गाड़ियां चलाई जाती हैं और हम दाईं तरफ चलाते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह एक अडॉप्शन ऑफ सिस्टम की बात है, मुझे नहीं लगता कि इससे बिजली के करंट लगने का कोई वास्ता है। बिजली के करंट लगने का कोई और कारण हैं जिसके बारे में माननीय सदस्या श्रीमती सुमिता सिंह जी ने प्रश्न पूछा था और मैंने तफसील से बताया भी था कि हम क्या-क्या मईयर्ज ले रहे हैं। इस बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है।

श्री रणधीर सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मेरे हल्के के एक-दो गांवों में कंडैक्टर्ज हटा कर केबल सिस्टम शुरू किया गया है। लेकिन वहां पर पोल्ज़ की ज्यादा दूरी होने की वजह से केबल बहुत ज्यादा डाऊन है। अध्यक्ष महोदय, उसकी वजह से उन गांवों में आज पहले की अपेक्षा ज्यादा लाईन-लोसिज़ हो चुके हैं। क्या मंत्री जी उन पोलों का डिफरैंस घटा कर ठीक करवाने का कष्ट करेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस बारे में ये मुझे लिखवाकर भिजवा दें। अगर वहां पर एक्स्ट्रा पोल्ज़ लगवाने होंगे तो हम वे अवश्य लगवा देंगे ताकि केबल नीचे न आये। आपकी बात सही है कि अगर केबल नीचे लटक जाएंगे तो उसका परपज़ ही डिफीट हो जाएगा।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : स्पीकर सर, जो आबादी के बीचों बीच पोल जा रहे हैं और जो तार लटकते हैं उनकी बात अभी यहां पर आई थी। मैं भी उसके बारे में कहना चाहता हूं कि आज गांवों के अन्दर इस बारे में बड़ी समस्या है क्योंकि जो लाल डोरे के अंदर घर हैं, जहां बाड़े काटे हुए हैं, पुराने ज़माने में तो गांव छोटे होते थे लेकिन अब वे एक्सटैंड हो गए हैं। अब इत्तेफाक से वे तारें मकानों के ऊपर आ गई हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या ये ऐसा कोई पॉलिसी डिसीजन लेंगे कि जो तारें लाल डोरे के अन्दर हैं वे सारी तारें गवर्नमैंट कॉस्ट पर हटा देंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, गांवों के लाल डोरे के अन्दर से वायरिंग हटाना तो शायद सम्भव नहीं होगा। माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर की है कि अगर किसी बाड़े के अंदर कोई पोल आ गया हो या पहले किसी ने उस तार के नीचे मकान नहीं बनाया था बाद में मकान बना दिया तो क्या वहां से पोल उखाड़कर गली में लगाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का हमारे पास प्रावधान है। हम लाल डोरे के अन्दर तो पोल्स शिफ्ट कर देते हैं लेकिन केस टू केस अगर आप हमें लिखकर भिजवा

देंगे तो हम दिखवा लेंगे। जो आबादी का क्षेत्र है वहां के लिए डिपैंडिंग अपान कि शिफ्टिंग के लिए क्या कॉस्ट वर्क आउट होगी यह देखना पड़ेगा, लेकिन नार्मली जो बिजली विभाग है वह लाल डोरे के अन्दर यह कार्य कर देगा।

Construction of R.O.B. at Kaithal

*844. **Sh. Shamsher Singh Surjewala :** Will the P.W.D. (B & R) Minister be pleased to state :—

(a) whether Haryana Government had approved the Construction of R.O.B. on the road passing through the Municipal Limits of Kaithal Town ;

(b) whether the tenders of the construction of the over bridge has been invited/allocated ; and

(c) the time by which the bridge is likely to be completed together with the total amount to be spent on the construction of the said bridge ?

Irrigation Minister (Captain Ajay Singh Yadav) :

(a) Yes, Sir.

(b) The tender for the construction of R.O.B. at Kaithal has been allotted on 31.1.08.

(c) The total estimated cost of work is Rs. 2365.37 lacs and this work is likely to be completed by 30.9.2009.

श्री एस०एस० सुरजेवाला : स्पीकर सर, रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण का जो पीरियड है वह करीबन डेढ़ साल का है। चूंकि यह कार्य शहर की मेन रोड पर हो रहा है तो इस दौरान शहर का ट्रैफिक तो चलता रहेगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इस ट्रैफिक के सुचारू रूप से चलने के लिए इन्होंने कोई इंतजाम किया है क्योंकि अगर ऐसा न हुआ तो फिर वहां पर ट्रैफिक में रुकावट आएगी?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, जहां तक शहर के ट्रैफिक की बात है, उसको आल्टरनेटिव रोड से निकालने का कार्य किया जा रहा है। साईड में भी इसके लिए जगह रखी गयी है वहां से वह ट्रैफिक निकल सकता है। बाकी जो दूसरा ट्रैफिक है उसको डायवर्ट करके निकाला जाएगा।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : स्पीकर सर, मंत्री जी ने इस प्रोजैक्ट की जो टोटल कॉस्ट के बारे में नोट फॉर पैड में बताया है कि यह करीब 23 करोड़ 65 लाख रुपये है। इसके लास्ट पैरा में इन्होंने यह लिखा है कि update expenditure of this work

[श्री एस०एस० सुरजेवाला]
is 26.21 lakhs यानी करीब 26 करोड़। स्पीकर साहब, जो 23 करोड़ और 26 करोड़ में वैरीएशन है क्या मंत्री जी इसके बारे में भी बताएंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, आप जानते हैं कि स्टील के रेट, सीमेंट के रेट बढ़ जाते हैं। जब एस्कालेशन होती है तो रेट बढ़ जाते हैं। जैसा मैंने बताया कि जो रेलवे का इसमें शेयर है वह 1028.65 लाख रुपये है जबकि सरकार के शेयर 1336.72 लाख रुपये है। यह काम मैसर्ज जूम डवैल्पर्स प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को दिया गया है। इसमें जो रेलवे का पोर्शन है उसके टैंडर 20.3.2008 को रिसीव कर लिये गये हैं और उम्मीद है कि यह कार्य 30 सितम्बर, 2009 तक पूरा हो जाएगा। जहां तक हमारे पोर्शन की बात है, इसका कार्य अप्रैल, 2009 तक हम पूरा कर देंगे।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : स्पीकर सर, नोट फॉर पैड में दूसरे पार्ट में कैथल कांस्टीच्यूएंसी की सड़कों के बारे में बताया गया है। इस में लिखा है कि 199.16 किलोमीटर लम्बी रोड्स कैथल कांस्टीच्यूएंसी में बननी हैं। आगे इन्होंने इसमें कहा है कि 34.71 किलोमीटर सड़कें वर्ष 2007-08 में रिपेयर की जानी हैं।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने सवाल के जवाब में जो कहा है that is not concerned with this question.

श्री एस०एस० सुरजेवाला : स्पीकर सर, इन्होंने मुझे लिखकर दिया है इसलिए मैं इनसे जानना चाहता हूँ।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह तो ऐडीशनल इन्फर्मेशन है जो कि अलग से मेरे पास होती है।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे हल्के की दो सड़कें पेहवा चौक से करनाल बाई-पास और बिजली घर से सिविल स्टेशन हैं जिनके बारे में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं, क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि इन्हें कब तक पूरा करेंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए माननीय सदस्य मुझे सैपरेट नोटिस दें, फिर जवाब दे सकूंगा।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जब मंत्री जी ने जवाब दे रखा है तो फिर सैपरेट नोटिस देने की क्या आवश्यकता है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह जवाब नहीं है। यह नोट फार पैड में है। यह इन्फर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए थी जो माननीय सदस्य के पास है।

श्री अध्यक्ष : यह इन्फर्मेशन सिर्फ इन्हीं के पास नहीं है बल्कि सभी सदस्यों के पास है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने कैथल बाई-पास के बारे में पूछा है उसमें 5 करोड़ 26 लाख रुपये लगेंगे। इसकी लैंड ऐक्वीजीशन कंप्लीट हो चुकी है और अवार्ड 7 मार्च, 2008 को हो गया है। इसकी लैंग्थ 5 किलोमीटर है।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सवाल नहीं था।

कैप्टन अजय सिंह यादव : उस सवाल के जवाब के लिए तो आपको सैपरेट नोटिस देना पड़ेगा।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं माननीय मंत्री जी से ऊपरगामी पुल के बारे में सवाल कर लूं। यह अनुमति मैं इसलिए ले रहा हूं कि कहीं बाद में आप यह न कह दें कि यह सवाल मेन सवाल से संबंधित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फरीदाबाद पुराना रेलवे स्टेशन है। जी०टी० रोड से प्रवेश मार्ग को क्रॉस करने के लिए वहां बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक रहता है और इस वजह से वहां से निकलने में बड़ी मुश्किल होती है। दो वर्ष पूर्व स्वयं मुख्यमंत्री महोदय ने इस रेल ऊपरगामी पुल को बनाने का ऐलान किया था और कहा था कि इसको जल्दी ही पूरा कर देंगे। इस बारे में रेल विभाग से भी परमीशन आ गई है। मैं यह जानना चाहूंगा कि पब्लिक की मांग के साथ-साथ क्या मुख्यमंत्री जी की ऐनाउंसमैंट को पूरा करने का कोई प्रस्ताव है? यदि है तो इसे कब तक पूरा करेंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इस वक्त इसकी इन्फर्मेशन मेरे पास नहीं है। माननीय सदस्य मुझे इस बारे में सैपरेट नोटिस दें तो मैं जरूर इसके बारे में जवाब दे सकूंगा।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रेल मंत्रालय द्वारा दिये गए पिछले रेल बजट को देखते हुए क्या ये मांग की गई है कि हरियाणा प्रदेश में कितने रेल ऊपरगामी पुलों का निर्माण होगा?

श्री अध्यक्ष : इस बारे में मुख्यमंत्री जी ने सदन में सारी इन्फर्मेशन दे दी थी। उस समय आप भी हाउस में मौजूद थे। उन्होंने बता दिया था कि कितने पुलों पर काम चल रहा है और उनके बजट के बारे में भी बता दिया था।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य डॉक्टर इन्दौरा जी की जानकारी के लिए इस सदन में आंकड़े देना चाहता हूं। 1966 से 2005 तक कुल 17 पुल बनाए गए थे। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के दौरान 3 साल की अवधि के दौरान 4 आर०ओ०बी० बना दिये हैं, 20 आर०ओ०बीज० पर काम चल रहा है। करीबन 37 आर०ओ०बी० सैंक्शन हो चुके हैं। 48 आर०ओ०बी० और आइडैंटिफाई किये गये हैं जिसमें से स्टेट रोड्स के 31 हैं और नेशनल हाइवे के 17 हैं। रेलवे के बारे

[कैप्टन अजय सिंह यादव]
में इन्होंने कहा है इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि 12 आर०ओ०बी० रेलवे के पास अप्रूवल के लिए पड़े हैं जिनमें से कुछ अप्रूव कर दिये हैं और कुछ अंडर अप्रूवल हैं।

डॉ० सीता राम : सिरसा और मंडी डबवाली के आर०ओ०बी० के बारे में भी मंत्री जी कृपया जवाब दे दें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इनका सिरसा डबवाली का पोर्शन है, इसके टैंडर कर लिये गये हैं और ये उम्मीद है कि जो आर०ओ०बी० डबवाली है इसको 2009-10 के प्रोग्राम में शामिल कर लिया जायेगा।

10.00 बजे **श्री जयसिंह राणा :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि नीलोखेड़ी और तरावड़ी के दो आर०ओ०बी० बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न थोड़ा अलग है। अगर ये इस बारे में मुझे अलग से लिखकर भिजवा दें तो मैं इनको पूरी इन्फर्मेशन दे सकूंगा क्योंकि इस समय मेरे पास इस बारे में पूरा विवरण नहीं है। वैसे मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि तरावड़ी का आर०ओ०बी० बनने के लिए मन्जूर हो चुका है और इस पर जल्दी ही कार्य शुरू हो जायेगा। बाकी नीलोखेड़ी के आर०ओ०बी० का मामला सरकार के विचाराधीन है।

Four Laning the Road Passing Through the Villages of Bahu Akbarpur, Madina and Kharkara.

***961. Sh. Anand Singh Dangi :** Will the Minister of P.W.D. (B & R) be pleased to state :—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to four-lane the road passing through villages of Bahu Akbarpur, Madina and Kharkara situated on the National Highway No.-10 and also to construct drain on both sides of the road passing through village Madina; and

(b) if so, the time by which the above said works are likely to be completed ?

Irrigation Minister (Captain Ajay Singh Yadav) :

(a) No Sir.

(b) Question does not arise.

Sh. Anand Singh Dangi : Speaker Sir, very surprise, यह क्वैश्चन बहुत ही अहम सड़क के बारे में है जो दिल्ली से लेकर अबोहर फाजिल्का तक जाती है। यह सड़क ठीक न होने की वजह से बहु अकबरपुर, मदीना और खरकड़ा इन तीनों गांवों

में इतना बुरा हाल है कि वहां न तो पानी की निकासी के लिए कोई साधन है और मदीना गांव में तो नैशनल हाई-वे की सड़क पर एक-एक फुट के गहरे गड्ढे हैं। इन तीनों गांवों की आबादी 20-20 हजार की है। इन तीनों गांवों में ट्रैफिक के आवागमन के इतने साधन हैं कि हर मिनट में एक व्हीकल वहां से निकलता है इसलिए वहां पर डिवाईडर भी बनाने की जरूरत है। इसके साथ ही पानी की निकासी के लिए ड्रेन बनाने पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ड्रेन बनाने के लिए स्पेस भी है और जमीन एक्वायर करने की जरूरत भी नहीं है। ऐसी सड़क के लिए मंत्री जी द्वारा यह कहना कि Question does not arise बहुत ही सरप्राईज की बात है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, बहु अकबरपुर, मदीना और खरकड़ा ये तीनों ही गांव एन०एच०-10 जो रोहतक से महम की तरफ जाता है उस पर पड़ते हैं। एन०एच०-10 वैसे दिल्ली से हिसार रोड है और इस रोड को बनाने का काम सरकार ने नैशनल हाई-वे एथोरिटी को ट्रांसफर किया हुआ है। माननीय सदस्य की इन्फर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूंगा कि इन तीनों गांवों के बाई-पास बनाने के लिए सरकार की एक प्रोपोजल है ताकि बाई-पास बनने के बाद जो गांवों के बीच से ट्रैफिक निकलने की समस्या है वह दूर हो जायेगी। बहु अकबरपुर के बाई-पास का काम आलरेडी चल रहा है। मदीना गांव के बीच में से होकर जाने वाली जो सड़क खराब है उसको हम एच०आर०डी०एफ० के माध्यम से बनवा देंगे और इसके दोनों तरफ ड्रेन जरूर बनवा देंगे।

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, जब से इन सड़कों का काम नेशनल हाई-वे एथोरिटी को दिया है तब से ही ज्यादा गड्ढा बैठ गया है। इससे पहले तो इन सड़कों पर कम से कम मिट्टी तो डलवा लेते थे। जब से एन०एच०ए० को दिया है इन सड़कों को कोई नहीं संभालता। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह बाई-पास कितने साल में बन जायेगा क्योंकि यह एक गम्भीर समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब भिवानी से रोहतक जाते हैं तो इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। मैं तो गांव में रहता हूं मंत्री जी तो शहर में रहते हैं। जो गांव में दिक्कत है वह तो हमें पता है। आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इन सड़कों पर विशेष ध्यान देकर इन सड़कों की रिपेयर जल्दी से जल्दी करवायें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं भी गांव में रहता हूं और मेरा गांव शहर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। मुझे पता है कि गांव में क्या होता है और शहर में क्या होता है। यह बात ठीक है कि इनको दिक्कत है। मैंने पहले ही बता दिया है कि इन तीनों गांवों में ड्रेन की व्यवस्था सरकार करवा देगी। जहां तक डिवाइडर की बात है तो इसके बारे में हम एग्जामिन करवा लेंगे, उसके बाद ही मैं कुछ जवाब दे पाऊंगा। जैसा कि मैंने बताया है कि यह रोड नेशनल हाई-वे अथोरिटी को ट्रांसफर कर दिया गया है इसलिए इस बाई-पास को हम जल्दी ही पूरा करवा देंगे। 464 करोड़

[Shri Anand Singh Dangi]
रुपये का यह प्रोजैक्ट है। जो हमारे अधिकारी हैं वे इस पर जल्दी कार्यवाही करेंगे। मैं इनकी चिन्ता से अपने आप को जोड़ते हुए कहना चाहूंगा कि इनकी समस्या का जल्दी समाधान किया जाएगा।

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इस बाई-पास के बनने में तो सालों साल लगेंगे इसलिए जब तक ये बाई-पास नहीं बनता तब तक हमारे यहां के गढ्ढे ठीक करवा दिए जाएं ताकि कम से कम लोगों के लिए आने-जाने के रास्ते ठीक हो सकें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इनके गांवों के गढ्ढे भी ठीक करवाए जाएंगे और ड्रेन भी बनवाई जाएंगी।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, दांगी साहब की बात वाजिब है क्योंकि यह मेन सड़क है और मैं अपने आप को इनकी बात के साथ जोड़ता हूं। आदरणीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस सड़क की मुरम्मत करवा दी जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय साथी को आश्वस्त कर दिया है कि इन सड़कों की जल्दी ही मुरम्मत करवा दी जाएगी।

श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी नेशनल हाई-वे का जिक्र आया है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि नैशनल हाई-वे नं०-8 पर भी यही पोजीशन है कि राजीव चौंक से नाहरपुर पहला गांव पड़ता है और आधा-आधा गांव दोनों तरफ है, उससे अगला नरसिंहपुर गांव है, स्कूल दूसरी तरफ है, गांव दूसरी तरफ है, श्मशान घाट भी दूसरी तरफ है। मुर्दे को कम से कम एक-एक घंटे के लिए रोकना पड़ता है क्योंकि हाई-वे पर ट्रैफिक तो रुकता नहीं इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इन दो-तीन गांवों के लिए कोई पुल बनवाया जाए ताकि वहां के लोगों को सुविधा हो सके।

Mr. Speaker : Jaunapuria ji, please ask separate question in this regard.

श्री रणधीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि मेरे हल्के में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत राखी से वाया मलिकपुर गुलकण की सड़क एक वर्ष पहले बननी शुरू हुई थी लेकिन उसके बीच में डेढ़ किलोमीटर टुकड़े का काम रुका हुआ है। क्या इस सड़क के बारे में मंत्री जी को मालूम है कि किस वजह से यह काम रुका हुआ है और यह काम कब तक कम्पलीट हो जाएगा?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि पंचायती राज की 110 सड़कों को हमने टेक ओवर किया था।

उसमें से 51 सड़कों की रिपेयर कर दी गई है। इनकी जो सड़क है उसका काम पी०डब्ल्यू०डी० (बी० एण्ड आर०) को ट्रांसफर होते ही शुरू करवा देंगे। मुझे मालूम नहीं है कि यह सड़क पी०डब्ल्यू०डी० (बी० एण्ड आर०) को ट्रांसफर हो गई है या नहीं। इस समय मेरे पास डिटेल नहीं है और अगर हमारे पास डिटेल आ गई है तो हम इसकी रिपेयर का काम करवा देंगे।

श्री रणधीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी को कहना चाहूंगा कि यह सड़क शुरु से ही पी०डब्ल्यू०डी० की है। किसी ने कोर्ट में केस डाला है तो मैं अब यह जानना चाहता हूं कि उस केस की क्या पोजीशन है?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो अलग बात है क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद ही इसका डिसीजन होगा।

श्री शाहिदा खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि नूंह को तावड़ू से जो रोड जाता है उसके बीच में पहाड़ पड़ता है और वहां डेली जाम लगा रहता है। इस सड़क पर 2-2 फुट के गड्ढे हैं जैसा कि डांगी जी ने भी बताया है। पूरे मेवात में हालत यह है कि जब करतार सिंह भडाना के और अवतार सिंह भडाना के डम्पर चलते हैं तो वे रोड्स टूट जाती हैं। मेवात की सड़कों का बहुत बुरा हाल है। यह चिन्ता की बात है और हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कम से कम जो ओवर लोडिड गाड़ियां चलती हैं उनको रोका जाए और उनके लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि इस रोड पर ओवर लोडिड गाड़ियां नहीं चलेंगी। जब कोई मेवात के अन्दर शिकरावा होकर आता है तो उसको उलटा रूट पड़ता है। शिकरावा से गोहाना और फिर नूंह आती है जबकि उन लोगों को उटावल मोड़ से हथीन से सीधा निकलना चाहिए। इसी ढंग से जो नूंहवाला होडलवाला रोड है उसका भी बहुत बुरा हाल है। मैं मंत्री जी से रिक्वैस्ट करता हूं कि क्योंकि उसका बनना तो बहुत दूर की बात है, कम से कम गड्ढे तो जरूर भरवा दें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने तावड़ू-नूंह सड़क का जिक्र किया है जो आगे जाकर पटौदी से मिलती है। उस सड़क को आलरेडी एन०सी०आर० के तहत ले लिया गया है। मैंने पहले भी बताया था कि 588 करोड़ रुपये मेवात के लिए मंजूर किए गए हैं। इनकी सड़क को भी उसमें ले लिया गया है और उस पर जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। जहां तक नॉर्मल रिपेयर की बात है तो वह हम करवा देंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात कप्तान साहब के साथ जोड़ना चाहता हूं कि शाहिदा खान जी रोज कप्तान साहब से यह प्रश्न पूछते हैं और वे रोज उनको बताते हैं कि आजादी के बाद पहली बार मेवात के इलाके में भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार ने 588 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों की रिपेयर,

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
नई कंस्ट्रक्शन और मुरम्मत का कार्यक्रम बनाया है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मैं माननीय सदस्य शाहिदा खान से कहना चाहूंगा कि वे अपने साथियों से इतना जरूर पूछें कि करतार सिंह भडाना किसके समय में मंत्री थे।

Repair of Roads

*966. **Shri Naresh Yadav :** Will the P.W.D. (B & R) Minister be pleased to state the time by which the following roads are likely to be repaired :—

1. Ateli to Mahendergarh via Dogra ;
2. Bewal to Rattakalan via Khairani ;
3. Rattankalan to Kund via Nangal ;
4. Kund to Narnaul main raod ;
5. Narnaul to Nangal Chaudhary upto Kotputli Rajasthan Border ;
6. Nirpur to Mandhana upto Dhani Bhatota ;
7. Gokalpur to Girdharpur via Bauchariya Hasanpur ;
8. Nangal Chaudhary to Nizampur ; and
9. Narnaul to Godbalawa upto Rajasthan Boarder ?

Irrigation Minister (Captain Ajay Singh Yadav) : Sir, the repair work on some of the above roads i.e. at Sr. No. 1, 6, 8 and 9 is in progress. Repair work on the remaining roads is likely to be carried out during 2008-09.

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, क्रमांक संख्या-4, 5, 6, 8 और 9 की सड़कों पर वर्ष 2005-06 के दौरान मौजूदा सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च करके रिपेयर का कार्य करवाया था। लेकिन अब इन सड़कों की बहुत बुरी हालत है। इसका कारण यह है कि वहां पर क्रैशर जोन है जिसकी वजह से ओवर लोडिड डम्पर वहां पर चलते हैं और जल्दी ही सड़कें टूट जाती हैं। जिसकी वजह से वहां एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। क्या मंत्री जी क्रैशर वालों पर और जो ओवर लोडिड बजरी के ट्रक लेकर आते हैं उन पर कोई कंट्रोल करेंगे ताकि बार-बार ये सड़कें न टूटें?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी की चिन्ता सही है। हमारी सरकार ने वहां पर सड़कें बनवाई हैं लेकिन राजस्थान से वहां पर डम्पर आते हैं जिनकी वजह से सड़कें टूट जाती हैं। इस पर हमारी सरकार विचार कर रही है कि जो कॉमर्शियल गाड़ियां वहां पर आती हैं उन पर बी०ओ०टी० बेसिज पर टैक्स लगाया जाये। अध्यक्ष महोदय, हम प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत भी सड़कों का

निर्माण कर रहे हैं। मेरे माननीय साथी नरेश यादव जी के हल्के में अभी दो सड़कें प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत रिपेयर करवाई हैं। रिपेयर करवाने के बाद जो सड़कें डम्पर आदि के चलने से टूट जाती हैं उस तरफ हमारी सरकार अवश्य ध्यान देगी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय साथी शाहिदा खान ने चिन्ता व्यक्त की कि उनके यहां सड़कों की रिपेयर और मैन्टेनैंस का काम नहीं हो रहा। मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इनकी सरकार के पांच साल के कार्यकाल के दौरान 1740 करोड़ रुपये सड़कों की मरम्मत और कन्स्ट्रक्शन पर खर्च किये गये थे जबकि हमारी सरकार के तीन साल के कार्यकाल के दौरान 2100 करोड़ रुपये सड़कों की मैन्टेनैंस, रिपेयर और कन्स्ट्रक्शन पर खर्च किये गये हैं। इसी तरह से ओम प्रकाश चौटाला के मुख्यमंत्री काल के दौरान प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मात्र केवल 100 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे और हमारी सरकार के तीन साल के कार्यकाल के दौरान 700 करोड़ रुपये इस योजना के तहत अब तक खर्च किए जा चुके हैं जिसमें सड़कों की वाईडनिंग का कार्य भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 360 करोड़ रुपये प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत वर्ष 2007-08 में और मंजूर करवाये हैं। इसके अतिरिक्त एन०सी०आर० एरिया की सड़कों के लिए 1200 करोड़ रुपये वर्ष 2007-08 के लिए सैंक्शन करवाये हैं जिसमें से 588 करोड़ रुपये मेवात को दिये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार मेवात के बारे में सोच रही है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इनकी सरकार के समय में 65 करोड़ रुपये एन०सी०आर० एरिया की सड़कों पर खर्च किया गया था जिसमें से एक पैसा भी मेवात पर खर्च नहीं किया गया। जहां तक माननीय साथी ने करतार सिंह भडाना के डम्परों की बात की है, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उनकी सरकार के समय में करतार सिंह भडाना के डम्पर क्यों नहीं रोके गये। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की यह नीयत नहीं है कि एक क्षेत्र में काम करे बल्कि हमारी सरकार पूरे प्रदेश में विकास कार्य करवा रही है।

श्री बच्चन सिंह आर्य : अध्यक्ष महोदय, करतार सिंह भडाना के नाम की चर्चा हुई कि वे इनकी पार्टी में मंत्री रहे हैं। लेकिन वे अब इनकी पार्टी में नहीं हैं। वे भी इनकी गलत नीतियों के कारण इनको छोड़कर चले गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कुछ रोड्स ऐसे हैं जो जिले की सीमा पर लगते हैं। उनके बारे में अधिकारियों से बात करते हैं तो एक जिले के अधिकारी कहते हैं कि वह रोड उनके जिले में नहीं पड़ता, दूसरे जिले में पड़ता है और जब दूसरे जिले के अधिकारियों से बात करते हैं तो वे भी ऐसा ही जवाब देते हैं। मेरे सफीदों हल्के में डीडवाड़ा गांव है और करनाल जिले में असन्ध में सालवन गांव है। ये दोनों गांव जिलों की सीमा पर पड़ते हैं। इन दोनों गांव के बीच चार कि०मी० की सड़क का टुकड़ा है जो बहुत बुरी हालत में है। इसको ठीक करने के लिए जीन्द जिला के अधिकारियों को कहते हैं तो वे कहते हैं कि उनके एरिया में नहीं आता और करनाल जिले के अधिकारियों को कहते हैं तो वे भी यही कहते हैं कि उनके एरिया में नहीं पड़ता। क्या मंत्री जी इस चार कि०मी० के टुकड़े को ठीक करवाने की कृपा करेंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि जो इन्होंने अपनी बात रखी है कि खासतौर से जो डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डरज़ पर जो रोड हैं उनकी हालत बहुत खराब है। इस बारे में मैं इनको यह कहना चाहूंगा कि इसके बारे में ये मुझे डिटेल में लिखकर दे दें कि वे स्पैसिफिक रोड्ज़ कौन-कौन से हैं जिनकी मुरम्मत किया जाना जरूरी है। जिन रोड्ज़ की हालत खराब होगी हम उनकी रिपेयर जरूर करवायेंगे।

Stopping of water by Rajasthan Government of Sahibi, Krishnawati and Dohan Rivers

***968. Shri Radhey Shyam Sharma :** Will the Irrigation Minister be pleased to state whether it is a fact that the Rajasthan Government has stopped the water of Sahibi, Krishnawati and Dohan rivers by constricting the dams on the said rivers togetherwith the steps taken or to be taken by the Government to get share of water of Haryana from aforesaid rivers ?

Irrigation Minister (Captain Ajay Singh Yadav) : Yes Sir, It is a fact that the Rajasthan Government has stopped the water of Sahibi, Krishnawati and Dohan rivulets by constructing Check Dams on these rivers. The matter has been taken up by the Haryana with Government of India.

श्री राधे श्याम शर्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन तीनों नदियों साहिबी, कृष्णावती और दोहन का बहुत बुरा प्रभाव हमारे नारनौल क्षेत्र पर पड़ता है और मंत्री जी ने यह जवाब दिया है कि "The matter has been taken up with the Government of India." But before Government of India, Government of Rajasthan comes in between. क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि राजस्थान सरकार ने जो सीमा के ऊपर बांध बना कर पानी रोक दिया, इसके बारे में मंत्री जी दिल्ली क्यों पहुंच गये जबकि उन्हें पहले जयपुर जाना चाहिए था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस मामले को राजस्थान सरकार के साथ उठाते समय क्या कार्यवाही की गई उसके बारे में सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, ये जो कृष्णावती, साहिबी और दोहन नदियाँ हैं इनसे पहले राजस्थान की तरफ से काफी पानी आया करता था। अध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता से पहले ये टोटल 45 बांध थे। उसके बाद 1978 तक 9 बांध और बना दिए गए और 1978 से लेकर अब तक 29 बांध और बनाकर इस समय टोटल 83 बांध बना दिये गये हैं जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम पेश आ रही है। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि पहले बरसात बहुत हुआ करती थी लेकिन अब बरसात बहुत कम होती है। दूसरी बात यह है कि इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपर यमुना बोर्ड की मीटिंग में उठाया गया था और पिछले दिनों जब अपर यमुना बोर्ड की

मीटिंग हुई तो मैंने भी इस मामले को उठाया था। इसके अतिरिक्त पिछली 24-25 मई को एस०ई०, राजस्थान और अपर यमुना बोर्ड में हरियाणा के मैम्बर सैक्रेटरी, अपर यमुना बोर्ड की एक टीम गठित की गई थी जिसमें ज्वायंट इंस्पैक्शन करने के बाद ये तथ्य सामने आये थे कि 83 चैक डैम्ज़ बनाये गये हैं और उनमें से 40 बांध ऐसे थे जो कि मसानी बैराज़ बनने के बाद बना दिए गए। उस वक्त चौधरी देवी लाल की सरकार थी उन्होंने बिना किसी सोच विचार के वहां पर इतना बड़ा बांध बना दिया। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार के आने के बाद मुख्यमंत्री जी मेरे क्षेत्र में आये थे तो मैंने उस समय उनके सामने अपनी यह मांग रखी थी। मैंने कहा था कि मसानी बैराज पर करोड़ों रुपये खर्च कर दिये गये और अब वह बेकार पड़ा हुआ है। उसमें जे०एल०एन० कैनाल से हमने लाल बहादुर शास्त्री नामक एक कैनाल निकालकर 6 करोड़ 70 लाख की लागत से एक रिचार्जिंग चैनल बनाकर उसको भरने के लिए उस पर कार्य चल रहा है। इसी प्रकार से हमीदपुर बांध के ऊपर भी काम चल रहा है और उस पर भी 2.50 से 3 करोड़ रुपये की लागत से इसको जोड़ने का काम पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही इनकी यह बात भी बिल्कुल सही है कि ये चैक डैम्ज़ क्यों बनाये गये हैं। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि अपर यमुना बोर्ड की प्रत्येक मीटिंग में हमने यह मामला उठाया है और जब 14.7.2005 को अपर यमुना बोर्ड की 20वीं मीटिंग हुई थी उसमें भी हमने यह मामला उठाया था। इस बार हमने यह निर्णय लिया है कि जब राजस्थान के साथ हमारा फैसला यमुना के पानी के सम्बन्ध में होगा तो उस समय हम यह कोशिश करेंगे कि जितना शेयर ये हमारा यहां रख लेते हैं हम यमुना के पानी में जो उनका हिस्से में होगा उसमें से हम कटौती करने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह एक इंटरस्टेट मैटर है इसलिए हम इस बांध को गिरा तो नहीं सकते और न ही हाउस में मैं कोई ठोस आश्वासन इस बारे में दे सकता हूं लेकिन माननीय सदस्य को मैं यह आश्वासन अवश्य दे सकता हूं कि हम इसके बारे में पूरी तरह से सजग हैं और हम इस मामले को हर लैवल पर उठा रहे हैं लेकिन हम चैक डैम्ज़ को हटा नहीं सकते क्योंकि ये उनकी स्टेट में बने हुए हैं। यह मामला हम अपर यमुना बोर्ड की मीटिंग में समय-समय पर उठाते रहते हैं।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कृष्णावती और दोहन नदियों में तो पानी की बूंद भी नहीं है केवल बरसात के दिनों में ही कुछ पानी आ पाता है। हमारे इलाके नांगल चौधरी में वाटर लेवल 400 से लेकर 1600 फुट नीचे चला गया है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि उस वाटर लेवल को रिचार्ज करने के लिए बजट में कोई प्रावधान किया गया है?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमीरपुर बाँध को भरने के लिए हमने एक स्कीम बनाई है। अध्यक्ष महोदय, दिक्कत यह है कि हमारी जो 90 माईनर्ज बनी हुई हैं उनमें से 40 में पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम वहां पर इंजैक्शन वोर बना दें ताकि बरसात का पानी आये तो रिचार्ज हो जाये। हमने हमीरपुर बाँध को

[कैप्टन अजय सिंह यादव]
जोड़ने की योजना बना रखी है। इसके अलावा और भी अगर कोई ऐसा बाँध होगा तो उस पर भी सरकार विचार करेगी। मैं इस समय कोई ठोस आश्वासन नहीं दे सकता कि सारे बाँधों को नहरों से जोड़ दिया जायेगा क्योंकि बहुत सी मौजूदा डिस्ट्रीब्यूट्रीज के टेल पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। मैं बी०एम०एल० हांसी बुटाना लिंक नहर के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ साथी इस मस्क्कत में लगे हुए हैं कि यह न बने, उसकी वजह से हमें कुछ समस्या आ रही है। कभी कोर्ट में चले जाते हैं वहां पर इनको मुंह की खानी पड़ती है और कभी अखबारों में ब्यान देते हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं है। मौजूदा सरकार पानी के समान वितरण में विश्वास रखती है और इस बारे में मेरा यही कहना है कि हम रिचार्जिंग के लिए अच्छी स्कीम बनायेंगे।

Construction of Water Works at Village Parhladgarh

***944. Dr. Shiv Shanker Bhardwaj :** Will the Water Supply and Sanitation Minister be pleased to state whether it is a fact that foundation stone of water works at village Parhladgarh was laid on 2.3.2006; if so, the time by which the construction of the said water works is likely to be started/completed ?

Power Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) :

Yes Sir, However, the proposal was not found suitable as land proposed to be provided by the village Panchayat of Parhladgarh was at an elevation of about 22 feet from the bed of Jui canal from where raw water was to be drawn.

After detailed technical scrutiny and keeping in view the site conditions, it was decided to supply water to Parhladgarh and Haluwas from Main Water Works No. 2, Bhiwani town.

At present, an independent boosting station has been constructed and commissioned by laying a rising main of 200mm diameter from Main Water Works No. 2, Bhiwani Town. As such, there is no need to have a separate water works at Parhladgarh.

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब इस वाटर वर्क्स की आधारशिला रखी थी तब क्या यह सूटेबिलिटी नहीं देखी गई क्योंकि जब इस प्रकार की आधारशिला रखते हैं और उसके बाद उस पर काम पूरा नहीं हो पाता है, तो एम०एल०ए. की रैपुटेशन खराब होती है। अगर कोई दूसरी सूटेबल लैंड वाटर वर्क्स के लिए मिल जाये तो क्या मंत्री जी उस पर विचार करेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि हमारे पास 231 लाख 6 हजार रुपये की राशि मौजूद है, ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं था

जो हमें जमीन दी गई है, वह जुई नहर जिसमें से पानी आना है उससे 22 फुट ऊपर है। It will become a lift drinking water scheme which ultimately give perpetual problems to the village. कहीं न कहीं पर बिजली की समस्या होगी, कहीं पर दूसरी समस्या होगी। ड्रिंकिंग वाटर स्कीम नेचुरल ग्रेडिएंट के आधार पर बनाई जाती हैं। वहां पर लिफ्ट वाटर वर्क्स कामयाब नहीं होगा, यह हमारा तजुर्बा है। इसीलिए यह निर्णय लिया गया है।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, अगर इस 22 फुट ऊंची जमीन की जगह कोई दूसरी जमीन दे दी जावे जो 22 फुट ऊंची न हो तो क्या मंत्री जी उस पर विचार करेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी हमें वह जमीन दिलवा दें हम उस पर अवश्य विचार कर लेंगे।

श्री रणधीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बरवाला शहर में सरहेड़ा रोड पर एक बूस्टिंग स्टेशन मंजूर हो चुका है। क्या मंत्री जी इस बूस्टिंग स्टेशन को जल्दी बनवाने की कृपा करेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह एक पृथक प्रश्न है। माननीय साथी लिख कर भिजवा दें, अवश्य इसे जल्दी बनवाने पर विचार किया जायेगा।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि हमारे कलायत क्षेत्र में भी कई जगह वाटर वर्क्स का काम चल रहा है और कई जगह पूरा हो चुका है। क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि वह काम जल्दी पूरा होगा और जहां पर वाटर वर्क्स का काम पूरा हो चुका है वहां पर सब जगह पाईप लाईन बिछा कर पानी जल्दी पहुंचायेंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे हमारे कलायत, बालू, पिंजुपुर, अम्बरसर आदि गांवों में वाटर वर्क्स हैं, लेकिन बिजली की कमी की वजह से वहां पर हम पानी लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसा कोई प्रावधान किया जा रहा है कि जहां पर पानी की ज्यादा किल्लत है वहां पर जैनरेटर सैट्स के माध्यम से पानी दिया जाए?

श्री अध्यक्ष : यह सवाल तो पहले ही आ चुका है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने दो सैपरेट प्रश्न पूछे हैं। एक तो early completion of laying of pipelines का है। मैं उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि जहां-जहां वाटर वर्क्स बनाए जाएंगे वहां-वहां हमारी योजना उसके साथ पाईपलाईन डालने की है, हम बजटरी ऐस्टिमेट्स के अन्दर ही उसको शामिल करते हैं। इनका दूसरा प्रश्न गांवों के अन्दर पानी की सप्लाई के लिए जैनरेटर सैट्स लगाने का है। अध्यक्ष महोदय, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। इस बारे में हमने पहले भी बताया था कि क्रूशियल लाईन्ज जो हमारे बड़े वाटर वर्क्स हैं उनके बारे में फिलहाल

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
हमने योजना बना रखी है कि जहां हमने डैडिकेटिड पावर लगाई है जिसे आप होट लाईन की संज्ञा भी दे सकते हैं वह पहले ही जारी है। फिलहाल सभी वाटर वर्क्स पर यह जैनरेटर सैट्स लगाना सम्भव नहीं है। जो हमारी क्रुशियल लाईन्ज हैं पहले फेस में हम उन पर जैनरेटर सैट्स लगाएंगे और धीरे-धीरे बाकी के वाटर वर्क्स पर जैनरेटर सैट्स लगाने का प्रयास करेंगे।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि लगभग एक साल पहले बवानी खेड़ा में रैली के अन्दर उन्होंने एक वाटर वर्क्स मिल्कपुर में मन्जूर किया था। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि अब उसकी क्या प्रक्रिया चल रही है और उस पर काम कब तक शुरू हो जाएगा?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो दिन पहले मुझे इस बारे में लिख कर दिया है और मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि हम उसे सैनिटेशन बोर्ड की बैठक के अन्दर ले जाएंगे और इस वाटर वर्क्स के लिए जितने पैसे की जरूरत है वह मन्जूर कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी मैं पहले ही माननीय सदस्य को दे चुका हूँ।

श्री सोमवीर सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से थोड़ा हट कर सवाल पूछना चाहता हूं। मेरी कांस्टीच्यूएंसी में बड़दो पूर्ण गांव है जहां वर्ष 1999 में वाटर वर्क्स बना था लेकिन न उसकी चारदीवारी है और सरकार चेंज होने के बाद न ही वहां पर पाईपलाईन डाली गई है। वहां पर कोई भी आदमी नहीं है। वह गांव उस वाटर वर्क्स के बिल्कुल नजदीक लगता है लेकिन आज तक उस वाटर वर्क्स में पानी की सप्लाई नहीं हुई है। क्या माननीय मन्त्री जी इस पर गौर करने की कृपा करेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, वहां पर वर्ष 1999 में जो वाटरवर्क्स बना था यह स्वाभाविक है कि उसकी चारदीवारी वगैरा बनाने के लिए पैसा साथ ही दिया जाना चाहिए था। माननीय सदस्य इस बारे में लिख कर भिजवा दें, इसके लिए जितना पैसा चाहिए है वह सारा पैसा जो भी होगा हम वह दिलवा देंगे।

श्री शाहिदा खान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मेवात में पानी की बहुत भारी किल्लत है। दो इलाके ऐसे हैं जहां पर ट्यूबवैल भी नहीं लगता है जिस में से एक को आरेज बोला जाता है और दूसरे को भयाना बोला जाता है। ये नूंह के इलाके में नगीना ब्लॉक के नजदीक है और जो हमारे एस०ई० साहब हैं वे पलवल में बैठते हैं। किसी अधिकारी से अगर कोई शिकायत भी की जाए तो पलवल जाना पड़ता है और इसमें काफी दिक्कत होती है क्योंकि वह दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। क्या माननीय मन्त्री महोदय यह कृपा करेंगे कि कम से कम एक एस०ई० को हमारे हैडक्वार्टर पर बिठाएं। अध्यक्ष महोदय, दूसरी

बात में यह जानना चाहता हूं कि जहां पानी की लीकेज हो जाती है और उसके कारण वहां पर बहुत बुरा हाल हो जाता है। लोग दफतरों के चक्कर लगाते रहते हैं। अगर गांव में 3-3 या 4-4 ट्यूबवैल्ज भी लगा रहें हैं तब भी लीकेज के कारण पानी की पूर्ति नहीं होती है। मैं माननीय मन्त्री जी से उम्मीद करता हूं कि वे इसे ठीक भी करवाएंगे। मन्त्री जी कई बार मेवात में गए हैं और लोगों को विश्वास भी दिला कर आए हैं इसलिए मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस काम को जरूर करवाने की कृपा करें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी की चिन्ता वाजिब है और मैं तो इनको इतना ही कहूंगा कि शायद सौ सालों से भी अधिक समय से मेवात के अन्दर पीने के पानी की समस्या है। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भी जानते हैं कि यह एक गम्भीर समस्या बनी हुई है। कई बार कहा गया है कि हम मेवात में रैनीवैल परियोजना या किसी दूसरी परियोजना के माध्यम से पानी लायेंगे। वहां पर एक बार नहीं बल्कि दो बार इस परियोजना के लिए पत्थर रखे गये परन्तु एक भी रुपये का काम वहां पर शुरू नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जब मौजूदा सरकार सत्ता में आई तो माननीय मुख्यमन्त्री जी ने हमें बुला कर यह जिम्मेदारी सौंपी और कहा कि मेवात हमारी प्राथमिकता का केन्द्र बिन्दु होना चाहिए और हमने राईट्स ऐजैंसी से फ्रैश डिजाईन करवाए। राईट्स सबसे स्पैशलाईज्ड ऐजैंसी है और सारे मेवात के एक-एक गांव का सर्वे करवा कर ग्रेडिएंटस दिखवा कर एक प्रोजैक्ट बनवाया है जिसको राजीव गांधी पेयजल योजना, मेवात कहते हैं। हम लोगों ने कोशिश की कि वहां पर पानी की सप्लाई सही हो। जो लोग पत्थर रख कर गए थे उन द्वारा और चौटाला साहब यहां पर बैठे हुए हैं इन्होंने भी इसका पत्थर रखा था परन्तु वहां पर एक भी रुपये का काम नहीं किया गया था क्योंकि उसके डिजाईन ही तैयार नहीं करवाए गए थे। ये वहां पर केवल पत्थर रखवा कर ही चले गए। हमारी सरकार आने के बाद हमने उसे नये सिरे से देखा और उसको राईट्स ऐजैंसी से डिजाईन करवाया। इसके लिए हमने 425 करोड़ रुपये मन्जूर करवाये हैं और इस पर इस समय काम जारी है। अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह बात बताते हुए खुशी है कि शायद हिन्दुस्तान की यह सबसे बड़ी पेयजल योजना है जिसका क्रियान्वयन इस समय जारी है और उम्मीद है कि एक साल के अन्दर-अन्दर यह परियोजना पूरी हो जाएगी इसके लिए हम रैनीवैल भी खोद चुके हैं। हम उस पानी को 100 एम०एम० डाया या उससे बड़े पाईप के माध्यम से हम फरीदाबाद के नजदीक से दो प्वायंटों से लेकर जाएंगे और बुस्टिंग स्टेशन के माध्यम से पानी को ऊपर चढ़ाएंगे। वहां पर 1500 किलोमीटर के करीब पाईप लाईन बिछाई जाएगी और उस पर तकरीबन 80 लाख से लेकर एक करोड़ रुपए तक के करीब खर्चा आएगा।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the question hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Spread of Bird Flu in Haryana

***924. Sh. S.S. Surjewala :** Will the Animal Husbandry & Dairying Minister be pleased to state :—

(a) whether the Bird Flu has also spread in Haryana; if so, the details of the areas effected by the said flu ; and

(b) whether Government of India and Government of Haryana are compensating the farmers for the loss caused to the farmers by Bird Flu ?

कृषि मंत्री (सरदार एच०एस० चड्ढा) :

(क) नहीं श्रीमान जी।

(ख) श्रीमान, जैसा कि "क" में व्यक्त किया गया है कि राज्य के किसानों को बर्ड फ्लू से कोई हानि नहीं हुई है। इसलिए किसानों को क्षतिपूर्ति करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

To increase the capacity of Mali Saiman Minor

***962. Shri Anand Singh Dangi :** Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the capacity of Mali Saiman Minor emanating from Jui Feeder by remodeling it and also to extend the tail by setting right the level of the said minor; if so, the time by which the said works are likely to be completed ?

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : श्रीमान जी, जुई फीडर से माली सैमाण माइनर नामक कोई चैनल नहीं निकलती है। यद्यपि माली सैमाण सम्पर्क चैनल नाम का एक चैनल है जोकि सुन्दर सब ब्रांच की बुर्जी 109031-बाएं से निकलती है। यह चैनल अपने अन्तिम छोर तक बिना किसी रुकावट के बह रही है।

Separate Water Works at Village Goripur

***945. Dr. Shiv Shanker Bhardwaj :** Will the Water Supply and Sanitation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a separate water works at village Goripur in District Bhiwani; if so the time by which it is likely to be constructed ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : नहीं, श्रीमान्! लेकिन गांव कितलाना और गोरीपुर के लिए, जिनका जलघर कितलाना में है, एक बढ़ौतरी योजना

का कार्य 91.61 लाख रुपये की लागत से चल रहा है, जो कि 30.9.2008 तक पूरा हो जाएगा।

Increase in the Price of Sugar-Cane

*936. **Dr. Sushil Indora :** Will the Co-operation Minister be pleased to state :—

(a) whether the price of the sugarcane has been increased during the year 2006 and 2007 ; and

(b) whether any Sugar Mill has been sold due to the non-availability of the sugarcane ?

कृषि मंत्री (सरदार एच०एस० चट्ठा) :

(क) हाँ, अध्यक्ष महोदय! वर्ष 2006 में गन्ने की कीमत बढ़ाई गई थी। वर्ष 2007 में वही कीमत लागू की जा रही है।

(ख) हाँ, अध्यक्ष महोदय! सहकारी चीनी मिल पन्नीवाला मोटा जिला सिरसा को गन्ने की अनुपलब्धता के कारण परिसमापन प्रक्रिया के अन्तर्गत बेचा गया है।

इसी तरह सहकारी चीनी मिल, भूना जिला फतेहाबाद को भी गन्ने की अनुपलब्धता के कारण परिसमापन प्रक्रिया के अन्तगर्त बेचा गया है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले बजट पर डिस्कशन शुरू हो, मैं जीरो ऑवर में आपकी इजाजत से एक बहुत ही अहम् लोक महत्व के मुद्दे पर बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज गुड़गांव जिले के लोगों में पानी के लिए बहुत हा-हाकार मचा हुआ है। वहां पर पानी का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। पिछले पांच-छः दिनों से वहां पर पानी की सप्लाई नहीं हो रही है और सरकार उस बारे में कोई ध्यान नहीं दे रही है।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आपने इस बारे में कब लिखकर दिया है?

डॉ० सुशील इन्दौरा : सर, मैंने इस बारे में आज सुबह नोटिस दिया है।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आपने यह नोटिस आज दिया है और यह मामला अभी अंडर कंसीड्रेशन है। इसके बाद यह गवर्नमैंट को भेजा जाएगा और गवर्नमैंट आपको इस बारे में पूरा जवाब देगी। आप अभी बैठ जाएं।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, अगर आप चाहें तो इस बारे में जीरो ऑवर में भी बोलने का समय दे सकते हैं। आज गुड़गांव में लोग बहुत दु:खी हैं और जो इम्पलाईज हैं वे पानी की प्रोब्लम की वजह से ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह शहर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का है और वहीं से हरियाणा का आर्थिक विकास हो रहा है इसलिए इस बारे में सदन में चर्चा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, यह प्रोब्लम वहां पर कब से है?

डॉ० सुशील इन्दौरा : सर, यह प्रोब्लम वहां पर 5-6 दिनों से है।

श्री अध्यक्ष : आप इस बारे में कल भी लिखकर दे सकते थे, परसों भी दे सकते थे। (शोर एवं व्यवधान) उससे पहले भी लिखकर दे सकते थे। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, जब हमारी जानकारी में आएगा, तब ही लिखकर देंगे। * * * * *

डॉ० सीता राम : * * * * *। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ये जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान) कल तो आप पांच घंटे शराफत से बैठे थे। आज ऐसी क्या चाबी भर गई है। (शोर एवं व्यवधान) पता नहीं टूक-टूक बोले जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में माननीय सदस्य से एक बात कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, किसी जरूरी मुद्दे को उठाने के बारे में आज और कल का प्रश्न नहीं उठता है। आज गुड़गांव जिले में पानी के लिए हा-हाकार मची हुई है। आज हरियाणा में पानी और बिजली का बड़ा भारी अभाव है। आज गुड़गांव में ई०डी०सी० के 1502 हजार करोड़ रुपए हैं। अगर आप पीने के पानी की जो मूलभूत सुविधा है अगर उसको नहीं कर पाएंगे तो कैसे काम चलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में इनको बताना चाहता हूं कि.........(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, कन्सर्न्ड मिनिस्टर इस बारे में जवाब देना चाहते हैं। आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) Chautala Ji, Please take your seat. Concerned Minister is giving the reply. (शोर एवं व्यवधान) ये जो भी बोल रहे हैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : * * * * *। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये जो चौटाला जी ई०डी०सी० के पैसे की बात कर रहे हैं तो चौटाला जी आपके समय में जब आप मुख्यमंत्री थे तो आप उस पैसे में से तनख्वाह दे दिया करते थे। आपने तो यह गुड़गांव जिले के साथ किया है। आपका तो कम से कम गुड़गांव जिले के बारे में कुछ कहना बनता ही नहीं है। कैसे पैसे लेकर रोज गाड़ी आपके निवास की तरफ चलती थी, इस बारे में सबको मालूम है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे कहना चाहूंगा कि ये सदन की गरिमा बनाए रखें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : * * * * *। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठें। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) आपको आपकी बात का रिप्लाई भी तो देना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान) सदन के नेता खड़े हैं, आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इन्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए। इन्हें सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) आप अध्यक्ष से इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please take your seat. (शोर एवं व्यवधान) सद्दाम हुसैन के तरीके से यह सदन नहीं चलेगा। (शोर एवं व्यवधान) Please sit down. Please take your seat. यह सदन इस तरीके से नहीं चलेगा। (शोर एवं व्यवधान) यह डैमोक्रेटिक लोगों का सदन है। यह प्रजातन्त्र में विश्वास रखने वाले लोगों का सदन है। (शोर एवं व्यवधान) सदन के नेता खड़े हुए हैं, मंत्री जी भी रिप्लाई देना चाह रहे थे और आप बीच में बोलते जा रहे हैं। आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) Nothing to be recorded. (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, * * *

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, * * *

श्री बलवन्त सिंह सढौरा : * * *

श्री अध्यक्ष : इनकी कोई भी बात रिकॉर्ड न की जाए, आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। Nothing to be recorded.

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल लोकदल के सभी सदस्य सदन की वैल में आ गए और जोर-जोर से बोलने लगे।)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) डॉक्टर साहब, आप कल भी हाउस में आए हुए थे। कल आपने क्यों नहीं इस बारे में बोला। (शोर एवं व्यवधान) एक मछली सारे तालाब को खराब करती है। आप सभी अपनी-अपनी सीट पर बैठें।

श्री आनन्द सिंह डांगी : स्पीकर साहब, क्या ये 600 रुपये की हाजिरी लगाने के लिए ही आए थे? (शोर एवं व्यवधान)

वाक-आऊट

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर आप हमारी गुड़गांव में पीने के पानी की कमी के बारे में बात नहीं सुनना चाहते हैं तो हम इसके विरोध में सदन से वाक-आऊट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल लोकदल के सभी सदस्य सदन से वाक-आऊट कर गए।)

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, जब भी चौटाला साहब यहां से उठकर चले जाते हैं तो उस समय इन्दौरा साहब बड़े खुश होते हैं। ये तो इस पर खुश होते हैं। स्पीकर सर, एक बात इस सदन के लिए गहन चिन्ता का विषय है। लोकदल के सारे सदस्य बड़े ही शांतिप्रिय तरीके से बैठते हैं और सदन में पार्टिसिपेट भी करते हैं। कल आपने डेढ़ घंटे का समय तो अकेले डॉक्टर सीताराम जी को बोलने के लिए दिया था। इनके सारे सदस्य यहां पर मौजूद भी थे लेकिन दो दिन से इन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। परन्तु हर बार जब भी चौटाला जी आते हैं तो इस सदन की जो परम्पराएं हैं, परिपाटी है, जो मर्यादाएं हैं उनका जघन्य उल्लंघन किया जाता है। ऐसा लगता है कि एक सोची समझी नीयत और नीति से वह यहां पर आते हैं। कुर्सी पर बैठने से पहले ही वह तैयारी करके आते हैं कि किसी प्रकार से सदन न चले, किस प्रकार से सदन के अन्दर व्यवधान डाला जाए, किसी भी प्रकार से कोई न कोई बात कहकर चेयर के ऊपर आक्षेप करके या किसी और माननीय सदस्य जो पड़ौस में बैठे हैं, उनके ऊपर आक्षेप करके ऐसा व्यवहार करते हैं जिसे किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही कहूंगा कि यह सदन के लिए जरूर एक चिंतन का विषय है कि एक व्यक्ति जो केवल इस सदन के अन्दर आता है तो वह इस तरह का व्यवहार क्यों करता है। उनकी बाकी पूरी पार्टी से तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, आपने भी कई बार देखा होगा कि वे पीछे बैठकर मुस्कराते रहते हैं। वे गंभीर से गंभीर मुद्दा उठाएं हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब चौटाला जी वाक-आऊट करके जाते हैं या जब जबरदस्ती नेम होकर जाते हैं तो उनकी पूरी पार्टी बड़ा आनन्द लेती है क्योंकि सच बात तो यह है कि वे भी बेचारे उनसे दुःखी हैं। इन दुखियों को भी मौका मिल जाता है इसलिए वे भी इन सारी बातों में शामिल हो

जाते हैं वे यह सोचते हैं कि किसी प्रकार से जल्दी वे चले जाएं और उनसे इनको छुटकारा मिल जाए। इसलिए मेरा कहना है कि सदन को इस मामले पर विचार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में एक मामला उठा है। सरकार की तरफ से हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि गुड़गांव के अंदर पीने के पानी की समस्या की जो चर्चा इस सदन में की गयी उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं, हालांकि वे लोग इस बात को सुनने के लिए रुके नहीं है। मैं आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूंगा कि सरकार इस समस्या को लेकर प्रयत्नशील है। मुख्यमंत्री जी को इस बात की बहुत चिंता है। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि कल तक गुड़गांव के अंदर वाटर सप्लाई रिस्टोर कर दी जाएगी। हमने जो इस बारे में प्रयास किए हैं यह उसी का नतीजा है। गुड़गांव में वाटर सप्लाई डिस्टर्ब इसलिए हुई क्योंकि जो गुड़गांव वाटर कैनाल है उसके अंदर ब्रीच हो गया था। यह सबको मालूम है कि कैनाल में पीछे ब्रीच कर लिया गया था। इसी वजह से गुड़गांव में जो वाटर सप्लाई स्टोरेज फैसेलिटीज है वह दो तीन दिन की है वह डिस्टर्ब हो गयी थी। जैसे ही यह ब्रीच हुआ मुख्यमंत्री जी ने 21 तारीख की रात को ही सारे अधिकारियों को बुला लिया था। इनको तो मालूम नहीं है क्योंकि ये तो 5-6 दिन की बात कहने लग रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इनकी तो कोई रुचि इस बात को देखने में नहीं है कि गुड़गांव के अंदर क्या सुविधा है, क्या दिक्कत है। अध्यक्ष महोदय, 21 और 22 तारीख के बीच की रात को मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलायी जिसमें चीफ सैक्रेटरी मौजूद थे, मुख्तलिफ अधिकारी मौजूद थे। उसके बाद इमीडियेट जो निर्णय लिये गये, उनका क्रियान्वयन कर लिया गया है। मैं उन बिन्दुओं के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा। एक तो कैनाल पर भविष्य में ब्रीच न हो उसके लिए वहां परमानैंट पुलिस पोस्ट लगा दी गई है। जिन लोगों ने यह ब्रीच किया था, उन 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पैट्रोलिंग की व्यवस्था कर ली गई है ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। समस्या से निपटने के लिए 210 ट्रैक्टर टैंकर और 65 ट्रक माउंटेड टैंकर जो कि सामान्य ट्रैक्टर टैंकर से चार गुना बड़ा होता है, ऐसे टैंकरों को 24 मार्च को अरेंज कर लिया गया था। 500 से ज्यादा ट्रिप्स लगा रहे हैं। मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि हुडा और वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन डिपार्टमैंट ने कंट्रोल रूम बनाए हैं उनके बाकायदा फोन नंबर हैं, यदि किसी को पानी की समस्या होती है तो वह हमें फोन कर दें तो हम तुरन्त टैंकर भेज देते हैं। अध्यक्ष महोदय, सभी ट्यूबवैल्स इस समय गुड़गांव में चल रहे हैं और एक जे०ई० को उसका इन्चार्ज लगाया गया है। जो ऐडवर्सली अफेक्टिड ऐरियाज हैं जैसे सैक्टर 4, 7, 14, 15, 21, 22, 23 और ओल्ड म्युनिसिपल टाउन, वहां पर हमने स्पेशल मैयर्ज लिए हैं और इसके अलावा जो प्राइवेट कालोनीज के जो ट्यूबवैल्स और पम्प्स हैं, वे भी अर्जैंट रिक्वायरमैंट के लिए ले लिए हैं और पानी की सप्लाई सुनिश्चित कर रहे हैं। कैनाल की रिपेयर का काम वारफुटिंग पर हो रहा है और उसे आज शाम तक पूरा कर लिया जाएगा।

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, उस कैनाल की रिपेयर पूरी कर दी गई है।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने हमें 5 हुक्म और दिये हैं। हमें मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो एन०सी०आर० वाटर सप्लाई चैनल है इसकी कंस्ट्रक्शन ऐक्सपेडाइट की जाए। इस चैनल की कैपेसिटी 500 क्यूसिक की थी अब इसको हम 800 क्यूसिक तक ले जाएंगे ताकि लॉंग टर्म नीड्स पूरी हो सकें। हुडा का जो वाटर वर्क्स है पहले उसकी स्टोरेज कैपेसिटी तीन दिन की थी अब उसको इन्क्रीज करके 8 से 10 दिन की करने लग रहे हैं। इसके अलावा 20 एम०सी०डी० का वाटर टैंकर हुडा बना रहा है और इसे जल्द पूरा कर लेंगे। दमदमा लेक पर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सप्लाई हो सकती है। इस पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। पैट्रौलिंग और पुलिस पोस्ट का प्रावधान हमने किया है। कल तक रेगुलर सप्लाई रिस्टोर कर दी जाएगी। It is something that is beyond anybody's control. मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिये हैं उनका हम पूरी तरह से क्रियान्वयन कर रहे हैं। लॉंग टर्म मैयर्ज ले रहे हैं और उनकी मैंने चर्चा भी की है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन ने इस बात को गंभीरता से लिया है। वाकई में बड़ी गंभीर समस्या उभर गई थी लेकिन मैं जिला प्रशासन को और हमारे चीफ सैक्रेटरी और सारे प्रशासन को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने समय पर पानी उपलब्ध कराया है। समस्या के हल के लिए तुरंत 400 टैंकर वहां भेज दिये गये और पानी की कमी नहीं होने दी। कल तक पानी की नॉर्मल सप्लाई रिस्टोर हो जाएगी। इसके साथ ही मैं इस बात के लिए डिफैंस सैक्रेटरी और आर्मी चीफ का भी आभार प्रकट करना चाहूंगा कि 22 तारीख रात को एक बजे फोन करते ही उसी समय टैंकर भेज दिये और पानी उपलब्ध कराया। इस कार्य के लिए मैं जिला प्रशासन और अपने प्रशासन की भी सराहना करता हूं। यह बहुत ही गंभीर मामला हो जाता लेकिन समय पर बहुत अच्छा काम किया और कल तक वाटर सप्लाई सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी।

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगा कि पानी के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एन०सी०आर० वाटर सप्लाई चैनल की आधारशिला रख दी है जिसकी 65 किलोमीटर की लम्बाई है और जिसको बनाने पर 225 करोड़ रुपये की लागत आयेगी जो बहादुरगढ़, खरखौदा और गुड़गांव को पानी सप्लाई करेगी। उसकी वजह से 500 क्यूसिक पानी की सप्लाई बढ़ेगी और पानी की समस्या का समाधान हो जायेगा। जहां तक गुड़गांव कैनाल को ठीक करने की बात है यह 24.3.2008 को ठीक कर दी गई है और कल तक गुड़गांव में पानी पहुंच जायेगा।

एक किसान की मौत के कारण आन्दोलन संबंधी मामला उठाना

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं किसानों के बारे में कहना चाहूंगा कि भिवानी कोर्ट में किसान अपनी एक छोटी सी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं।

उनकी मांग यह है कि जिन किसानों को शहीद का दर्जा सरकार ने दिया है जो कई काण्डों में मारे गये थे उनमें भिवानी जिले के लुहारू तहसील के फरतिया गांव का एक महावीर सिंह स्योराण भी है। मेरा सरकार से निवेदन है कि उस महावीर सिंह को भी शहीद का दर्जा देकर उसके परिवार के एक सदस्य को सरकार की पॉलिसी के हिसाब से नौकरी दी जाए क्योंकि यह महावीर सिंह 19 फरवरी 1981 को किसानों के आन्दोलन में मारा गया था। दूसरी बात भिवानी के सब-डिविजन सिवानी में लगभग पिछले 9 साल से अकाल पड़ रहा है वहां के किसान बुरी तरह से पीसे हुए हैं। सरकार को कोई ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि वे बेचारे किसान भूख से बच सकें क्योंकि वे आज भूख से मरने की पोजीशन में आ गये हैं। तोशाम की भी यही पोजीशन है लेकिन तोशाम के बारे में तो मंत्री महोदया बैठी हैं, वे ज्यादा जानती हैं।

वन मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपने इलाके की फिक्र करें। तोशाम की फिक्र न करें। तोशाम में अगर कोई दिक्कत होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके वहां का समाधान करवा लेंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सदन में बात उठाई हैं मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। भिन्न-भिन्न काण्डों में दर्जनों किसान मारे गये थे। जैसे कई बार कण्डेला में जो गुप्ता जी का विधान सभा क्षेत्र है, मेरा जिला है वहां पर दर्जनों किसान मारे गये थे। वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले आये थे और भिवानी में कादमा, मण्डियाली में भी कई किसान मारे गये थे। वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय कर दिया था कि जो किसान ऐसे काण्डों में पुलिस की गोली से मारे गये हैं उन सब के परिवार के एक सदस्य को सरकार रोजगार देगी। ऐसा पहली बार हुआ है क्योंकि ये सारे काण्ड इस सरकार के आने से पहले ही हुए थे। लेकिन चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने यह निर्णय किया कि जो कण्डेला, मण्डियाली, कादमा में किसान मारे गये हैं उनके परिवार के एक सदस्य को जो इलीजीबल होगा उसको रोजगार दिया जायेगा और उन सभी को रोजगार दे दिया गया है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने लुहारू में पब्लिक मीटिंग में महावीर सिंह के बारे में घोषणा कर दी थी।

वर्ष 2008-09 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा
(पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, general discussion on Budget Estimates for the year 2008-09 will resume. Now, Shri Jai Singh Rana will speak.

श्री जय सिंह राणा (नीलोखेड़ी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। आदरणीय वित्त मंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह जी ने 18 मार्च, 2008 को वर्ष 2008-09 का बजट इस सदन में पेश किया है। यह बहुत ही अच्छा बजट है। इस बजट की सराहना मैं ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के लोग कर रहे हैं क्योंकि इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। हर वर्ग को राहत देने का कार्य इस बजट में किया गया है। किसी भी क्षेत्र में कोई कर न लगाकर सरकार ने अपनी उदारवादी नीतियों का प्रमाण दिया है। हरियाणा के आर्थिक सर्वे के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्यों पर वृद्धि वर्ष 2005-06 में 9.2 प्रतिशत और 2006-07 में 11.4 प्रतिशत थी जो कि उल्लेखनीय है। अर्थ व्यवस्था की विकास की दर 9 परसैंट से अधिक हुई है जो पिछले 3 वर्षों की सरकार की सही दिशा और दशा की ओर इशारा करती है। चालू वर्ष में उद्योग और सेवा क्षेत्र में क्रमशः 10 प्रतिशत और 12 प्रतिशत की वृद्धि होने की सम्भावना है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इन क्षेत्रों की वृद्धि क्रमशः 9.4 प्रतिशत और 10.7 प्रतिशत है जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। पिछले वर्षों में अन्य सैक्टर्ज जैसे सर्विस सैक्टर, ट्रैड कम्युनिकेशन सैक्टर, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, सोफ्टवेयर और आई०टी० सैक्टर में विकास की दर बहुत अच्छी रही है जिसका नतीजा यह रहा है कि हरियाणा प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वह बढ़ी है और हरियाणा आज प्रति व्यक्ति आय में दूसरे नम्बर पर है। मुझे यह भी उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में नम्बर एक पर होगा। वर्ष 2006-07 में प्रति व्यक्ति आय 49038 रुपये थी जो बढ़कर वर्ष 2007-08 में 56280 होने का अनुमान है जो प्रदेश की प्रगति को दर्शाता है और जो सरकार के प्रयासों का नतीजा है। प्रति व्यक्ति आय में गोवा के बाद हरियाणा दूसरे नम्बर पर है। मुझे उम्मीद है कि यह प्रदेश जल्दी ही नम्बर एक पर होगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो मेहनत और लगन से प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय की दर गोवा के बाद नम्बर एक पर है इसको और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह फिस्कल मैनेजमैंट के मामले में भी सरकार सफल रही है और इसके लिए वित्त मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। मैं वित्त मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि इस उपलब्धि के कारण प्रदेश सरकार ऋण रिलीफ और ब्याज रिलीफ हो गई है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में किसानों के लिए हरियाणा की सरकार ने, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने जो किया है आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। जैसे कि किसानों के बिजली के बकाया बिलों के 1600 करोड़ रुपये माफ करके उनको राहत देने का काम किया गया है, उसके बाद इस साल में किसानों का जो कर्जा माफ किया गया है, उससे भी किसानों की दशा में सुधार आया है। इस साल का केन्द्र का जो बजट है उस बजट में 60 हजार करोड़ रुपये केन्द्र की सरकार ने किसानों के कर्जे माफी के लिए दिए हैं और उससे हरियाणा प्रदेश के किसानों को भी बहुत लाभ मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, आज के दिन हरियाणा प्रदेश का किसान हमारी सरकार से और भी उम्मीद रखता है क्योंकि जो मदद किसान की अभी तक की गई है, वह किसानों को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए पर्याप्त

नहीं है। हरियाणा प्रदेश का किसान मेहनत करने वाला है। सरकार ने किसानों का जो ब्याज माफ किया है या कर्जा माफ किया है उसके बावजूद भी किसान उस स्थिति में नहीं आ पा रहा है जो स्थिति एक किसान की होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, हरियाणा प्रदेश की उन्नति और तरक्की किसान की उन्नति और तरक्की पर निर्भर करती है। हमारे प्रदेश में यदि किसान की स्थिति बेहतर होगी तो हमारे यहां के व्यापारियों, दुकानदारों और खेतीहर मजदूरों की स्थिति भी बेहतर होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि हमारे प्रदेश के किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार को बहुत से ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले यह बात जानने की जरूरत है कि किसानों पर कर्जा क्यों चढ़ता है, किसान ही सबसे ज्यादा कर्जदार क्यों होते हैं? इस बारे में अर्थशास्त्रियों, कृषि विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों की एक कमेटी बनानी चाहिए जो उन कारणों को जाने कि किसानों पर कर्जा क्यों चढ़ता है और किस प्रकार से किसानों को कर्जे से मुक्त किया जा सकता है। बार-बार कर्जा देना और माफ करना तथा फिर कर्जा चढ़ना यह किसानों के लिए और हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। हमें कारणों को जानकार ऐसी व्यवस्था लानी चाहिए जिससे हमेशा-हमेशा के लिए किसान कर्ज से मुक्त हों और दोबारा से किसानों पर कर्जा न चढ़े। अध्यक्ष महोदय, आप सभी जानते हैं कि यदि किसान को एक अच्छी फसल मिल जाये तो किसान उभर जाता है और यदि किसान की एक फसल खराब हो जाये तो किसान कर्जदार हो जाता है। पिछले दिनों ओलावृष्टि से किसानों की फसलों का जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने उदार हृदय होकर दिया और इतना मुआवजा किसानों को दिया जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दिया। जो लोग हमेशा किसानों के नाम पर राजनीति करते आये हैं उन्होंने भी कभी किसानों को इतना मुआवजा देने के बारे में नहीं सोचा जितना मुआवजा हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों प्रदेश के किसानों को दिया है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जितना भी नुकसान किसान की फसल को प्राकृतिक आपदा से हो वह पूरा नुकसान सरकार की तरफ से किसान को मिलना चाहिए जिससे किसान की स्थिति मजबूत होगी और किसान कभी भी कर्जदार नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, सामने वाले साथी आज उठकर चले गये। जिस दिन चौटाला जी सदन में आते हैं उस दिन से लोग हंगामा करके चले जाते हैं। चौटाला जी जो बातें लोगों में जाकर कहते हैं वे बातें हम उनसे यहां सुनना चाहते थे। लेकिन इनके पास कोई बात बोलने के लिए नहीं है और न ही सरकार के बजट में कोई नुक्ताचीनी है जिसके बारे में वे बात करते। अध्यक्ष महोदय, चौटाला जी अब प्रदेश के किसानों को कहते हैं कि एक बार मुझे मौका दे दो मैं तुम्हारा सात पीढ़ियों का इन्तजाम कर दूंगा, मेरा तो हो गया, अब तुम्हारी बारी है। अध्यक्ष महोदय, यही बात हम उनसे यहां सुनना चाहते थे कि वह कौन सा तरीका है जिससे चौटाला जी किसानों का सात पीढ़ियों का इन्तजाम कर देंगे। अगर वे इस बारे में सुझाव यहां सदन में देते और उनका सुझाव वाकई में किसानों का सात पीढ़ियों का इन्तजाम करने वाला होता तो हम भी हमारे मुख्यमंत्री जी से कहते कि वे चौटाला जी के सुझाव पर अमल करें। स्पीकर सर, किसान की जो खेती है उसको भी उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए और जहां तक इंश्योरेंस की बात है

[श्री जय सिंह राणा]

उसकी सभी फसलों का पूरा बीमा होना चाहिए ताकि अगर किसी कारणवश फसलें खराब हो जाती हैं तो उसे उनका पूरा मुआवज़ा मिल सके। स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व वाली हमारी राज्य सरकार ने जो अनुसूचित जातियों और बी०पी०एल० के अन्दर आने वाले परिवारों के लिए 100-100 गज के प्लाटों के आबंटन का फैसला किया है यह एक बहुत ही अच्छी बात है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इन लोगों को सरकार द्वारा अभूतपूर्व सहायता दी जा रही है। इस मामले में यह एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे हरियाणा प्रदेश में अनुसूचित जाति की जो संख्या है वह कुल जनसंख्या का 19.35 प्रतिशत है और उनके कल्याण और विकास के लिए हमारी सरकार के वर्तमान बजट में कुल बजट का 21.55 प्रतिशत प्रावधान रखा गया है। यह एक बहुत बड़ी बात है जो कि गरीबों और अनुसूचित जातियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी की उदारता और लम्बी सोच की सबूत है। जहां तक बी०पी०एल० के परिवारों को 100-100 गज के प्लाटों के आबंटन के फैसले का सम्बन्ध है इसकी चारों तरफ बहुत भारी प्रशंसा हो रही है। जिनके पास घर बनाने के लिए जगह नहीं थी सरकार के इस फैसले से उनके मन में खुशी की लहर दौड़ गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में एक और बात यह भी लाना चाहूंगा कि अनुसूचित जातियों के अलावा भी हरियाणा में अनेक जातियां ऐसी हैं जो कि पिछड़े वर्ग में आती हैं और वे इनसे भी बहुत ज्यादा गरीब हैं। जैसे हमारे इलाके में कश्यप हैं जिनको झींवर भी कहते हैं। ये बहुत ही गरीब लोग हैं। इसी प्रकार से और भी गरीब जातियां हैं जैसे नाई, धोबी, तेली और जोगी वगैरह। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि ये जातियां भी अनुसूचित जाति की तरह ही सरकार की कल्याणकारी नीतियों से लाभ उठाने की पात्र हैं इसलिए इनको भी बी०पी०एल० स्कीम में शामिल करके इनको भी पूरा लाभ पहुंचाना चाहिए। इसके साथ-साथ बहुत से ऐसे भूमिहीन लोग भी हैं जो कि स्वर्ण जातियों से सम्बन्ध रखते हैं लेकिन बहुत ज्यादा गरीब हैं। उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि ये जो बी०पी०एल० के मापदण्ड हैं ये केन्द्र सरकार के द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार हैं इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि एक बी०पी०एल० स्कीम हमें अपने हरियाणा प्रदेश की अलग से बनाना चाहिए जिसमें हमें उन जातियों और वर्गों को शामिल करना चाहिए जो किसी कारणवश इससे छूट गये हैं ताकि ये सुविधायें हर गरीब आदमी को मिल सकें और इनके लाभों से कोई पात्र, गरीब आदमी वंचित न रहे। स्पीकर सर, प्रदेश सरकार ने ऋण माफी और शहरों के विकास के लिए भी अनेक ठोस एवं कारगर कदम उठाये हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने अपने वर्तमान बजट में बहुत सी रियायतें दी हैं चाहे वह कार ऋण की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख करने की बात हो या फिर घर बनाने के लिए मिलने वाले ऋण की सीमा 7.50 लाख से बढ़ाकर 12.50 लाख करने की बात हो। इसके लिए भी सरकार की जितनी तारीफ की जाये वह कम होगी। स्पीकर सर, वर्तमान बजट में प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी सरकार द्वारा भरसक प्रयास किये गये हैं। जैसे सरकार द्वारा जहां पर अध्यापकों की कमी थी उस कमी को

स्थाई बंदोबस्त होने तक दूर करने के लिए गैस्ट टीचर्ज की नियुक्ति की गई है।

Mr. Speaker : Please wind up, Rana ji.

श्री जय सिंह राणा : स्पीकर सर, मैं थोड़ी सी बात और कहकर अपनी बात समाप्त कर देता हूं। स्पीकर सर, जहां तक हरियाणा प्रदेश के विकास की बात है मैं समझता हूं कि सम्पूर्ण हरियाणा प्रदेश का विकास समानता के आधार पर होना चाहिए। सरकार ने पूरे प्रदेश में 91 गांवों को आदर्श गाँव का दर्जा दिया है। हरियाणा प्रदेश में बहुत से ऐसे गांव हैं जिनको आदर्श गांव का दर्जा दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से भाई आनन्द सिंह दांगी कह रहे थे कि जहां मेरे जैसे विधायक गांव में रह रहे हों कम से कम उन गांवों को तो उस श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। यहां पर मुख्य संसदीय सचिव महोदय बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी की तरफ से वे ही इस कार्य को देखते हैं, तो मैं उनसे आश्वासन चाहता हूं कि मेरे गांव को आदर्श गांव का दर्जा देंगे।

श्री अध्यक्ष : राणा साहब, ठीक है। सी०पी०एस० साहब इसको कंसीडर कर लें बाकि आप लिख कर भिजवा दें, आपका पढ़ा मान लिया जायेगा।

श्री जय सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट का समय और दे दीजिए मैं अपनी बात को कंकल्यूड कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप 16 मिनट तक बोल चुके हैं और भी सदस्य बचे हुए हैं जिनको बोलना है। आपका समय पूरा हो चुका है अब आप बैठ जाइये। I know your capacity. I know the capacity of every member. I know you can speak for hours but I have to give chance to every member. मैडम राजरानी पूनम, अब आप बोलिए।

श्री जय सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसका धन्यवाद।

श्रीमती राजरानी पूनम : अध्यक्ष महोदय, मैं आज नहीं बोल पाऊंगी मुझे कल बोलने का समय दे देना।

श्री बचन सिंह आर्य : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने 18 मार्च को 2008-09 का जो सुन्दर बजट पेश किया है उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी और सरकार को धन्यवाद देता हूं। यह एक बहुत ही सुन्दर और सराहनीय बजट है। इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना, उच्चकोटि की शिक्षा प्रदान करना, बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाना, समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण पर जोर देना और सुदृढ़ आधारभूत ढांचा तैयार करना ये सब विशेष प्राथमिकताएं इस बजट में रही हैं। स्थानीय साहूकारों और आढ़तियों से किसानों ने बहुत ऊंची दरों पर ऋण ले रखे हैं, इस समस्या के समाधान के प्रति बजट में पूरी तरह से चिन्ता जताई गई है। अध्यक्ष

[श्री बचन सिंह आर्य]

महोदय, महिलाओं के लिए स्टाम्प शुल्क की दरों में एक प्रतिशत की कमी करना, न्यूनतम मजदूरी 3510 रुपये करना। प्रत्येक गाँव में ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिनों का रोजगार देना अपने आप में अभूतपूर्व कार्य है। मुख्यमंत्री अनुसूचित शिक्षा प्रोत्साहन स्कीम नामक क्रान्तिकारी योजना के तहत सभी बी०पी०एल० परिवारों एवं अनुसूचित जाति के सभी छात्रों को छात्रवृत्तियाँ, यूनिफार्म और स्कूल बैग्स के रूप में राहत देना सरकार की विशेष उपलब्धियाँ हैं। पेयजल आपूर्ति एवं स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा गया है। अनुसूचित जाति के परिवारों को निःशुल्क पेयजल कनैक्शन देना, मुफ्त पानी की टंकी और टूंटी देना विशेष सराहनीय कार्य हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सफीदों में भी पीने के पानी के ट्यूबवैल लगवा कर कड़वे पानी से छुटकारा दिलवाया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और जनस्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। मेरे पैतृक गाँव भुसलाना में पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर ने पीने के पानी के लिए ट्यूबवैल का 1.10.07 को शिलान्यास किया था अभी तक उसका पैसा नहीं गया है, कृपया, उसकी स्वीकृति देने का कष्ट करें। कम से कम 18-20 ट्यूबवैल का पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर जी ने शिलान्यास किया था, उन सभी का काम पूरा हो चुका है और चालू हो चुके हैं इसके लिए मैं पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर का आभार व्यक्त करता हूं। सड़क बनाने और पुलों का निर्माण करके मुख्यमंत्री जी द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाये गये हैं। 37 सड़क ऊपरगामी पुल स्वीकृत करके विशेष रिकॉर्ड कायम किया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सफीदों में सड़कों की पिछली सरकार की देन, जर्जर हालत को सुधारने हेतू 4.31 लाख रुपये दिये हैं। इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं और विनम्र अनुरोध करता हूं कि विभाग द्वारा कार्य जल्दी करवाएं। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र के साथ लगते हुए छछड़ाना असन्ध में एक शूगर मिल लगवाई है जिससे वहां के क्षेत्र के किसानों की एक बहुत पुरानी मांग पूरी हुई है और सरकार का यह एक ऐतिहासिक कदम है। इस क्षेत्र में किसान गन्ने की बिजाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। यह ऐरिया मेरे हल्के के साथ ही लगता ऐरिया है। यह शूगर मिल मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव से चार किलोमीटर दूरी पर है। यहां से गन्ना मिल तक जाने का रास्ता कच्चा है जिसके कारण वहां पर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर इस सड़क को बनाया जाए ताकि मिल में गन्ना आसानी से ले जाया जा सके। स्पीकर सर, इसी तरह से रोहड़ से शाजूखुर्द सड़क, सालावास से बिरवाना सड़क, सानपुर से धर्मगढ़ सड़क तथा बुड्ढाखेड़ा से खरगा तक सड़क का निर्माण करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का विकास करने का निर्णय लिया है जिसके तहत 91 गांवों को आदर्श गांवों के रूप में विकसित करने के लिए चयन किया गया है। सरकार से मेरा यह नम्र निवेदन है कि मेरे इलाके के दो गांव कालवा एवं मुआना को आदर्श गांव का दर्जा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गांव-गांव में खेल स्टेडियम बना कर सराहनीय कार्य किया है। मेरे क्षेत्र में गांव डिडवाना में स्टेडियम बनवाने की कृपा करें। इस बारे में पंचायत का रैजोल्यूशन

भी विभाग के पास आया हुआ है। इतना ही नहीं सरकार ने शिक्षा में रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियां हासिल की है। बहुत बड़ी संख्या में स्कूलों का दर्जा बढ़ाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में गांव रोहड़ का स्कूल सन् 1958 से अब तक आठवीं कक्षा तक का है। यह गांव सिख भाईयों की आबादी वाला गांव है। सरकार से मेरा निवेदन है कि इस स्कूल को दसवीं कक्षा तक अपग्रेड करने की कृपा करें तथा राम नगर गांव में गवर्नमैंट मिडल स्कूल को गवर्नमैंट हाई स्कूल तक अपग्रेड करने की कृपा करें। इस स्कूल में कमरे बने हुए हैं और यह स्कूल अपग्रेडेशन की सारी शर्तें पूरी करता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस स्कूल को अपग्रेड करने के लिए पिछली सरकार के समय में 'सरकार आप के द्वार' कार्यक्रम के तहत उस समय के मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी दिनांक 5.1.2004 को उस गांव में गये थे। लन्च भी उन्होंने वहीं पर किया था और वहीं पर आराम भी किया था। वहां के छोटे-छोटे किसान चन्दा इकट्ठा करके स्कूल अपग्रेड करवाने के लिए उन्हें लेकर गए थे और उन्होंने वहां पर इस स्कूल को अपग्रेड करने की हामी भरी थी। चन्दा इकट्ठा करके 51 हजार रुपये की माला वहां के उस समय के सरपंच श्री मदन सिंह मलिक ने श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के गले में डाली थी और गांव के लोगों ने उनसे एक ही मांग रखी थी कि हमारे स्कूल को अपग्रेड किया जाए। उस समय के मुख्यमंत्री ने पूरे गांव के आगे स्कूल अपग्रेड करने की घोषणा की थी। उनके फोटो भी हैं और टेप भी गांव के लोगों के पास हैं मगर इस स्कूल को अपग्रेड करने का काम नहीं हुआ। मेरा अपने विकास पुरुष मुख्यमंत्री और सरकार से अनुरोध है कि गांव के लोगों की मांग और आवश्यकता को देखते हुए इस स्कूल का दर्जा बढ़ाने की कृपा करें। उन्होंने हरियाणा प्रदेश को देश का नम्बर वन प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है। हमारे विकास पुरुष मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के कार्यों का सभी साथियों को प्रदेश हित में समर्थन करना चाहिए। बी०जे०पी० के हमारे साथी सदस्य और बसपा के एकमात्र सदस्य राजनैतिक तथा वैचारिक भिन्नता होते हुए भी सरकार की सही बात को सही मानते हैं और हम जो 10 इंडिपैंडैंट साथी जीत कर आए हैं हरियाणा के विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री जी का तहेदिल से साथ दे रहे हैं। हमारे साथी जो हमारे सामने बैठते हैं लेकिन इस समय हाउस में उपस्थित नहीं है और उठ कर बाहर चले गए हैं, मैं उनकी पार्टी के साथियों को भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश के हित में उन्हें आदरणीय मुख्यमंत्री और सरकार का समर्थन और सहयोग करना चाहिए ताकि हरियाणा प्रदेश की जनता में एक अच्छा संदेश जाए। अध्यक्ष महोदय, सरकार की अच्छी और सही बात को भी जानबूझ कर गलत ढंग से पेश करना, खाली नुक्ताचीनी करना और गलत परम्पराओं से ओछी राजनीति करना, गलत रिवाज डालने के सिवाय कुछ नहीं है। हरियाणा सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कद उनके कार्यों की वजह से हरियाणा की जनता में सच्चे, सज्जन, शरीफ, ईमानदार और श्रेष्ठ कार्यकुशलता से हिमालय की तरह इतना ऊंचा हो चुका है कि उसको छू पाना अहंकारी और हताश लोगों के सामर्थ्य से बाहर की बात है। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बिना क्या यह हो सकता था कि दो हजार करोड़ रुपये के बजट की बजाय तीन गुणा से भी ज्यादा 6600 करोड़ रुपये का बजट पेश हो, क्या यह हो सकता था 1600 करोड़ रुपये के किसानों के बिजली के बिल

[श्री बचन सिंह आर्य]
माफ हो जाएं, क्या यह हो सकता था कि अंग्रेजों के समय का काला कानून जो किसान की गिरफ्तारी का था, वह समाप्त हो जाए? क्या यह हो सकता था कि 830 करोड़ रुपये के गांव के किसानों और गरीब व्यक्तियों के ब्याज माफ हो जाएं? क्या यह हो सकता था कि अढ़ाई-तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल के भाव से किसानों का धान बिक जाए? क्या यह हो सकता था कि 100-100 गज के प्लॉट गरीब आदमियों को रहने के लिए दे दिये जाएं? क्या यह हो सकता था कि हांसी बुटाना लिंक नहर का निर्माण हो जाए? क्या यह हो सकता था कि किसानों की ऊबड़-खाबड़ जमीन जो डेढ़ से दो लाख रुपये प्रति एकड़ की कीमत की थी वह 25-30 लाख रुपये की हो जाए? क्या यह हो सकता था कि हरियाणा में गुण्डागर्दी खत्म करके प्रत्येक शहर एवं गांव का व्यक्ति सुख, अमन और चैन का जीवन जीये? सोनिया गांधी जी और प्रधान मंत्री जी को सलाह देकर किसानों के 60,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ करवाने का सराहनीय कदम उठाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के लिए दिल से निकले हरियाणा के हित में उदगारों की यह पंक्तियां प्रत्येक हरियाणावासी खेतों, खलियानों और बाजारों में गुणगुणाता फिरता है।

''जिन्दगी की असली उड़ान अभी बाकी है,
हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है,
अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमनें,
आगे सारा आसमान बाकी है।''

आज इनके होते हुए हरियाणा का किसान, मजदूर, व्यापारी और प्रत्येक वर्ग आगे बढ़ेगा। आज मुख्यमंत्री जी ने राजनीति को बिलो कर रख दिया है। अध्यक्ष महोदय, जब दही को बिलोया जाता है तो उसमें कुछ समय बाद मक्खन ऊपर आ जाता है। इसी तरह से जब आने वाले समय में चुनाव का रिजल्ट आएगा तो उसको सब देखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आने वाले चुनावों में जो भी मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का नाम लेकर चुनाव में जाएगा वही विधान सभा में आ पाएगा क्योंकि इनके कामों को जनता द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार द्वारा किए गए कार्य बहुत ही जबरदस्त हैं। अध्यक्ष महोदय, महर्षि दयानन्द जी ने ''सत्य और प्रकाश'' के चौथे अध्याय में लिखा है कि जो ठीक तरह से बरतता है, उसको ठीक तरह से बरतना चाहिए। उसमें यथायोग बर्ताव करने की बात कही गई है। जो दुष्ट है, उसको उसी ढंग से बरतना चाहिए। अगर इस तरह से नहीं किया गया तो सारा वातावरण खराब हो जाएगा। इस बात के लिए मैं अध्यक्ष महोदय जी की प्रशंसा करता हूं कि जो साथी सदन के सारे माहौल को बिगाड़ते हैं उनके खिलाफ यथायोग कार्यवाही करके इन्होंने सदन के माहौल को ठीक किया हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी तो एक मीठे बेर की तरह हैं। जो भी उसको खाता है वह उसको याद रखता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय , जो कैर का फल होता है वह बहुत ही कड़वा होता है, तीखा होता है। अध्यक्ष महोदय, ये जो हमारे भाई सदन से उठकर चले गए हैं वो और पिछली सरकार के वक्त के मुख्यमंत्री हमारे आज के मुख्यमंत्री जी के सामने टिक नहीं सकते हैं, इनसे आंख

नहीं मिला सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि कैर के फल में और बेर के फल में अन्तर होता है। कैर का फल कड़वा होता है और वह कभी हजम नहीं होता है।

"कैर और बेर का मेल हो किस तरह,
एक तीखा है, एक मुलायम सजर,
ऐसे आते हैं, दुष्टाचारी नजर,
दूध इनको नहीं पिलाना चाहिए।"

स्पीकर सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती शकुंतला भगवाड़िया (बावल, अनुसूचित जाति) : स्पीकर सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें आम जनता को बहुत राहत दी गई है। इसमें विशेष तौर पर दिखाया गया है कि मुख्यमंत्री जी किसानों को राहत देंगे और भय मुक्त राज देंगे। हमारे साथ बैठने वाले साथी जो यहां से उठकर चले गए हैं उनके समय में बरसौला और झज्जर में बहुत दिक्कत आई थी और उन साथियों के मन में बहुत वहम था कि उनका वहां पर बहुमत है। लोगों ने इस बारे में फैसला कर दिया और उनके सदन में आठ-नौ आदमी ही आ पाए हैं। जनता ने यह बहुत ही सराहनीय काम किया है। इस सरकार ने शिक्षा के स्तर को ऊंचा किया है और उसमें भी महिलाओं का हित दिखाया है। छोटे आदमियों को राहत देने के लिए बड़े आदमी का ध्यान नहीं किया जाता है लेकिन मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी की सराहना करूंगी उन्होंने चौकीदारों के बारे में सोचा है, किसानों का और गरीब आदमियों का कर्जा माफ किया है। इसके लिए मैं सोनिया गांधी जी और प्रधानमंत्री जी की भी सराहना करूंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि जिस देश का किसान भूखा होता है, वह देश भी भूखा रहता है। जिस देश के किसान का पेट भरा होता है, उस देश का पेट भी भरा रहता है। आज एक प्रदेश का किसान अपने प्रदेश के लिए अनाज की पूर्ति नहीं करता है बल्कि दूसरे प्रदेशों के अनाज की भी पूर्ति करता है। यह वास्तव में सराहनीय बात है। स्पीकर सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगी और मैं इसके लिए सराहना भी करना चाहती हूं कि किसान का इतना बड़ा कर्जा माफ करके राहत दी गयी है। स्पीकर साहब, एक बड़ा व्यक्ति अपने खेत में काम नहीं कर पाता है। काम उस खेत में गरीब आदमी ही करता है लेकिन फायदा केवल साहूकार आदमी ही उठाता है। फैक्ट्री का मालिक तो बहुत बड़ा आदमी होता है लेकिन गरीब आदमी के हाथ में कुछ नहीं होता है। जो गांवों में छोटा-छोटा काम करते हैं और जिन्होंने छोटे-छोटे लोन ले रखे हैं जैसे बकरी पालन के लिए उन्होंने लोन ले रखे हैं तो उनको भी राहत सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए। स्पीकर सर, कहा उससे ही जा सकता है जिसमें कुछ करने की क्षमता हो।

श्री अध्यक्ष : मैडम, सभी मैम्बर्ज ने यह बात उठायी है so I would request all the members, kindly don't repeat the same things.

श्रीमती शकुंतला भगवाड़िया : स्पीकर साहब, हुड्डा साहब से ही ऐसी आशा रखी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : मैडम, भगवाड़िया तकरीबन हर मैम्बर्ज ने यह बात कही है।

श्रीमती शकुंतला भगवाड़िया : स्पीकर साहब, मैं तो उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती हूं इसलिए मैं यह बात कर रही हूं। करना या न करना यह मुख्यमंत्री जी की सोच है।

श्री अध्यक्ष : आप यह कहें कि इस बारे में जितने स्पीकर्ज बोले हैं उनके साथ मैं भी अपने आपको जोड़ती हूं।

श्रीमती शकुंतला भगवाड़िया : स्पीकर साहब, मैं भी अपने आप को जोड़ ही रही थी। मैंने तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी किया। स्पीकर साहब, एक बात मैं अपने हल्के के बारे में कहना चाहती हूं। मेरे हल्के के काकड़ी गांव में वोकेशनल ऐजुकेशन की बिल्डिंग बनी हुई है। मेरा निवेदन है कि उसको आई०टी०आई० में परिवर्तित कर दिया जाए। मैं इसके लिए सरकार की आभारी रहूंगी। इसके अलावा मेरे हल्के की कई ऐसी सड़के हैं जिनका निर्माण होना अभी बाकी है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कैप्टन अजय सिंह जी को रोड्ज का महकमा दिया है। मैं अपने आप भी उनसे सहयोग ले लूंगी। मैं साथ-साथ यह भी कहना चाहती हूं कि एक दिन मैं अचानक रिवाड़ी में वृद्ध होम में चली गयी। यह वृद्ध होम 1982 में बना होगा। यह बड़े दुःख की बात है मैंने वहां पर देखा कि उसके सारे शीशे टूटे हुए पड़े हैं और आज तक भी उनकी रिपेयर नहीं हुई है। वहां पर बजुर्ग आदमी बहुत दुःखी थे इसलिए मेरा सरकार से विनम्र अनुरोध है कि उस वृद्ध होम की तरफ विशेष रूप से ध्यान देकर उसकी सफाई करवायी जाए, उसमें सभी शीशे लगवाए जाएं। यह इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि जब रिवाड़ी जिला बना था तो उस समय सारे अधिकारीगणों ने वहीं पर बैठकर काम शुरू किया था। लेकिन बाद में वे सारे उस बिल्डिंग को ऐसे ही छोड़कर चले गए। उन्होंने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। मेरे हल्के में कई गांव ऐसे हैं जैसे मामड़िया गांव है जहां पर पानी खारा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी इस विभाग के मंत्री हैं इन्होंने हमें काफी सहयोग भी दिया है लेकिन आज भी पानी की वहां पर दिक्कत है। इसी तरह से और भी कई गांव हैं जैसे नांदापलवाड़ी है वहां पर भी पानी की दिक्कत है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह (मेवला महाराजपुर) : अध्यक्ष महोदय, सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हरियाणा के माननीय वित्त मंत्री जी ने अपना चौथा

बजट पेश किया है। कई रोज से यहां पर इस बजट पर चर्चा हो रही है। अध्यक्ष महोदय, जो बजट है वह किसी भी राज्य या राष्ट्र के विकास की तस्वीर होता है, आईना होता है एक ऐसा दस्तावेज होता है जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि विकास की दृष्टि से प्रदेश की स्थिति क्या है। अध्यक्ष महोदय, अगर हम इसकी अच्छी तरह से समीक्षा करें तो विपक्ष के साथियों ने दोनों डॉक्टर्ज ने ये जिक्र किया कि बजट में कोई विशेष बात नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले सालों की तुलना करें तो बिजली में, सिंचाई में और अन्य मदों में बजट का अनुपात घटा है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष का काम सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आलोचना ही करनी है। ऐसा कहना कि बजट नीरस है, बजट अच्छा नहीं है, यह बात उचित नहीं है। बजट की विपक्ष को भी गहराई से समीक्षा करनी चाहिए। उनको इस बात का ध्यान अवश्य करना चाहिए कि जब सरकार छोड़ी थी तो उस समय 2200 करोड़ भी नहीं, मात्र 2000 करोड़ रुपये से भी कम का बजट था। आज जो बजट है वह निरंतर तीन वर्षों में लगभग तीन गुना बढ़ा है। इसका भी अंदाजा लगाना चाहिए। इसे या तो नेतृत्व की बुद्धिमता कहें या क्या कहें कि संतुलित ढंग से हर मद में पैसा बांटने का प्रयास किया गया है कि किस विभाग को कितनी कहां आवश्यकता है? इन सब बातों का इस बजट में ध्यान रखने का प्रयास किया गया है। इस बात का भी विपक्ष को चिंतन करना चाहिए। यह बात निसंदेह काबिले तारीफ है। पुराने समय में वार्षिक योजना में 100 या हद से हद 200 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ करता था। किसी प्रदेश के बजट की सेहत वित्तीय प्रबंधन और संसाधनों के दोहन से लगाई जाती है और इसका पूरा ध्यान इस बजट में रखा गया है और इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय प्रशंसा और बधाई के पात्र हैं। यह बजट आज हरियाणा में ही नहीं बल्कि देश में भी आदर्श है। पंजाब प्रान्त हमसे बड़ा है, हिस्से में भी बड़ा है। पंजाब की स्थिति हर तुलना में पिछले वर्षों में हमसे आगे रही है लेकिन अब जैसा मैंने अखबारों में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने पंजाब का बजट 2210 करोड़ रुपये का पढ़ा था। हरियाणा के लिए इससे बड़ी तारीफ की बात हो नहीं सकती। वैसे तो हमारे बी०जे०पी० के साथी माननीय गौतम साहब फिराखदिल व्यक्ति हैं। उन्होंने भी एक तरीके से बजट का अनुमोदन किया है और बजट की प्रशंसा की है। दूसरी पार्टी से होते हुए भी उन्होंने प्रशंसा की है तो इससे आगे बजट के बारे में कुछ कहने की गुंजाइश रह ही नहीं जाती है। किसी भी राज्य का वित्तीय प्रबंधन और संसाधन दोनों ही बराबरी पर हैं और संतुलित हैं तो फिर प्रदेश के विकास के मामले में सर्वश्रेष्ठ होने में कोई संदेह नहीं रह जाता। जो प्राप्तियां हैं वह यदि 2003 से लेकर 2007 और 2008 तक देखी जाएं तो प्लान और नॉन प्लान में वह 10 हजार से लेकर पिछले 4-5 वर्षों में डबल हुई हैं। ऋण के जो उस समय हालात थे, वह आज तकरीबन 80-86 करोड़ रुपये रह गए हैं जो कि सैकड़ों हजारों करोड़ में थे। इससे ज्यादा प्रशंसा के लायक कोई बात हो नहीं सकती। आज जो राजस्व प्राप्तियां हैं वह वर्ष 2007 के 19629.69 करोड़ के मुकाबले में 21695.32 करोड़ हो गई हैं। इसलिए इस बजट को वास्तविक रूप से दूरदृष्टिपूर्ण, एक संतुलित और एक विकासशील बजट कहा जाये तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। इसलिए मैं कहूंगा कि यह बजट

[श्री महेन्द्र प्रताप सिंह]
विकासशील बजट है। इस बजट से मालूम होता है कि वह दिन दूर नहीं जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को सर्वोच्च स्थान पर लाने का है वह शायद एक आध साल में जरूर प्राप्त हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार को बने हुए तकरीबन तीन साल हो गये हैं, शायद यह वायदा कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं किया था। कांग्रेस पार्टी का इतिहास है कि जब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है वह जनता के विश्वास पर खरी उतरती है। जनता को यह विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ही देश को सुरक्षित रख सकती है। कांग्रेस पार्टी ही इस देश और प्रदेश को संभाल सकती है। इन तीन वर्षों में सरकार बनने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। जिसके लिए सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष के समझदार सदस्य उनकी प्रशंसा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल इस सरकार ने माफ किए हैं। जिनके नीचे किसान दब गये थे, मर गये थे उन बिजली के बिलों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कलम से माफ किया। 100-100 गज के प्लॉट गरीब वर्ग के लिए अपने एस०सीज० भाईयों के लिए देकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया जिसकी ऐसी कोई मिसाल कहीं और नहीं है। शहर और गाँवों में गृह कर माफ करना आज तक मेरे ख्याल में देश में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। मेरे ख्याल से संसाधन टैक्स जो उन्हीं शहरों और गांवों के लिए खर्च होते हैं खत्म करके एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं बजट की अलग-अलग मदों के बारे में जिक्र करना चाहूँगा अगर आप मुझे दस मिनट का समय और देंगे तो।

श्री अध्यक्ष : महेन्द्र प्रताप सिंह जी, आपने 11.24 बजे बोलना शुरू किया था और आपका समय 11.34 बजे तक है। Repeatedly if I say the same thing again and again, there is no meaning at all. आप जैसे सीनियर मैम्बर को तो कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दूसरे माननीय सदस्य भी बैठे हैं। 12-13 मैम्बर्ज बोलने बाकी हैं और आज डिसकशन का लास्ट डे है। It is my moral duty to give an opportunity to every Member.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, अब मैं सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूँ। पहली बार हरियाणा प्रदेश में सिंचाई के पानी का समान बंटवारा हुआ है ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक नहरी पानी अंतिम छोर तक पहुंच जाये। यह काबिले तारीफ है। इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जहां तक पानी के समान बंटवारे की बात है,समान बंटवारे के लिहाज से जो फरीदाबाद की स्थिति है वह यह है कि हमारे यमुना, आगरा कैनाल और गुड़गांव कैनाल से जो फरीदाबाद को पानी मिलता था पहले एग्रीमेंट के मुताबिक वह दो हिस्से हुआ करता था। लेकिन आज स्थिति यह है कि हमें केवल 200 क्यूसिक से ज्यादा पानी नहीं मिलता है।

श्री अध्यक्ष : महेन्द्र प्रताप सिंह जी इस बारे में सदन में नॉन आफिशियल रेजोलूशन पर पहले ही चार घण्टे की डिसकशन हो चुकी है। बार-बार एक ही बात को रिपीट करना ठीक नहीं।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, शायद इसका समाधान संभव न हो। लेकिन दूरगामी स्टैप्स अगर हम लें तो जिन एरियाज में पानी की कमी है वह मेवात का इलाका है, महेन्द्रगढ़ का इलाका है, फरीदाबाद का इलाका है। मेवात का इलाका तो पहाड़ के नजदीक है जहां पानी की कमी है। इस बारे में सरकार अपने प्रयास कर रही है लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है जैसा कि अभी राजस्थान का जिक्र आया था वहां इन छोटे-छोटे डैम्ज की संख्या बढ़ा दी गई है। बरसाती पानी के सदुपयोग के लिए क्या सरकार कोई ऐसी स्कीम बना रही है जिससे उस एरिया खास तौर से पहाड़ की तलहटी में पानी इकट्ठा हो जाए और वहां की जमीन की रिचार्जिंग भी हो जाए और उस एरिया को पानी भी दिया जा सके? जो यमुना का पानी है इसके लिए पलवल में, हसनपुर में या कहीं भी चैक डैम्स बनाए जाएं ताकि फालतू पानी का इस्तेमाल किया जा सके और समस्या का समाधान पूरी तरह से हो सके। अध्यक्ष महोदय, अब मैं, ग्राम उत्थान के विषय में कुछ कहना चाहूंगा। ग्रामीण प्राधिकरण बनाया गया है। उसने काम करना शुरू किया है या नहीं इस बारे में मुझे नहीं पता लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि गांव वालों का शहरों की तरफ इसलिए अट्रैक्शन है कि शहर में सुविधाएं हैं, एजुकेशन है, इसलिए वे गांव छोड़कर शहर की तरफ भागते हैं। मेरा सुझाव है और मैंने पहले भी एक आध बार यह सुझाव दिया है कि उन गांवों को विशेषकर जो शहर के नजदीक हैं और जो गांव शहर से दूर भी हैं, जिनकी आबादी 10 हजार की है उन गांवों को कालोनियों के रूप में, ऐसी संस्थाओं के रूप में डिवैल्प किया जाए कि वहां के लोगों को गांव में ही सभी सुविधाएं मिल जाएं। शहरों की तरफ बढ़ावा होने की वजह से शहरों की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और पोल्यूशन, ट्रैफिक और क्राइम जैसी समस्याएं बहुत ज्यादा पैदा हो रही हैं। शहरी विकास के लिए सरकार ने कमेटीज को 240 करोड़ रुपया दिया है। फरीदाबाद के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत 1203 करोड़ रुपये का प्लान पास किया गया है। इसके विषय में मैं थोड़ा जरूर कहना चाहूंगा। वैसे तो इस बारे में मैंने सवाल भी किया था। फरीदाबाद और आस-पास के शहरों को इस योजना में इसलिए लिया गया है क्योंकि इनकी स्थिति दिल्ली के नजदीक होने के कारण काफी खराब हो रही है और बहुत बदतर होती जा रही है। सैंट्रल गवर्नमैंट भी इसके नवीकरण के लिए पैसा दे रही है और स्टेट भी इसमें शामिल हो रही है। इन 3 वर्षों में काम भी किये गए हैं इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके लिए सीवरेज, पानी की व्यवस्था, सड़कें आदि डिवैल्पमैंट के काम शुरू हुए हैं लेकिन हमें इन कामों की तरफ ध्यान देना होगा नहीं तो सरकार का विकास वहीं का वहीं रुक जाएगा। बल्लभगढ़, एन०आई०टी० और मेवला महाराजपुर की आबादी बहुत ज्यादा है और इन शहरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनअथोराइज्ड कालोनियों की है। इन अनअथोराइज्ड कालोनियों की आबादी अथोराइज्ड कालोनियों की आबादी से दो गुना है। अगर हम इन अनअथोराइज्ड कालोनियों को पास करके डिवैल्प नहीं करेंगे तो इस नवीकरण की स्कीम का कोई फायदा नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, झुग्गी-झोंपड़ियों की संख्या 30 हजार से ज्यादा है इसलिए हमें उनके लिए समग्र रूप में एक इकट्ठी योजना तुरन्त बनानी होगी। हाऊसिंग बोर्ड और जो दूसरी एजैन्सियां हैं वे वन-रूम सैट बनाकर उन झुग्गी-

[श्री महेन्द्रप्रताप सिंह]

झोपड़ी वालों को इसमें शिफ्ट कर दें क्योंकि वे लोग इसके लिए पैसा भी देने के लिए तैयार हैं। इससे फरीदाबाद की सूरत और सीरत दोनों बढ़िया हो जाएंगी। मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि सरकार की नीयत भी ठीक है, नीति भी ठीक है और नेतृत्व भी ठीक है तथा किसी बात की कोई कमी नहीं है। पहली बार यह महसूस किया जा रहा है कि 3 सालों का बजट इतना अधिक बढ़ा है तथा विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन जरूरत इस ओर ध्यान देने की है कि जो कुछ भी हम दे रहे हैं, जितनी भी योजनाओं पर हम पैसा खर्च कर रहे हैं वह सही सलामत रूप से लगे और ठीक जगह तक पैसा पहुंचे। यह मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पिछली बार इसी हाउस में हमने मुलाना जी से और सरकार से कहा था कि खेड़ी कलां में डाइट की बिल्डिंग बहुत समय से बनी पड़ी है, इसको शुरू करवा दें तो उन्होंने यह कहा था कि इस सैशन में हम इसको शुरू करवा देंगे लेकिन अध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वह डाइट की बिल्डिंग आज एक साल के बाद भी ऐसे ही खाली पड़ी है। मांगेराम जी बैठे हैं आज इनके पास ये डिपार्टमैंट है मैं इनको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय ने दो वर्ष पहले ऐलान किया था कि इस डाइट की बिल्डिंग में वोकेशनल एजूकेशन तुरन्त शुरू की जाए। उनकी काम करने की चाह है, उनकी नीयत है इसलिए उन्होंने यह आदेश दिया था। लेकिन आज भी खेड़ी कलां की वह डाइट की बिल्डिंग खाली पड़ी है, पिछले सैशन में कहा गया था कि इसको चालू कर देंगे लेकिन वह अभी तक शुरू नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जो सरकार की योजनाएं हैं, वह अगर पूरी न हों तो वे सरकार की छवि पर बुरा असर डालती हैं और इस बात का फायदा उठाकर विपक्ष के लोग सरकार की छवि को खराब करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट की हिमायत करते हुए अपील करता हूं कि पूरा सदन सर्वसम्मति से इस बजट को पास करे। धन्यवाद।

श्रीमती अनीता यादव (साल्हावास) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं और आशा करती हूं कि आप मुझे बोलने के लिए 20 मिनट का समय देंगे। पिछली सरकार के समय में, मैं अकेली अपनी पार्टी की महिला विधायक थी लेकिन मुझे सदन में बोलने का अवसर नहीं दिया जाता था। अध्यक्ष महोदय, मैं बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं बजट पर चर्चा करूं उससे पहले एक बात कहना चाहूंगी कि एक बार एक नम्बरदार और किसान दोनों के दोनों तहसीलदार के पास गये। नम्बरदार ने तहसीलदार को कहा कि तहसीलदार साहब किसान का लोन पास कर दो। नम्बरदार किसान की अप्रोच करने के लिए उसके साथ गया था। तहसीलदार ने नम्बरदार से पूछा कि नम्बरदार तू बता किसान का लोन पास करूं या न करूं। नम्बरदार ने तहसीलदार को कहा कि किसान के पास कोठी है, गाड़ी है और सबकुछ है। इस पर तहसीलदार ने कहा कि यदि किसान के पास सबकुछ है तो इसको किस बात का लोन मिलेगा। बाहर आकर किसान ने नम्बरदार से कहा कि भाई तू मेरी अप्रोच करने के लिए गया था या तू मेरा दुश्मन है जो मेरा

लोन पास नहीं होने दिया। इस पर नम्बरदार ने किसान को कहा कि कोई बात नहीं तीन-चार दिन बाद दोबारा तहसीलदार के पास चलेंगे। तीन दिन बाद दोनों फिर से तहसीलदार के पास चले गये। तहसीलदार ने उनसे पूछा कि बताओ किस काम से आये हो। नम्बरदार ने कहा कि लोन पास करवाने आये हैं। तहसीलदार ने नम्बरदार को कहा कि तीन दिन पहले तो किसान के पास कोठी, गाड़ी और सबकुछ था आज क्या हो गया? इस पर नम्बरदार ने कहा कि साहब तीन दिन में ऐसी मार पड़ी जो कभी नहीं पड़ी थी और सब कुछ मलियामेट हो गया। अध्यक्ष महोदय, ऐसा ही हाल चौटाला जी की सरकार के समय में लोगों का हुआ करता था कि तीन दिन में ही लोगों का सबकुछ लुट जाता था। जिस समय चौटाला जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय उनका बेटा कहता था कि जो विधायक उनकी शरण में नहीं आयेगा उसको वे कूटेंगे। जो छोड़ गये वे तो ठीक रहे लेकिन जो उनके साथ रहे वे आज भी चुपचाप बैठे हैं। उस समय ओम प्रकाश चौटाला जी कहा करते थे कि जब तक जीऊंगा तब तक मुख्यमंत्री रहूंगा लेकिन हमारे मुख्यमंत्री इस तरह की गलत बातें नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, अब मैं बजट की बात करना चाहूंगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने बहुत अच्छा बजट प्रदेश की जनता को दिया है। इस बजट से प्रदेश आगे की तरफ जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं बिजली के बारे में बात करना चाहूंगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसी से वायदा नहीं किया था कि वे किसानों के 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ करेंगे लेकिन उन्होंने सरकार बनते ही एक कलम से किसानों के 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ करके प्रदेश के किसानों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। 1600 करोड़ रुपये बोलने में आसान लगता है लेकिन इस जिम्मे को उठाना बहुत बड़ी बात थी जिसको हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश के किसानों के हित में उठाया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देती हूं और मुख्यमंत्री जी की शख्सियत में एक लाईन कहना चाहूंगी कि —

धीरे-धीरे रे मना, धीरे-धीरे रे मना, धीरे सबकुछ होय,
माली सींचे बाग को रुत आए फल होय।

अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने हमें प्रदेश में बड़ी गली-सड़ी व्यवस्था बिजली की दी थी लेकिन हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने प्रदेश में बिजली प्लांट लगाने की तरफ विशेष ध्यान दिया है और हमारे वित्त मंत्री महोदय ने भी इसके लिए पूरा पैसा मुहैया करवाया है। हमारे झाड़ली में 1500 मैगावाट का इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है जिससे प्रदेश को 750 मैगावाट बिजली मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय अपने प्रदेश में ही बिजली पैदा करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं जबकि पिछले मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला के समय में प्रदेश में बिजली उत्पादन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। चौटाला जी की सरकार नहीं बनी थी तो उस समय वे लोगों को कहा करते थे कि तुम बिजली के बिल मत भरो, हमारी सरकार आयेगी तब न मीटर होगा और न ही मीटर रीडर होगा। उसके बाद उनकी सरकार भी

[श्रीमती अनिता यादव]

बनी लेकिन उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण जहां हमें 750 मैगावाट बिजली अपने ही प्रदेश में झाड़ली के थर्मल पॉवर प्लांट से मिलेगी वहीं मेरे हल्के के मातनहेल गांव में भी 1320 मैगावाट का थर्मल पॉवर प्लांट लगाने की सरकार की योजना है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के लोगों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के तहत 232731 कनैक्शन दिए जायेंगे और हमारी सरकार की 2 अक्तूबर, 2006 से एक स्कीम चल रही है जिसके तहत गरीब लोगों को दो सी०एफ०एल० बल्ब मुफ्त दिए जा रहे हैं, जो कम बिजली खाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के साहसिक कदम उठाकर हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदेश के लोगों को बिजली मुहैया करवाने की कोशिश की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगी। मेवात के बारे में मेरे भाई जिक्र कर रहे थे कि मेवात की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं मेरे साथी को बताना चाहूंगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी फूड प्रोसैसिंग की बात करते हैं या कोई और बात होती है तो वे मेवात क्षेत्र को चुनते हैं ताकि वहां पर शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितना पैसा मेवात में जाता है, इस बारे में आप सभी जानते हैं। शिक्षा के विस्तार के बारे में मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पुत्र माननीय दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की एक सोच है। वह बाहर से पढ़कर आये हैं और बाहर सर्विस करके आये हैं। प्रदेश में इससे पहले शिक्षा की स्थिति जो थी, वह गली-सड़ी व्यवस्था चौटाला जी की गवर्नमैंट ने दी थी। आप जानते हैं कि चौटाला साहब खुद तथा उनके बेटे अण्डर मैट्रिक हैं। उन्होंने हूज़ हू में अपने आपको बी०ए० तक शिक्षित दिखाया हुआ है। उनसे मैं कहना चाहूंगी कि पढ़ाई और शालीनता के मामले में अगर कुछ देखना और सीखना है तो उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के बेटे चौधरी दीपेन्द्र सिंह हुड्डा से शिक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने जगह-जगह पर जाकर खुद शिक्षा का विस्तार किया। वे सोच रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे भाई-बहन और हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो माननीय दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने जगह-जगह पर स्वयं जाकर इस प्रकार के प्रोग्राम बनवाये जिससे शिक्षा का चहुंमुखी विकास हो सके। इसके अतिरिक्त मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि पिछले 2007-08 के बजट में शिक्षा के लिए 290 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जो कि इस बार के 2008-09 के बजट में बढ़ाकर 540 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार से कुण्डली (सोनीपत) में राजीव गांधी एजूकेशन सिटी और मुरथल में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। इसके साथ ही राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना के तहत पिछले वर्ष के बजट में सरकारी स्कूलों की छात्राओं के लिए जो 50 हजार रुपये का प्रावधान किया गया था उसे इस बार बढ़ाकर एक लाख किया गया है। इसलिए चौटाला साहब की पार्टी के सदस्यों को विशेषतौर से जो अनपढ़ों जैसी बातें करते हैं कि इस सरकार ने मेवात की भलाई पर कोई ध्यान नहीं दिया उनको मैं यह बताना चाहूंगी कि प्रत्येक जिले में चाहे वह मेवात का जिला हो, चाहे पंचकूला का जिला हो या और कोई दूसरा जिला हो प्रत्येक जिले में एक मॉडल संस्कृति स्कूल हमारी सरकार ने खोला है और सर्व शिक्षा अभियान के

तहत 6-14 वर्ष की लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान करके इस मद के लिए एक लाख रुपये की राशि बजट में रखी गई है। इसी प्रकार से एक लाख रुपये का पुरस्कार उन ग्राम पंचायतों को भी दिया जायेगा जो ज्यादा से ज्यादा छात्रों को उसमें दाखिल करवायेंगी और मेवात में छात्रों को वर्दी, खाना, कापी-किताबें, बस्ता, पैंसिलें सभी कुछ निःशुल्क दिया जा रहा है। इसके बाद भी अगर वहां बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो इसके लिए अभिभावकों को भी उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए न कि वे उस लाईन पर चलें जो लाईन चौटाला जी ने खींची थी। इसी तरह से वह खानदानी रिवाज़ जो चौटाला जी के रिवाज़ थे अनपढ़ता और क्रूरता के उनसे इनको बचना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहूंगी कि पिछली सरकार के दौरान विधान सभा सैशन में किस प्रकार की घटिया मिसालें पेश की जाती थी? किस प्रकार का घटिया व्यवहार विपक्षी सदस्यों के साथ किया जाता था और किस प्रकार के भद्दे इशारे करके विपक्षी सदस्यों को बोलने से रोका जाता था। इसके साथ ही बहुत से सदस्य ऐसे भी थे जो शराब पीकर सदन में आते थे और कुछ तो रात को इतनी शराब पी लेते थे कि सुबह तक भी उनका नशा ढ़ीला नहीं पड़ता था। कुल मिलाकर उन्होंने यहां पर अनपढ़ टोला इकट्ठा किया हुआ था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि ये जो शराब के ठेकों के आबंटन की प्रक्रिया चल रही है इसमें वे चोर और बदमाश लोगों को ठेका न देकर शरीफ और बढ़िया लोगों को ठेके दें। इसके साथ-साथ मैं सिंचाई के विषय में भी कहना चाहती हूं क्योंकि यह भी मेवात इलाके से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हमारे एक साथी हैं जो कि मेवात से हैं, उनको मैं विशेषतौर पर अर्ज़ करना चाहती हूं कि आप अपनी ये बिना मतलब की बातें छोड़कर हमारी बात सुनो और हमारे समर्थन में माननीय मुख्यमंत्री जी की सराहना करो तब जाकर आपकी बात बनेगी! अब मैं कानून व्यवस्था के बारे में बात करना चाहती हूं। पिछली सरकार के समय में जब रैलियाँ होती थी तो तीन दिन पहले ही प्राईवेट बसों और जीपों की आर०सी० जमा करवा ली जाती थी और बसों और जीपों को जब्त कर लिया जाता था। रैली के तीन दिन बाद ही उनके कागज वापिस किये जाते थे। लेकिन अभी हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के 60 हजार करोड़ रुपये के कर्जे माफी के लिए माननीय सोनिया गाँधी जी का धन्यवाद करने के लिए की गई रैली में हिस्सा लेने के लिए हम दिल्ली के रामलीला ग्राऊंड में गये थे। आज कोई भी जीप वाला भाई या बस वाला भाई यह बता दे कि हमारी आर०सी० या गाड़ी जब्त की गई हो। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार के तीन साल के कार्यकाल में प्रदेश में आज हर तरफ अमन चैन है। ये साथी मेवात की बात कर रहे थे। इनको तो फक्र होना चाहिए कि देश की पहली मोबाइल कोर्ट मेवात के पुन्हाना में शुरू की गई है। इस ऐतिहासिक फैसले के लिए इनको तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने जो भय मुक्त प्रशासन देने का वायदा किया था वे उस पर खरे उतरे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि या तो गुण्डे प्रदेश को छोड़ कर भाग जायेंगे या जेल में होंगे बाकि उनके लिए हरियाणा में कोई जगह नहीं है। आज हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं, आजादी से घूम सकते हैं। यह सब अमन चैन हुड्डा साहब के आशीर्वाद से हुआ है। पिछली

[श्रीमती अनिता यादव]
सरकार के मुख्यमंत्री चौटाला जी जब किसी के घर खाने पर या चायपान पर जाते थे तो वहां भी जाड़ बजाई के नाम पर पैसे लेते थे, वे तो किसी के घर अगर चाय पीने भी जाते थे तो भी कहते थे कि तेरे घर चाय पीने आ रहा हूं कौन सी गाड़ी की चाबी दोगे।

श्री अध्यक्ष : अनिता जी जाड़ बजाई से आपका क्या मतलब है?

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, जाड़ बजाई से मेरा तात्पर्य दाँत घिसाई से है। चौटाला जी कहते थे कि मैं आपके घर खाना खाने आ रहा हूं मुझे कितने पैसे दोगे। किसी के घर पर खाना खाने या चाय पीने तो हमारे सांसद दीपेन्द्र जी भी जाते हैं। हमारे हल्के में कई जगह गये हैं लेकिन कोई एक आदमी भी बता दे कि उनसे पैसे लिए हों। अगर आप लोगों का इसी तरह से सहयोग और कॉर्डिनेशन रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हम कह सकेंगे :—

हरा-भरा हरियाणा सै यो, उन्नतशील बनाना सै यो,
काम करांगे चालो खेत में, सोना निपजैगा बालू रेत में।

इसी प्रकार से मैं सिंचाई के बारे में विशेष रूप से एक बात कहना चाहूंगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे बड़े भाई कैप्टन अजय सिंह यादव को सिंचाई मंत्री बनाया जिन्होंने पानी का समान बटवारा करने की कोशिश की है। चौटाला जी ने पहले कुछ नहीं किया। वे पेड़ काट देते थे और रोड जाम कर देते थे। पहले मुख्यमंत्री चौटाला जी तो केवल ढाई जिलों को पानी देते थे लेकिन हमारे मुख्यमंत्री माननीय हुड्डा साहब का कहना है कि अगर एक रोटी होगी तो उसके हिस्से करके सभी को बराबर बांट देंगे, अकेले नहीं खायेंगे। उसी बात को बुलन्द करते हुए उन्होंने एक बात कही थी :—

खुदी को कर बुलन्द इतना कि हर तकदीर से पहले,
खुदा बन्दे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।

बी०एम०एल० हांसी-बुटाना लिंक नहर का निर्माण कार्य जोरों पर है और जल्दी ही वह पूरा हो जायेगा जिससे 16 जिलों को पानी मिलेगा। लेकिन हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं कि हम इस नहर को बनने नहीं देंगे और अगर यह बन गई तो हम इसको आंट देंगे। हमारे ये साथी कह रहे थे कि मेवात के लिए कुछ काम नहीं हुए हैं। मेवात के लिए जो नहर बन रही है उस पर 267 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने बड़ी फिराखदिली से मेवात के लिए काम किया है। इनको तो सोचना चाहिए कि इनकी बिना पानी की जमीनों के रेट आज बहुत ज्यादा हो गये हैं। पहले इनकी जमीन 2 लाख रुपये तो क्या 20-20 हजार रुपये प्रति एकड़ में खुले बिकती थी और जब से मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार आई है तो एक-एक आदमी करोड़पति बन गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रैक्टिकल बात कह

रही हूं। जो लोग हरे रंग की पगड़ी बाँध कर घूमते थे उन्होंने वह पगड़ी फाड़ फैंकी और वे कहते हैं कि हमें तो चौटाला ने लूट खाया था। हम तो अब करोड़पति बन गये हैं। आज हमारे पास गाड़ियाँ हैं और चारों तरफ अमन चैन कायम है। इसी कारण आज उन लोगों ने चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है। उनकी जमीनें बिक रही हैं। हमारे क्षेत्र में जो कोसली सब-स्टेशन है वहां की जमीन सवा करोड़ रुपये प्रति एकड़ में बिकी है जबकि वहां पर 7-8 लाख रुपये प्रति एकड़ का रेट था। माननीय स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। वैसे तो 2-4 टॉपिक और थे जिन पर मैं बोलना चाहती थी। माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में जो बजट पेश किया है उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट पेश किया है और अपने बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा है। आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूं। जयहिन्द!

श्री हर्ष कुमार (हथीन) : अध्यक्ष महोदय, 18 तारीख को माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट अनुमान सदन में पेश किये हैं मैं उनकी सराहना करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं। जिस तरह से बजट अनुमानों में प्राथमिकताएं दर्शाई गई हैं उनसे यही लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री और वित मंत्री जी ने इस प्रदेश की तरक्की के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे बहुत ही प्रयत्नशील हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस दिन उनका यह मकसद पूरा होगा, उस दिन हरियाणा प्रदेश दुनिया के आधुनिकतम शहर के तौर पर पहचाना जाएगा। इसका मकसद पूरा होने के बाद हरियाणा प्रदेश दुनिया में अपना अलग महत्व बनाएगा और अपनी अलग पहचान बनाते हुए आगे बढ़ेगा उसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए थोड़ा समय दिया है इसलिए मैं अपनी बात को छोटा करने की कोशिश करूंगा। बजट में गरीब और दलित लोगों के लिए सरकार ने जो प्रावधान रखे हैं वे सराहनीय हैं। बहुत से लोग आज जाट और गैर जाट की राजनीति करने में लगे हुए हैं। जिस तरह से कुछ लोग जातिवाद के नाम पर नफरत फैला कर देश, प्रदेश और समाज को तोड़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं इस सरकार ने उन कोशिशों पर विराम लगा कर उन सब कोशिशों पर पानी फेरते हुए उन्हें नाकाम किया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में प्रदेश के हर वर्ग का बराबर ध्यान रखा है। सरकार ने गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, इण्डस्ट्रियलिस्ट का जिस तरह से ध्यान रखा है उससे आज देश को एक नई दिशा मिली है। चाहे कोई किसी भी पार्टी का सदस्य है उनको इस बात से सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने अपने राज में जो कारनामे किए, जो गलतियां की हैं उनके लिए पश्चाताप करें और इस नई पहल से सीख लेकर अपने आपको इस नये परिवेश में ढालने की कोशिश करें। उस नये परिवेश के अनुसार अपने प्रदेश की, अपने देश की सेवा करने में लगें। स्पीकर सर, शिक्षा आज की तरक्की का आधार है चाहे देश की तरक्की है और चाहे प्रदेश की तरक्की है और चाहे किसी परिवार की

[श्री हर्ष कुमार]

तरक्की है वह शिक्षा के बिना नहीं हो सकती है। आज स्कूल अपग्रेड करके शिक्षकों और वैज्ञानिकों को जिस तरह से सहूलियतें हमारी सरकार ने दी हैं उससे हमारी सरकार की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता की झलक मिलती है। जिस तरह से स्कूलों को अपग्रेड किया है और विश्वविद्यालयों में नई-नई तकनीकें ऐड करके उनके नवीनकरण की तरफ ध्यान दिया है उससे हमारा प्रदेश बहुत ही तरक्की करेगा, आधुनिक दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा और यहां का नौजवान आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, सरकार का और माननीय वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि इस दिशा में उन्होंने मेवात क्षेत्र का पूरा ध्यान रखा है। मेवात क्षेत्र के हर पोलिटैक्नीकल कॉलेज में सीटें दुगुनी की हैं, हर आई०टी०आई० में सीटें दुगुनी की हैं और एक ऐसा असम्भव काम किया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। किसी के जेहन में ऐसी बात नहीं थी कि इस तरह के काम भी हो सकते हैं। स्पीकर सर, उटावड़ पोलिटैक्नीकल कॉलेज में सीटों की संख्या डबल कर दी गई है जिसमें से 50 प्रतिशत सीट्स मेवात जिले के लिए रिजर्व रखी गई हैं और 10 प्रतिशत उटावड़ के लिए रिजर्व रखी हैं, जिनकी पंचायत ने वहां पर जमीन दी थी। मुख्यमंत्री जी ने जो वहां के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यशैली अपनाई है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, बिजली के लिए जिस तरह से इन्होंने उत्पादन का लक्ष्य रखा है और जब यह सरकार उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी तो हरियाणा में तरक्की की एक नई क्रान्ति सी आ जाएगी। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने किसानों के जो बिल माफ करने का कार्य किया है उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसी तरह से किसानों के ट्यूबवैल्ज के लिए जो कार्यप्रणाली लाए हैं उससे किसानों को बहुत फायदा होगा। पहले जो किसान रात को कीड़े-मकौड़ों से डरता हुआ काम करता था उसको अब डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको पूरी बिजली मिलेगी। इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि हमारे हल्के में कई जगहों पर नहरें नहीं हैं, ट्यूबवैल्स नहीं हैं और जहां पर हैं वहां पर खारा पानी है। हमारे बहुत से लोग वहां पर डीजल इंजनों से, ट्रैक्टरों से भराई करते हैं। उनके लिए भी सरकार किसी न किसी तरीके से प्रति एकड़ के हिसाब से बोनस देने का प्रावधान करे। अगर सरकार ऐसा करती है तो उन लोगों पर बहुत एहसान होगा। अध्यक्ष महोदय, आज यह जो बिजली की तारें और कंडैक्टर्ज बदलने का काम किया जा रहा है यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी आज कहीं पर भी चले जाएं तो इनको लोग दुआएं देते हैं। लेकिन जो पहले वाले मुख्यमंत्री थे और वे कहीं पर चले जाते थे तो लोग उनको बद्दुआएं ही दिया करते थे। हमारे मुख्यमंत्री जी को आज इतनी दुआएं मिलती हैं जो आज से पहले किसी भी मुख्यमंत्री जी को नहीं मिली होंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष : हर्ष कुमार जी, आपके दो मिनट रह गए हैं। आपने 11.55 पर बोलना शुरू किया था। आप जल्दी कन्कल्यूड करें।

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, अगर आप कहेंगे तो मैं अभी खत्म कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, किसानों की जहां तक बात है तो मैं इस बारे में यह कहना चाहूंगा कि अगर किसान खुशहाल होगा तो मजदूर भी खुशहाल होगा क्योंकि उसको उसकी मजदूरी मिलेगी। अगर किसान खुशहाल होगा तो व्यापारी भी खुश होगा क्योंकि उसको ग्राहक मिलते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने 1600 करोड़ रुपए के किसानों के बिजली के ऋण माफ किए हैं, गेहूं पर 100 रुपए का बोनस दिया है और गन्ने के रेट भी बहुत अच्छे बढ़ाए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जो कोआप्रेटिव सैक्टरों में ब्याज माफ करने का कार्य किया है वह अपने आप में एक मिसाल है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि पहले की सरकार के समय में स्टेट के मुख्यमंत्री जी सैन्टर के हिसाब से चलते थे और उनके हुक्म से चलते थे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है और ऐसा करके इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है। पहली दफा किसी मुख्यमंत्री की सोच के अनुसार सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने काम किया है। जो 60 हजार करोड़ रुपये के कर्जे माफ किए हैं यह हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच और इनकी कार्यशैली के अनुसार ही सैंट्रल गवर्नमैंट ने माफ किए हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं। इसके अलावा जो नये कृषि उपकरणों की खरीद पर 50 परसैंट की सब्सिडी सरकार ने दी है उसके लिए भी मैं इनको धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, बजट में हर क्षेत्र में सहूलियतें दी गई हैं चाहे पी०डब्ल्यू०डी० हो, चाहे सिंचाई हो या चाहे ऐजूकेशन हो, सारी चीजों पर सहूलियतें बजट में दी गई हैं। वाकई में यह बजट सराहनीय है। अध्यक्ष महोदय, मैं बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जिस तरह से वित्त मंत्री जी का यह चौथा बजट है तो यह सरकार, मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी दसियों, बीसियों बजट हरियाणा के इस सदन में पेश करते रहेंगे। मुझे ऐसी आशा है और मेरी उनको शुभकामनाएं भी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी चीजें छोड़कर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अच्छे कामों को करने में बाधाएं आती हैं। सत्ता में होते हुए भी अच्छे नेताओं को, अच्छे मुख्यमंत्रियों को अच्छा काम करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी भी संघर्ष से गुजर रहे हैं। यह संघर्ष पिछली सरकार का दिया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने सबसे ज्यादा योगदान करप्शन में दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जिसकी जैसी नीयत होती है वह उसी के अनुसार काम करता है। मुख्यमंत्री जी की, वित्त मंत्री जी की और सरकार की जो नीयत है वह उसके अनुसार ही काम कर रही है इसलिए आज इनकी नीयत की वाहवाही हो रही है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकारों ने सिवाय नौकरियों के नाम पर पैसा लेने के और कुछ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब मानेंगे कि कितने ही गरीब लोग ऐसे हैं जो दो, तीन, चार लाख रुपये नौकरियों के लिए देकर लुटे बैठे हैं। उनको आज तक न नौकरी मिली है और न ही पैसा वापस मिला है। वे धक्के खा रहे हैं। पिछली सरकार के दौरान कब्जे करना एक आम बात थी। अगर कोई अच्छा मकान देख लिया या कोई अच्छा प्लाट देख लिया तो वे उस पर कब्जा

[श्री हर्ष कुमार]
कर लिया करते थे। इसी तरह से उनके छोटे वर्कर्ज भी ऐसा ही करते थे जब उनसे कहते थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो तो उनका कहना था कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े-बड़े कब्जे कर रहे हैं तो क्या हम छोटे कब्जे भी न करें। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज हमारे मुख्यमंत्री जी की सलाह केन्द्र सरकार भी मानती है। इसलिए ही मैं कह रहा हूं कि आज अगर करप्शन कोई रोक सकता है तो वह हमारे मुख्यमंत्री जी ही रोक सकते हैं। आज न कोई नेता पैसा ले सकता है, न कहीं किसी का अपहरण हो सकता है, न डकैती हो सकती है और न रिश्वतबाजी हो सकती है। मान्यवर, जो सरकार का लेनदेन है वह कैश में न होकर, चैक और ड्राफ्ट में हो सकता है। चाहे पांच रुपये हों या चाहे दस रुपये हों अगर आज हम सारे नोटों का प्रचलन खत्म कर दें तो इससे भी करप्शन को रोकने में मदद मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, दो रुपये, पांच रुपये, दस रुपये के सिक्के चला दिए जाएं और 100 रुपये, 500 रुपये, एक हजार रुपये के नोटों का प्रचलन बंद कर दिया जाए जाना चाहिए और सीधे बैंकों से ही लेनदेन शुरू किया जाना चाहिए। लोगों के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड बनवा दिए जाने चाहिएं। बड़े लोगों के तो ये बन ही रहे हैं अगर इसी पद्धति को छोटे लेवल पर भी लागू कर दिया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी पढ़ा लिखा देश का नौजवान बेरोजगार नहीं मिलेगा क्योंकि उनको बैंकों में नौकरियाँ मिल जाएंगी। उसके बाद कहीं डकैती नहीं होगी, कहीं राहजनी नहीं होगी, किसी को तिजोरी रखने की जरूरत नहीं होगी। नोटों के बंडल अगर बैंकों में ही होंगे तो यह स्थिति हो जाएगी कि इनको लेने वाला कोई नहीं होगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। सर, मान लो कि जब नोटों के बंडल अगर रख देंगे और यदि वहां से चौटाला साहब गुजर रहे हों तो क्या वे चुपचाप वहां से निकल जाएंगे?

श्री हर्ष कुमार : स्पीकर साहब, मैं एक ही बात कह सकता हूं कि उन नोटों के ढेर को देख कर वे रह तो पाएंगे नहीं लेकिन अगर कानून बन जाएगा तो चौटाला साहब ले भी नहीं जा सकते और अफसोस में गम में वे जा सकते हैं और गम में हो सकता है कि वे कोई उल्टा सीधा कदम उठा बैठें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, चौधरी साहब, अब आप बैठ जाएं।

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय बैठे हुए हैं उनको आज इस चीज के बारे में पहल अवश्य करनी चाहिए क्योंकि अगर करप्शन रहेगी तो ऐसे नेताओं को, ऐसे मुख्यमंत्रियों को, ऐसी सरकारों को ऐसे बजट को अमली जामा और असली जामा पहनाने में परेशानियां उठानी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा इसलिए इसका एक ही तरीका है कि सब कुछ जितना आपका बजट है वह सही सलामत रहे। नोटों का प्रचलन बंद कर दें और बैंक से सीधा लेन

देन रहे तो ही करप्शन पर काबू पाया जा सकता है। जहां ये अच्छा काम कर रहे हैं वहीं बहुत से राजनैतिक लोग देश में नफरत की राजनीति कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको बोलते हुए 16 मिनट का समय हो गया है। अब आप बैठ जायें। बोलने के लिए तो ऐसे-ऐसे सदस्य थे कि दो दो घंटे का समय लेते और आप को बोलने का मौका ही न मिलता। लेकिन व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है।

श्री हर्ष कुमार : ठीक है अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को मुबारकवाद देता हूं कि इनकी सरकार अच्छा काम कर रही है। मैं इनका समर्थन कर रहा हूं और यह आशा कर रहा हूं कि आगे भी अच्छा काम करेंगे। आपका भी मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया चाहे एक मिनट ही फालतू दिया लेकिन दिया जरूर।

श्री अध्यक्ष : आपको एक मिनट नहीं सोलह मिनट का समय दिया गया है।

श्री बलवंत सिंह सढौरा (अनु०जा०) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट में आंकड़े दर्शाये हैं उनको देखने से ऐसा महसूस होता है कि प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर के जो मेन मुद्दे हैं उन पर बजट की मदें पिछले साल से इस साल में कम की हैं। यह मेरे कहने की बात नहीं है बजट में जो लेखा-जोखा है उसके हिसाब से है। मैं वित्त मंत्री जी का एक बात के लिए जरूर धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने अपने पहले बजट में एक बात कही थी कि हमें विरासत में जो वित्तीय प्रबंधन या सिस्टम मिला है वह बहुत बढ़िया है। यह इन्होंने माना था। इसके कारण चाहे हमारी सरकार को इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा पर प्रदेश को वैट रूपी ऐसा सिस्टम दिया था जिससे सरकार को बहुत आमदनी हुई। उस आमदनी को चाहे जिस फील्ड में खर्च कर सकते हैं। उसके साथ जो बजट में बढ़ौत्तरी हुई, खजाने में पैसा आया उसका एक यही विकल्प था। हमारे आदरणीय श्री चौटाला साहब ने राजनीतिक नुकसान सहते हुए इस काम को पूरा किया और वित्तीय प्रबंधन के लिए यूनीफार्म फ्लोर रेट टैक्सिज को लागू किया इससे सारे प्रदेश में आमदनी का जरिया बहुत बढ़ा। इस वैट की चर्चा मेरे साथियों ने पहले भी की है पर जब यह वैट सिस्टम हरियाणा में लागू हुआ तब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही इसका बहुत विरोध किया था। जब यह वैट लगा तो कई तरह की चर्चायें और इफ एंड बट लगाये गये। इस सबके बावजूद आदरणीय श्री चौटाला साहब ने इसको लागू करके प्रदेश को एक सही दिशा दी। एक सुदृढ़ आर्थिक आधार दिया जिससे हमारा प्रदेश उन्नति और तरक्की की राह पर आगे आया।

श्री मांगे राम गुप्ता : इस प्रणाली के लागू होने से बजट में कितनी बढ़ौत्तरी हुई?

श्री बलवंत सिंह सढौरा : सर, 2004-2005 के प्लान बजट में 2705.16 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ था जो 36.99 प्रतिशत था, वर्ष 2005-2006 में 3769.7 करोड़ रुपये का जो कि 34.21 प्रतिशत था, वर्ष 2006-2007 में 4975.42 करोड़ रुपये का जो कि 34.21 प्रतिशत है। वर्ष 2007-2008 में 5998.76 करोड़ रुपये है जो 32 प्वायंट कुछ है। 7566.82 करोड़ रुपये इस वर्ष 2008-2009 में बजट अनुमानित है वे केवल 15.18 प्रतिशत रह गया है जो अच्छे इन्डीकेटर नहीं हैं। मेरे कहने की बात नहीं है यह बजट के आंकड़े हैं जो बजट पेश किया गया है ये इस प्लान्ड बजट के आंकड़े हैं। सर, नॉन प्लान एक्सपैंडीचर कम रखा जाए। उतना ही बजट अच्छा होता है। अगर हम देखें तो वर्ष 2007-2008 में वर्ष 2006-2007 की तुलना में 13999.5 करोड़ रुपये की बजाए 14951.28 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं जोकि 6.8 प्रतिशत अधिक है और वर्ष 2008-2009 में वर्ष 2007-2008 के मुकाबले 14951.28 करोड़ रुपये से बढ़कर 16645.01 करोड़ रुपये होने जा रहा है यानी बढ़ौत्तरी 10.12 प्रतिशत है जो ठीक नहीं है। इसी तरह से रैवेन्यू रिसीट्स लें उसमें वर्ष 2005-2006 में जहां कुल राजस्व प्राप्तियां 13853.31 करोड़ रुपये की थी वह वर्ष 2006-2007 में बढ़कर 17952.43 करोड़ रुपये हो गई क्योंकि उस समय सारे देश में वैट लागू हो चुका था। उसके उदाहरण एक साथ सामने आये और यह बढ़कर 30 प्रतिशत के करीब है जो बढ़िया बात थी जब सारे देश में वैट लागू हो गया और सारे इन्कम सोर्स सेफ हो गये। इसी प्रकार से वैट का न्यूट्रीलाईजेशन हो गया। वर्ष 2007-2008 में राजस्व प्राप्तियां 19629.69 करोड़ रुपये की हुई जो केवल गत वर्ष की अपेक्षा 9 प्रतिशत रह गई। वर्ष 2008-2009 में अनुमानित राजस्व प्राप्तियां जो नॉन प्लान एक्सपैंडीचर में दिखाई गई हैं उनमें फिर 9 प्रतिशत की वृद्धि है। स्पीकर सर, राजस्व प्राप्तियां केवल दो मदों से ही हरियाणा प्रदेश में होती हैं, एक तो वैट से दूसरे स्टाम्प ड्यूटी से। सत्ता पक्ष के मेरे सम्मानित साथी यह कह कर वाहवाही लूट रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश की मौजूदा सरकार ने एक प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी गांवों में और दो प्रतिशत महिलाओं के मामले में घटाई है। और ऐतिहासिक फैसला करार दे रहे हैं। सर, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में शहरी सम्पत्ति की रजिस्ट्री साढ़े सोलह प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत और गांवों की जमीन की रजिस्ट्री 12 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत की गई थी जो एक ऐतिहासिक फैसला किया था। वर्ष 2005-2006 स्टाम्प ड्यूटी का रेट उस समय बरानी जमीन का डेढ़ लाख रुपये प्रति एकड़ होता था और किसान की एक एकड़ जमीन की रजिस्ट्री नौ हजार रुपये में हो जाती थी। आज उस जमीन की कीमत कलैक्टर रेट के हिसाब से बढ़कर पांच लाख रुपये हो गई है और रजिस्ट्री की कीमत 5 प्रतिशत के हिसाब से 25 हजार रुपये प्रति एकड़ बनती है। चाही की जमीन की हमारे यहां कलैक्टर रेट के हिसाब से कीमत अढ़ाई लाख रुपये थी, जिसकी रजिस्ट्री 15 हजार रुपये में हो जाती थी। आज उसकी कीमत बढ़कर सात-आठ लाख रुपये प्रति एकड़ हो गई है जहां 5 प्रतिशत के हिसाब से उस जमीन की रजिस्ट्री 40 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से होती है। यह बात मैं नहीं कह रहा यह आंकड़े कह रहे हैं। एक बात और ऑन दी फलोर ऑफ दि हाउस कही जा रही है कि आज हरियाणा प्रदेश के हर एरिया में एक प्रतिशत और दो प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी कम हो गयी है इसको लेकर ये वाहवाही लूट रहे हैं। स्पीकर सर, ऐतिहासिक फैसला

तो वह था जिसमें स्टाम्प ड्यूटी को साढ़े सोलह प्रतिशत से आठ प्रतिशत और 12 प्रतिशत से 6 प्रतिशत किया गया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय और सदन के नेता का ध्यान एक और जरूरी बात की तरफ दिलाना चाहूंगा कि आज हरियाणा प्रदेश में आम आदमी का मौलिक अधिकार है कि उसके पास जो 100, 200 या 400 गज का प्लाट है, उसमें से वह अपनी जरूरत के मुताबिक 50 गज या 100 गज जमीन अपनी बेटी की शादी वगैरह के लिए बेचना चाहे तो बेच सकता है लेकिन आज की मौजूदा सरकार ने वे रजिस्ट्रियां बन्द कर दी। वह गरीब आदमी NOC लेने के चक्कर में मारा-मारा फिरता है लेकिन उसको NOC नहीं मिलती। वह गरीब आदमी 50 गज या 100 गज का प्लाट बेचकर अपना गुजारा करना चाहता था लेकिन रजिस्ट्रियां बन्द होने की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि लाल डोरे के अन्दर या शहरी म्युनिसिपल कमेटीज के अन्दर ऐसा नहीं होना चाहिए। 5-6 महीने पहले सरकार की तरफ से FCR साहब ने एक ओर्डिनैंस जारी किया कि शहर में रजिस्ट्रियां बिना NOC के होंगी, उसका लाभ किसको हुआ, क्या हुआ हमें पता नहीं लेकिन एक हफ्ते के अन्दर रजिस्ट्रियां बैक डेट से बन्द कर दी गई। यह अध्यादेश सरकार के पास है। सरकार कृपया बताने का कष्ट करे कि कौन सी ऐसी आफत आ पड़ी थी कि पहले वह रजिस्ट्रियां खोलनी पड़ी और फिर बन्द करनी पड़ी।

श्री अध्यक्ष : सढौरा जी, आपको बोलते हुए 10 मिनट हो गए हैं।

श्री बलवंत सिंह सढौरा : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे अब बैठने के लिए कहें तो मैं अभी बैठ जाता हूं। मैं 2-4 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के मित्रों ने चर्चा की कि हरियाणा प्रदेश इस राज के 3 वर्षों में पर-कैपिटा इन्कम में गोआ के बाद नम्बर एक पर है। लेकिन बजट को देखने से पता चलता है कि हरियाणा प्रदेश 2003-04 में भी गोआ के बाद पर कैपिटा इन्कम में नम्बर एक पर था। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं यह सच्चाई है और इसको हम झुठला नहीं सकते। ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस अगर हम यह कहें कि हमने कल परसों या दो-तीन सालों में हरियाणा स्टेट को नम्बर एक पर कर दिया तो यह ठीक बात नहीं है। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री महोदय स्पष्ट कर दें कि 2003-04 में हरियाणा पर कैपिटा इन्कम में गोआ के बाद नम्बर एक पर था या नहीं। यहां तक कि हमारी सम्मानित सदस्या पार्लियामैंट्री सैक्रेटरी मैडम शारदा राठौर ने गवर्नर एड्रैस पर अनुमोदन करते हुए कहा कि हरियाणा पर कैपिटा इन्कम में 13वें स्थान पर है।

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : सढौरा जी, इन्होंने पर कैपिटा इन्वैस्टमैंट की बात की थी।

श्री बलवंत सिंह सढौरा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक ग्रांट-इन-ऐड की बात है तो सरकार विभिन्न संस्थाओं को, म्युनिसिपल कमेटीज को, पंचायतों को, कॉलेज को और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनको ऐड देती है। यह ग्रांट वर्ष 2007-08 में 2828 करोड़ 96 लाख रुपये थी। 2008-09 में यह ग्रांट केवल 2246.27 करोड़ रह गई। किस की

[श्री बलवंत सिंह सढौरा]

ग्रांट कटेगी, किसकी ग्रांट बढ़ेगी यह बात तो वित्त मंत्री जी अपने जवाब में बता देंगे। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सब्सिडी की बात करना चाहूंगा। आज की मौजूदा सरकार गरीबों और किसानों के हित की बात करने का दावा करती है। यह बात ठीक है कि आज किसान का लागत मूल्य बढ़ गया है और उसको उचित दाम मिले इस बात के हम पक्षधर हैं। जहां किसान को अपनी फसल का उचित दाम मिले वहीं किसी भी बिरादरी से सम्बन्ध रखने वाला गरीब आदमी जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन बसर कर रहा है और जो गांव में रह रहा है सरकार उसको कम रेट पर खाने के लिए आटा, दाल और डालडा दे क्योंकि इन चीजों को खरीदना आज उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। क्या सरकार ने इस बारे में सोचा है कि उसको कम रेट पर ये सारी चीजें मिलें। वर्ष 2007-08 में सरकार ने जो सब्सिडी दी थी वह 3858.10 करोड़ की थी। वर्ष 2008-09 में यह सब्सिडी 2838.81 करोड़ रह गई। ये मैं बजट के आंकड़े बता रहा हूं। किस-किस की सब्सिडी कम होगी यह तो हमारे सुलझे हुए वित्त मंत्री जी अपने जवाब में ही बतायेंगे। अध्यक्ष महोदय, बजट के पेज-25 पर प्वाइंट 40 में लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के बाद पशुपालन आजीविका का मुख्य साधन है। यह बात हम भी मानते हैं कि पशुपालन से आम आदमी गुजारा कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सत्तापक्ष से जानना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में 8 पोस्टें पशुपालन विभाग में ज्वायंट डायरेक्टर की हैं जो पशुओं की देख-रेख और सारे सिस्टम को देखते हैं लेकिन उन 8 पोस्टों में से पिछले तीन साल से 7 पोस्टें खाली हैं। सरकार एक तरफ कहती है कि पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य साधन है और दूसरी तरफ पशुओं की देख-रेख करने वाले सात अधिकारियों की पोस्टें खाली पड़ी हैं। इसी तरह से पशु पालन विभाग में चण्डीगढ़ में एक डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट होती थी, जो पशुओं की सारी बीमारियों का सर्वे करता था और उनके इलाज के सुझाव भी देता था लेकिन डिप्टी डायरेक्टर की वह पोस्ट चण्डीगढ़ से बदलकर उसका हैड क्वार्टर नारनौल में कर दिया। इसके क्या कारण हैं कि उसका हैड क्वार्टर नारनौल बना दिया गया। यदि हैड क्वार्टर बदलना ही था तो बेरी में बना दिया जाता क्योंकि बेरी में साल में एक दफा पशुओं का मेला भी लगता है लेकिन पता नहीं नारनौल को हैड क्वार्टर क्यों बना दिया?

श्री अध्यक्ष : सढौरा जी, प्लीज अब आप बैठें। अब श्री हबीब-उर-रहमान जी बजट पर बोलेंगे।

श्री हबीब-उर-रहमान (नूंह) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी की देख-रेख में हमारे वित्त मंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए जो बजट सदन में पेश किया है यह वाकई में काबिले तारीफ है। मैं इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय को मुबारकवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से एक संतुलित बजट पूरे प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया

है यह एक सोच की बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि हरियाणा प्रदेश की तरक्की की गाड़ी जो पहले रुकी हुई थी उसको पिछले तीन साल से हमारे मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे तालमेल के साथ दोनों आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर इसी तरह हरियाणा प्रदेश विकास करता रहा तो बहुत जल्दी हरियाणा प्रदेश नम्बर एक के आंकड़े को अचीव कर लेगा। अध्यक्ष महोदय, पूरा प्रदेश जानता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी की नेक नीयती और नीति ने प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हरियाणा में 20 जिले हैं और उनमें मेवात जिला पिछली सरकारों की अनदेखी की वजह से पिछड़ा हुआ जिला है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसकी तरफ भी ध्यान दिया है। मैं एक कहावत कहना चाहूंगा कि यदि पड़ोसी के घर भेली फूटेगी तो भोरा हमारे घर भी आयेगा। आज के दिन जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं उनके साथ-साथ मेवात जिले में भी मुख्यमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जबकि पिछली ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार के समय में एक भी तरक्की का काम मेवात जिले में नहीं करवाया गया। अलबत्ता उन्होंने वहां के लोगों की नब्ज को पढ़कर वोट बटोरने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, मेवात का एरिया मुस्लिम बहुल एरिया है। चौटाला जी ने वहां पर रोजा इफ्तयार की परम्परा शुरू की ताकि वह वहां पर धार्मिक भावना को जगाकर वहां के लोगों से वोट ले सकें। इसके अतिरिक्त कब्रिस्तान की चारदीवारी बनाने के नाम पर भी उन्होंने धार्मिक भावनाओं को वोट लेने के लिए उकसाने की कोशिश की। जहां तक मेवात को जिला बनाने की बात है तो जब वे 6 साल तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तो उस दौरान उन्हें मेवात को जिला बनाने का ख्याल नहीं आया लेकिन आखिर जब चलते वक्त उन्होंने मेवात को जिला घोषित किया तो उन्होंने उसका नाम रखा ''सत्यमेवपुरम''। क्योंकि वहां पर ''मेव'' कम्युनिटी बसती है। इसलिए उन्होंने ''सत्यमेवपुरम'' में ''मेव'' शब्द को बीच में डालकर ''मेव'' कम्युनिटी को इसमें अटैच करने की कोशिश की। इस प्रकार से उनकी भावनाओं को कैश करके उन्होंने वोटों के रूप में बदलने की कोशिश की। वे इस तरह के काम करने में बड़े माहिर हैं। जहां तक मेवात के पिछड़ेपन की बात है तो उन्होंने मेवात को प्रगति और विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए कोई काम नहीं किया। आज जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी सभी को साथ लेकर प्रगति और विकास के पथ पर चल रहे हैं, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को मुबारकवाद देता हूं। प्रत्येक जिले में मॉडर्न स्कूल खोले गये हैं। मेवात में भी मॉडर्न स्कूल खोला गया है। मेवात-उटावड़ में एक पॉलिटैक्नीक कॉलेज है उसमें सीटों को दुगुणा करते हुए उटावड़ गांव के लिए रिजर्वेशन दी। यहां तक कि पूरे मेवात के लिए रिजर्वेशन दी। हरियाणा में एजूकेशन के मामले में मेवात बहुत पीछे था। आई०टी०आईज० की स्थापना के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए जिस तरह से आज मुख्यमंत्री ने नूंह में आई०टी०आई० की आधारशिला रखी है यह एक सराहनीय कदम है। यह आई०टी०आई० हरियाणा में सबसे बड़ी आई०टी०आई० होगी। उस एरिया को उसमें 50 प्रतिशत रिजर्वेशन दी गई है, चाहे वह नगीना हो और चाहे वह झिरका हो। उसमें सीटों को बढ़ाया गया है। इसी तरह से वहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय

[श्री हबीब-उर-रहमान]
भी खोला गया है। इसके अलावा लड़कियों के लिए ब्लॉकवाईज स्कूल भी खोले गये हैं। हमारे मेवात में यह सबसे बड़ी समस्या है कि वह पढ़ा-लिखा एरिया नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने स्कूलों का जाल बिछाते हुए 137 स्कूलों को एक कलम से अपग्रेड किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेवात को याद रखते हुए इनके द्वारा 137 प्राईमरी स्कूलों को अपग्रेड किया गया है। इन्होंने पहली बार यह सब कुछ किया है। इसके लिए भी मैं इनका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। ये हरियाणा के इतिहास में सबसे पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने मेवात के लिए इतना कुछ किया है। एग्रीकल्चर रीजनल सैन्टर वहां खोला गया, एम०डी०यू० का रीजनल सैन्टर वहां पर खोला गया है और सबसे बढ़कर एग्रीकल्चर कम्पलैक्स वहां पर बनाया गया। कोटला लेक प्रोजैक्ट की मंजूरी देते हुए 104 करोड़ रुपये इस स्कीम के लिए दिए गए ताकि वहां की सिंचाई और पीने के पानी की समस्या हल हो सके। इसके अतिरिक्त मेवात फीडर कैनाल वहां के लिए दी है। आज तक यह पिछली सरकारों का रिकॉर्ड है कि जिन स्कीमों और जिन कामों से मेवात इलाके की तरक्की होती वह एक भी काम और स्कीम मेवात को इससे पहले के मुख्यमंत्रियों द्वारा नहीं दी गई थी। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा सबसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मेवात के विकास के लिए सोचा है। मैं इनके किसी काम तो नहीं आ सकता अलबत्ता दुआएं जरूर देता हूं और मेरे साथ ही वहां की आने वाली जैनरेशन्ज भी इनको दुआएं देंगी और इनको याद रखेंगी। मेरी तो इनके लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए यही दुआएं हैं कि हमेशा इनका राज बना रहे। हमारे मेवात से कांग्रेस पार्टी को एक सीट मिली थी उस रेशों के हिसाब से भी हम दो इंडीपैंडैंट उम्मीदवार वहां से जीत गये और इनकी नीयत और नीति को देखकर हमने इनको समर्थन दिया और उसी नीयत और नीति के ऊपर जो ये खरे उतर रहे हैं मैं समझता हूं कि आने वाले समय में मेवात भी बाकी 20 जिलों के बराबर तरक्की करेगा और मेवात की जनरेशन यही दुआएं देती है कि इस टर्म के साथ-साथ पीढ़ी दर पीढ़ी माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा हरियाणा में राज करें। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री नरेश कुमार प्रधान (बादली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो बजट पर मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं जिन्होंने किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, अधिकारियों और हरेक वर्ग की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक शानदार बजट पेश किया है। साथ ही साथ मैं माननीया श्रीमती सोनिया गाँधी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हरियाणा प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया जो स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त परिवार से है तथा एक ईमानदार व्यक्तित्व का धनी है। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश समृद्धि और विकास के रास्ते पर अग्रसर है इसके लिए हम सरकार को बधाई देते हैं। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस प्रदेश को

काफी पहले तरक्की कर लेनी थी लेकिन इस प्रदेश पर कई बार आक्रमण हुए। दो सौ अढ़ाई सौ साल तक तो अंग्रेजों ने इस देश पर राज किया और कई बार यहां पर मोहम्मद गजनवी जैसे लोगों ने भी आक्रमण किये और लूट कर चले गये। उसके बाद जब स्ववतंत्रता की खुली सांस लेने का मौका आया और देश को तरक्की करने का समय आया तो हरियाणा प्रदेश का यह दुर्भाग्य रहा कि ऐसे-ऐसे लोगों को सत्ता प्राप्त हुई जो मोहम्मद गजनवी के भी चाचा-ताऊ लगते थे। जिन्होंने प्रदेश को बुरी तरह से लूटा और प्रदेश को निचोड़ कर रख दिया। कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। हरियाणा प्रदेश को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। जो आदमी साइकिल पर चुनरी बेचते थे, वे इस देश के बहुत बड़े उद्योगपतियों में कैसे शामिल हो गये? वे इसलिए उद्योगपति बन गये क्योंकि उन्होंने इस प्रदेश को लूटा है। एक आदमी जो कभी रिक्शा में सफर करता था और 22 की बीड़ी पीता था वह कैसे इस प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योगपति बन गया? (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका है।

श्री बलवन्त सिंह सढौरा : अध्यक्ष महोदय, वे इस प्रदेश के लैंडलॉर्ड आदमी हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ईश्वर सिंह पलाका : स्पीकर साहब, आप मेरी बात सुनें।

श्री अध्यक्ष : पलाका साहब, उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया। चलो, आप बोलिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ईश्वर सिंह पलाका : अध्यक्ष महोदय, लूट खसोट का काम तो नरेश शर्मा जी जैसे आदमी करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है?

श्री अध्यक्ष : हाँ जी, गौतम जी, आपका प्वाइंट ऑफ ऑर्डर क्या है?

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी नरेश शर्मा जी जो बात कह रहे हैं वह 100 प्रतिशत सही है। मेरे पिता जी 120 एकड़ जमीन के मालिक थे। उनके सगे भाई ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया था। हम चारों भाईयों को 30-30 एकड़ जमीन आती थी और जिस भाई का जिक्र शर्मा जी कर रहे हैं वह भाई लूट-पाट करके 3 हजार करोड़ रुपये का मालिक बन गया और सुप्रीम कोर्ट ने वह केस रिमांड किया था। हाई कोर्ट में जाकर गवाही दी लेकिन वह भाई समझौता कर गया और एक जिला शायद लूटने के लिए उसके पास छोड़ गया कि तुम भी लूटो और मैं भी लूटता हूँ। इसलिए वह चुप हो गया। मैं तो चौटाला जी को कहता हूँ कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की एक आदम कद तस्वीर (जैसी दिल्ली से गुड़गाँव आते हैं तो हनुमान जी की लगी हुई है) अपने घर में और लूटपाट के जो दूसरे अड्डे हैं वहां पर लगानी चाहिए। वे इन्हीं साहब की मेहरबानी से ही बचे हुए हैं वर्ना उसका यहां आने का कोई ब्यौंत नहीं था। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील कुमार इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप बजट पर बुलवाईये, हम भी बजट पर बोले हैं। सदन की गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। माननीय सदस्य बार-बार एक ही बात कहते हैं यह कोई तुक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप जाना चाहते हैं क्या? (शोर एवं व्यवधान)आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, आप लोग एक मिनट के लिए बैठें (विघ्न एवं शोर) आपने यह कहा है कि चौधरी देवी लाल बहुत बड़े जमींदार थे। (विघ्न एवं शोर) आप अपनी सीटों पर बैठें। (विघ्न एवं शोर) चौधरी देवी लाल ने तो यह भी कहा था कि यह मेरा लड़का नहीं है फिर उनकी प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा कैसे हो गया? (विघ्न एवं शोर) चौधरी देवी लाल की प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा कहां से आ गया? (विघ्न एवं शोर) पण्डित जी, आप अपनी स्पीच कांटीन्यू करें (विघ्न एवं शोर)

श्री बलवन्त सिंह साढौरा : अध्यक्ष महोदय, *** *** ***

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, *** *** ***

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, ऑनरेबल मैम्बर यह कहना चाहते हैं कि पहले बजट कम क्यों था और अब बजट ज्यादा क्यों है? (विघ्न एवं शोर) ये भूमिका बना रहे हैं (विघ्न एवं शोर) आप इनको अपनी भूमिका बनाने दो।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, *** *** *** (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : आप सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें (विघ्न एवं शोर) Nothing to be recorded. (Interruptions). Please take your seats. Sharma ji, please continue. (Interruptions) शर्मा जी, आप बजट पर बोलें। (विघ्न एवं शोर) पण्डित जी, आप कान्टीन्यू करें। (विघ्न एवं शोर)

श्री नरेश कुमार प्रधान : अध्यक्ष महोदय, कृषि क्षेत्र में सरकार ने किसान को हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उच्चकोटि की शिक्षा प्रदान करना, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना, सामाजिक क्षेत्र में समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण करना और जो मजबूत अर्थ-व्यवस्था इस सरकार ने दी है उसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर राजा का खजाना खाली होता है तो वह नागरिकों और देश को तबाह कर देता है जैसे कि पहली सरकारों ने किया है। मेरा तो एक सूत्रीय कार्यक्रम है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने हरियाणा प्रदेश को बुरी तरह से लूटा है उनको आज तक कोई सजा नहीं हुई है। जनता इस बारे में हम से पूछती है कि उनका क्या हुआ तो हम कहते हैं कि कार्यवाही चल रही है। जनता पूछती है कि कौन कार्यवाही कर रहा है तो हम कहते हैं कि सी०आई०डी० और सी०बी०आई० कार्य कर रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

से आग्रह करता हूं कि सी०आई०डी० और सी०बी०आई० तो अपने हिसाब से कार्य करती रहेंगी लेकिन एक महीने के अन्दर-अन्दर इनको उठा कर जेल में पटको और जो लूट का धन है उसको कुड़क करो। अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार ऐसा करती है तो इससे प्रदेश की गरीब जनता के अन्दर खुशी होगी और हरियाणा प्रदेश का भला होगा। इससे लोगों को नसीहत मिलेगी और हरियाणा में फिर कभी ऐसे लोग सत्ता में नहीं आ पाएंगे। जो अच्छे लोग हैं वे ही सत्ता में आएंगे और हरियाणा प्रदेश के हित के लिए काम करेंगे। इस प्रकार को जो लोग हैं वे इस प्रदेश को छोड़ कर भाग जाएंगे और अन्नामलाई जेल में बैठकर भजन कर लेंगे इससे प्रदेश का बहुत भला होगा। (विघ्न) स्पीकर साहब, सरकार ने प्रदेश के लिए जो सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्धन किये हैं उनके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। अनुसूचित जाति के अपने भाई-बहनों, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों, महिलाओं और बच्चों के बारे में सरकार ने गहरी चिन्ता जताई है। हालांकि अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 19.35 प्रतिशत है तथापि वर्ष 2008-09 के दौरान योजनागत परिव्यय में 21.55 प्रतिशत राशि का प्रावधान अनुसूचित जाति के विशेष घटकों एस०सी०, एस०टी० और बी०सी० के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गों के विकास एवं उत्थान के लिए किया गया है। अध्यक्ष महोदय, बी०पी०एल०, अनुसूचित जाति, पिछड़े और गरीब परिवारों को 100-100 गज के आवासीय प्लॉट देने का प्रबन्ध सरकार ने किया है जिसके लिए हम सरकार को बधाई देते हैं और उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। हमारी सरकार राज्य में सामाजिक कल्याण के विकास को बढ़ावा देने और उसको समाज के हर स्तर तक पहुंचाने के लिए बचनबद्ध है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार का आभार प्रकट करता हूं कि जैसे ही इन्होंने सत्ता सम्भाली थी, उसी समय इन्होंने घोषणा की थी कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश का मुख्य सेवक हूं। जनता ने मुझे सेवा का मौका दिया है तो मैं अपने साथियों से भी आग्रह करता हूं कि वे 24 घंटे जनता की सेवा में तत्पर रहें। अध्यक्ष महोदय, जैसे पहले की सरकार के वक्त में बड़ी-बड़ी मालाएं लेते थे, बड़ी-बड़ी लूट करते थे, इन्होंने लोगों से यह भी कहा कि अब तुम्हारा लेने का टाईम नहीं है। सर, अगर आज किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो हर गरीब आदमी उसके घर में जाकर बधाई देता है और बच्चे को पुचकार कर एक, पांच या सौ रुपया देकर प्यार देता है। उसका मान-सम्मान करता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे जो पुराने माननीय साथी हैं जिनकी पिछले तीन सालों से पहले सरकार थी और जब वे ऐसी जगह पर जाते थे तो यह तय करते थे कि आपका खाना खांवांगे, जाड़ हिलावांगे, सौदा कितने में पटेगा और भेंट क्या करोगे। वे एक रुपया देने की बजाए भेंट लेते थे। आशीर्वाद देने की बजाए उनको लूट कर आते थे। जाड़ घिसाई के पैसे लेकर आते थे। (विघ्न) उन्होंने जनता जनार्दन को ऐसा लूटा था कि आज वे पांच मिनट भी यहां पर बैठकर हमारे से आंख भी नहीं मिला सकते हैं। बार-बार यहां से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज कृषि में विकास दर समग्र रूप से धीमी पड़ गई और अत्यधिक ग्रामीण खर्चदारी की वजह से हताश व परेशान किसानों द्वारा देश के कई भागों में आत्महत्याएं करने की घटनाएं हो रही थीं। इस अवसर पर यू०पी०ए० की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मुख्यमंत्री जी के

[श्री नरेश कुमार प्रधान]

आह्वान पर 60,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ किये। उसके लिए हम यू०पी०ए० की अध्यक्षा और हमारे मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम यह भी मानते हैं कि बड़ी संख्या में ऐसे किसान भी हैं जिन्होंने स्थानीय साहूकारों और आढ़तियों से बहुत ऊंची ब्याज की दर पर ऋण ले रखा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस वर्ग पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए आश्वासन दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह भी एक ऐतिहासिक कदम इस सरकार का होगा। इसके लिए भी हम इस सरकार को और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से छोटी-सी प्रार्थना है कि सदन में कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो जनता की आंखों में धूल झोंक कर आए हैं। वे आज भी फिर से कहते फिर रहे हैं कि एक बार और सत्ता दे दो, सात पीढ़ी का जुगाड़ कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई बड़ा गांव होगा तो यूं घनी बोल दी और कोई छोटा गांव होगा तो कहते हैं कि चार पीढ़ियों का जुगाड़ कर देंगे। कभी कहते थे कि नोटों की मशीने दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, एक बड़े गांव वाला बोला कि नोटां की मशीन कै-कै दिन दोगे, न्यू कहया भई एक-एक दिन। न्यू बोल्या जी म्हारा तो घना बड़ा गांव है 30000 हजार कुढ़ी का। न्यू कहया भई तुम दो दिन ले ल्यो लेकिन वोट तो गेरो। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सत्ता में आते ही नोटों की मशीन देने की बजाए मशीनगन फिट कर दी। महम में निर्दोष लोगों का खून बहा दिया था, कण्डेला के अन्दर 9-9 किसानों की हत्याएं कर दी गई थी और दुलीना के अन्दर 4-4 हरिजन भाईयों को मिहत्थे जला दिया था। अध्यक्ष महोदय, ऐसे-ऐसे लोग फिर से सत्ता की कामना करते हैं। स्पीकर सर, एक बार एक आदमी एक गांव के अन्दर घोड़ी लेकर चला गया। गैर टाईम हो गया, उसने सोचा कि इस गांव के अन्दर शरण ले लेता हूं। वह एक बेईमान कै फंस ग्या, बारने आगे घोड़ी बांध दी। न्यू बोल्या कि भई एक वक्त की रोटी मिल जाएगी। न्यू बोल्या कि मिल जाएगी भाई। सर, घोड़ी ब्यातड़ थी और रात को ब्यागी। घोड़ी ब्यागी तो तड़के वह चालन लाग्या, उसने पहले बच्ची खोली। न्यू बोल्या भाई के करै है। घोड़ी वाला बोल्या कि अक मेरी घोड़ी ब्यागी, इस बच्ची ने भी ले ज्यांगा और घोड़ी ने भी। न्यू बोल्या घोड़ी ना ब्याई है या बच्ची तो म्हारी भैंस के पैदा हुई है। तेरी बच्ची कड़ै तैं आई या तै म्हारी है। घोड़ी वाला बोल्या कै इसा जुल्म, भैंस के तो घोड़ी की बच्ची पैदा ही नहीं हो सकती है। न्यू बोल्या अक म्हारी कै होया करै। घोड़ी वाले ने गांव जोड़ लिया, 10-5 आदमियां धौरै गया, सरपंच धौरै गया और न्यू बोल्या जी मेरी गैल्यां बड़ा अन्याय हो गया। एक टाईम की रोटी गैल्यां पांच किलो तूड़ा मांगया था। मेरी घोड़ी ब्या गई अर बच्ची ने चापर गया। वह बोल्या सरपंच साहब न्याय करो। सरपंच बोला कि न्याय क्या करूं इसकी भैंस ने पिछले साल भी घोड़ी की बच्ची दी थी इसलिए घोड़ी की बच्ची तो इसकी है। घोड़ी वाला हाथ जोड़कर बोला कि भला हो आप जैसे न्यायकारियों का और वह रोने लग गया और कहने लगा कि एक बात और बता दो। सरपंच बोला कि एक क्यों तो चार बातें पूछ ले क्योंकि हम तो बड़े न्यायकारी हैं। वह बोला कि जब तुम मर जाओगे तो फिर ऐसे-ऐसे न्याय कौन करेगा। वह कहने लगा कि हम मर जाएंगे तो हमारे बाद

हमारी औलाद न्याय करेगी। घोड़ी वाला कहने लगा कि निर्भागो, ऐसे-ऐसे न्याय करके क्या आप औलाद की भी बाट रखते हो? स्पीकर सर, इसी तरह से जब हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे-ऐसे जुल्म चौटाला जी ने किए हों और अगर वे सत्ता में आने की बाट देखते हैं तो क्या यह ठीक है? धन्यवाद।

श्री अरजन सिंह : स्पीकर साहब, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए टाईम दिया। सर, आप मुझे कितना समय बोलने के लिए देंगे?

श्री अध्यक्ष : आपको पांच मिनट बोलने के लिए दिए जाते हैं।

श्री अरजन सिंह : स्पीकर साहब, आप मुझे पचास मिनट बोलने के लिए दें क्योंकि 75 घंटे का सैशन है। मैं भी किसी पार्टी से बिलोंग करता हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप सात मिनट बोल लें।

श्री अरजन सिंह : स्पीकर साहब, बड़ी भारी रियायत कर दी। सर, बजट पर कई सदस्य बोले हैं और उनमें से कई सदस्यों ने बजट का समर्थन भी किया है। बजट का समर्थन करने वाले सदस्यों के साथ मैं भी अपने आपको जोड़ता हूं। जिन्होंने बजट की सराहना की है मैं उनके साथ अपने आपको जोड़ता हूं और जिन्होंने बजट की आलोचना की है उनके साथ मैं अपने आपको नहीं जोड़ता हूं। स्पीकर साहब, जितने भी मेरे पड़ौस में भाई बैठे हैं ये ठीक-ठाक आदमी हैं। मैं उनकी आलोचना नहीं करता लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये लोग तो अच्छे हैं परन्तु ये गलत जगह चले गए हैं और इनका रिमोट किसी और के हाथ में है। वह रिमोट अब तो चला गया है इसलिए फिलहाल अब ये ठीक-ठाक रहेंगे। स्पीकर साहब, जब भी कोई बोलता है तो मैं अपनी तरफ से टिप्पणी नहीं करता हूं इसलिए मेरी सारे भाईयों से रिक्वैस्ट है कि जब मैं बोलूं तो किसी को भी बीच में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं बजट पर ही बोलूंगा। स्पीकर साहब, बजट के बारे में सबको पता है कोई देखकर भी अनदेखी करे तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। सरकार की बहुत बढ़िया नीयत है। मैं बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करता हूं इसलिए कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग गैलरीज में बैठे हुए हैं ये सारे के सारे वही लोग हैं जो भुक्तभोगी हैं। इनको हर चीज का पता है। इनको अपने नफे-नुकसान के बारे में पता है। जो सरकार ने इनके लिए किया है उसका भी इनको पता है और जो पिछली सरकार ने इनके लिए किया था उसका भी इनको पता है। अगर सरकार अच्छा करेगी तो हम उसको अच्छा कहेंगे। चाहे अच्छा ये लोग करें और चाहे अच्छा सरकार करे हम उसको अच्छा ही कहेंगे और यदि कोई गलती करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। चाहे गलत काम ये करें चाहे वे करें, हम उसका विरोध जरूर करेंगे। बहुत स्पष्ट सी बात है। स्पीकर साहब, कांग्रेस की इस सरकार से पहले जो सरकार थी उससे लोगों का विश्वास उठ गया था। लोग सोचते थे कि अब क्या होगा, हम कैसे बचेंगे? उस सरकार के जो नेता थे वह सिर्फ झूठ बोलकर एक मदारी जैसी ढोलक बजाकर बड़े स्पष्ट तरीके से अपना भाषण शुरू करते थे और लोगों को गुमराह करते थे। लोग इनकी बातों को सुनकर सोचते थे कि किस दिन इसकी सरकार आएगी

[श्री अरजन सिंह]

और किस दिन ये जो योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं वह पूरी होंगी। इनके वही भाषण लोगों के कानों में गूंजते रहे। वे सोचते थे कि क्या ये वही लोग हैं जो इतना अच्छा भाषण देते थे? लोगों का यह कहना था कि इन लोगों ने हमें लूट खसोटकर बर्बाद कर दिया। ये इतने बढ़िया स्टाइल से अपना भाषण शुरू करते थे कि जिसका कोई जवाब नहीं। ये कहते थे कि चैत्र और वैशाख की तपती लू में, सावन भादों की अंधेरी रात में साँप और बिच्छुओं की परवाह न करते हुए धरती माता का सीना चीरकर जब किसान का बेटा अन्न पैदा करता है, जब उसको वह मंडी में ले जाता है और अगर उसको उसका भाव नहीं मिलता तो वह किसान निराश हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, बोली कब लगी जब वह कुर्सी पर बैठ गया। उसके बाद जीरी की बोली एक हजार से गिरकर चार सौ रुपये पर खत्म हुई और आज की सरकार में जीरी की बोली 800 रुपये से लेकर 2200 रुपये में लग रही है। पिछली सरकार के दौरान एक किल्ले की जीरी दस हजार रुपये में लूटती थी लेकिन आज वह जीरी 50 हजार, 60 हजार रुपये में बिक रही है। इसी तरह से पोपुलर के रेट की बात है उस समय जो पोपुलर की बोली लगी थी वह 150 रुपये की लगी थी लेकिन आज वह 750 रुपये पर पहुंच रही है। पहले जो ट्रॉली 15000 रुपये की बिकती थी वह आज 70 से 80 हजार रुपये में बिक रही है। पिछली सरकार ने जो गेहूं के रेट दिये थे वह किसी से छुपे हुए नहीं हैं। जिसकी जेब से पैसा निकलता है उसी को उसका अहसास होता है। आज अगर किसी रिश्तेदार से 10-20 हजार रुपया उधार ले लो और उसका वापस न मोड़ो तो रिश्तेदारी खराब हो जाती है। पिछली सरकार के समय में ट्रॉली 15000 रुपये में बिकी। हर छोटे से छोटे किसान की एक किला जमीन तो होती ही होगी और एक किले में एक ट्रॉली तो गेहूं या जीरी की पैदा हो ही जाती है तो जिस किसान को 65000 रुपये का एक ट्रॉली में नुकसान हुआ तो ये किसान हितैषी होने का दावा कैसे करते हैं? ये कहते क्या थे कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी बिजली-पानी फ्री, मीटर फ्री और मीटर वाला भी फ्री। शेर के पट्ठे ने भट्ठा बैठा दिया और मीटर ऐसे ले आया कि बिजली हो या न हो मीटर नहीं थमता। मैं तो मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि जिन्होंने पब्लिक की इतनी ज्यादा चिन्ता की और पब्लिक में बिश्वास पैदा किया। पब्लिक के हितों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हमें जो भी बात करनी हो वह पब्लिक के हित में करनी चाहिए क्योंकि पता नहीं दुबारा आएं या नहीं आएं। गुमराह करने वाली बात करना या झूठी बात करना और निजी स्वार्थ के लिए कोई बात करना मैं तो अच्छा नहीं समझता। अपना निजी स्वार्थ या हित तो हम किसी भी पार्टी में रह कर सिद्ध कर सकते हैं लेकिन ऐसा करके हम पब्लिक की सेवा या उनका हित सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक काम करने का सवाल है, मुख्यमंत्री जी ऐसे दूरदर्शी हैं कि हम जिस बात को कहना चाह रहे होते हैं उससे पहले ही उस बात को समझ कर, उस बात को कैच करके उससे पहले ही उस काम को कर देते हैं। मैं बलवंत सिंह सढौरा जी को कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार के साढ़े पांच साल के शासन काल के दौरान प्रदेश की भी और इनके अपने

हल्के की सड़कें बहुत खराब हालत में पड़ी रहीं, वही सड़कें आज ठीक हालत में हैं। जहां सरकार की कमी होगी वहां मैं कमी भी बताऊंगा लेकिन मैं **(इस समय सभापतियों की सूची में से माननीय सदस्य आई०जी० शेर सिंह पदासीन हुए।)** यह भी कहना चाहूंगा कि जब से प्रदेश में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार बनी है, सरकार बनते ही उन्होंने बिजली पैदा करने का काम शुरू कर दिया। बिजली जैसे ही तैयार होगी, वह दी जाएगी। पिछली सरकार ने क्या किया कि दूसरे राज्यों से बिजली ले ली और उनके पैसे नहीं दिये। अब अगर हमारी सरकार दूसरे राज्यों से बिजली मांगती है तो वे कहते हैं कि पहले पैसे दो फिर बिजली देंगे। सभापति महोदय, खाये कोई और दे कोई। आज मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि बहुत सूझबूझ से प्रौजैक्ट लगाने में लगे हुए हैं और जैसे ही बिजली तैयार होगी, वह सारी बिजली लोगों को ही दी जाएगी। (विघ्न) सभापति महोदय तो मेरे अपने ही साथी हैं। ये मुझे बैठने के लिए नहीं कहेंगे। ऐसा मुझे विश्वास है। सभापति महोदय, कर्ज माफी की बात जो सरकार ने की है उसके लिए भी मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। पिछली सरकार की नीतियों की वजह से किसान कर्ज में डूब गए थे। फसल के रेट किसानों को नहीं मिले। किसान को कितना भी नुकसान क्यों न हो लेकिन मजबूरन वह फसल ही बोएगा। आज किसान अपनी फसल बेचकर ही अपना जीवन यापन कर लेता है। उसे कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं रहती।

श्री सभापति : आप वाईंड-अप करने की कोशिश करें।

श्री अरजन सिंह : सभापति महोदय, मुझे बीच में न टोको। बीच में टोकने से मेरे पल्ले कुछ नहीं रहता। मुझे जो बात कहनी है वही कहनी है।

श्री सभापति : मुझे भी टाइम का पालन करने के निर्देश हैं।

13.00 बजे

श्री अरजन सिंह : सभापति महोदय, इस सरकार ने हर जाति का ख्याल रखा है। मेरा हल्का हिमाचल प्रदेश से लगता है और मेरे हल्के में मुस्लिम जाति के लोग हैं उनके पास कोई साधन नहीं है न उनके पास कोई जमीन है। वे भैंस वगैरह रख कर अपना दूध का काम करते हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार ने मेवात में जो सुविधाएं हमारे मुस्लिम भाइयों को दे रखी हैं उसी तर्ज पर मेरे हल्के के मुस्लिम भाइयों को भी सुविधाएं दी जाएं। जैसे उर्दू की जे०बी०टी० का ट्रेनिंग सैंटर खोलना चाहिए। मुस्लिम लड़कियों के लिए सी०बी०एस०ई० की तर्ज पर स्कूल खोलना चाहिए और होस्टल भी खोलना चाहिए। आई०टी०आई० खोलनी चाहिए, खाड़ विकास बोर्ड तथा खाड़ क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान के तहत बालिका कस्तूरबा गान्धी स्कूल, होस्टल सहित खोला जाए। वहां के किसान भैंस रखकर दूध का काम करते हैं इसलिए एक कोल्ड मिल्क प्लांट खोलना चाहिए। उसमें मुस्लिम लड़कियों को नौकरी में आरक्षण दिया जाना चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि छछरौली के अन्दर एक बिजली का प्लांट लगा हुआ है उसकी मशीनरी 30 साल पुरानी हो गई है उसके पुर्जे अब नहीं मिलते इसलिए उनको सहारनपुर जाकर जुगाड़ फिट कराना पड़ता है इसलिए बिजली की उस मशीनरी को बदलना चाहिए।

श्री सभापति : अरजन सिंह जी आप वाईंड-अप कीजिए बाकी मैम्बर्ज ने भी बोलना है।

श्री अरजन सिंह : यमुनानगर प्लांट में भी बहुत पुरानी मशीनरी लगी हुई है जिसे 300 मैगावाट बिजली पैदा करनी चाहिए उसके स्थान पर 160 मैगावाट बिजली पैदा हो रही है। इससे ऊपर जाकर वह मशीनरी ट्रिप कर जाती है। उसको ठीक करना चाहिए। इसी प्रकार से कलेसर से बंजारा बास वाद की सड़क जो कि लगभग 1½ किलोमीटर की है उसको बनाना चाहिए। दूसरे जो गुर्जर और घुमन्तु लोग हैं जो भैंसों का दूध बेचकर अपना काम चलाते हैं उनको रहने के लिए जगह उपलब्ध करवाई जाए।

श्री सभापति : अरजन सिंह जी, आप वाईंड-अप कीजिए।

श्री अरजन सिंह : सभापति महोदय, गौतम साहब अभी सदन में बैठे नहीं हैं। कल उन्होंने बहन मायावती और मान्यवर श्री कांशी राम जी के बारे में एक बात कही थी। जब कोई सदस्य हाउस में मौजूद नहीं है तो उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बहन मायावती जी ने यह कहा था, ''तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार।'' हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा और मान्यवर कांशीराम जी ने ऐसी बात कभी नहीं कही थी। मुझे नहीं पता या तो ये रामकुमार गौतम जी पण्डित नहीं है या फिर सतीश मिश्रा जी पण्डित नहीं हैं।

श्री सभापति : अरजन सिंह जी, आपने जो कहा वह ठीक है, आप चेयर को एड्रैस कीजिए। आप जल्दी वाईंड-अप कीजिए।

श्री अरजन सिंह : सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके सहयोगियों के बारे में एक बात कहना चाहता हूं,

''सब आपको चाहते हैं, यह शोहरत की बात है।
मैं आपको चाहता हूं, यह मेरी किस्मत की बात है॥
कर्म कर ही दिया आपने इस हरियाणा पर।
ये भी जनाब आपकी हिम्मत की बात है॥
रखता नहीं कोई किसी को याद।
यह भी अपनी-अपनी फितरत की बात है॥
तारीफ कर रहे हैं सब आजकल तुम्हारी।
यह सब आपकी शराफत की बात है॥
किसानों के कर दिये कर्ज सब आपने माफ।
यह भी आपकी दरियादिली की बात है॥
यूं तो सुने हैं कई किसानों के मसीहा हमने।
यह भी हुड्डा साहब आपके जज्बात की बात है॥''

श्री रणधीर सिंह (बरवाला) : सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वित्त मंत्री महोदय ने हमारी सरकार का चौथा बजट पेश किया है। इस बजट में सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा प्रदेश के किसी भी वर्ग के ऊपर किसी किस्म का टैक्स नहीं लगाया गया है। हरियाणा प्रदेश की सरकार को बने हुए 3 वर्ष हुए हैं। इन तीन वर्षों में हरियाणा के वित्त मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय ने हरियाणा की अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार किया है और उस सुधार को देखते हुए हरियाणा का बजट तीन गुना तक बढ़ाया गया है इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं। यू०पी०ए० अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो इस देश के कर्जदार किसान थे, उनके 60 हजार करोड़ रुपये के ऋण माफ करने का एलान किया है, इसके लिए इस देश और प्रदेश के किसान श्रीमती सोनिया गांधी के, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह जी के और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं। सभापति महोदय, हम मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हरियाणा के किसान को गेहूं, गन्ने, सरसों और धान की फसल का अच्छा भाव दिया है। इसके लिए हम यू०पी०ए० अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। हरियाणा प्रदेश में चाहे वह चुनाव का समय था, चाहे उसके बाद का समय था, हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय ने हरियाणा के किसी भी वर्ग के लिए कोई ऐसा नारा नहीं दिया था कि हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हरियाणा के किसानों के 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ किए जाएंगे या हरियाणा के गरीब वर्ग के लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए 8 हजार फ्री कनैक्शन देने का काम किया जाएगा। आज चाहे शिक्षा व्यवस्था का मामला हो, चाहे वह किसान से सम्बन्धित मामला हो, गरीब मजदूर से सम्बन्धित मामला हो, चाहे व्यापारी से सम्बन्धित मामला हो, चाहे कर्मचारी और अधिकारियों से सम्बन्धित मामला हो या फिर दूसरा कोई भी क्षेत्र हो हरियाणा सरकार ने हर वर्ग के लिए अलग-अलग योजनाएं दी हैं ताकि हर वर्ग के लिए यह बजट लाभदायक बजट साबित हो। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री महोदय जी की तमन्ना थी कि हरियाणा के किसान ने जो साहूकारों और आढ़तियों से कर्जा लिया है उसके बारे में सोचा जाए। हरियाणा के किसान को उस कर्जे से मुक्त करने के बारे में विचार चल रहा है जो कि सरकार का एक बहुत बढ़िया कदम है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय और हरियाणा की सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और सम्पत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाली स्टैम्प ड्यूटी को 8 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया गया है। महिलाओं के नाम रजिस्ट्री करवाने पर पहले 2 प्रतिशत की छूट थी अब इसमें स्टाम्प शुल्क में एक प्रतिशत की और छूट देना हरियाणा सरकार का सराहनीय कदम है। अर्थ व्यवस्था के विकास को सार्थक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसका लाभ कुछेक व्यक्तियों तक सीमित न रहकर प्रदेश के हर वर्ग तक जाए। इसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय जी ने गृह ऋण की सीमा 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 12.5 लाख रुपये करने का काम किया है। इसी के साथ-साथ घर की मरम्मत तथा विस्तार आदि के लिए ऋण सीमा वर्तमान में एक लाख रुपये और 1.80 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये और अढ़ाई

[श्री रणधीर सिंह]

लाख रुपये कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जहां तक मुख्य भत्ते बढ़ाने की बात है उसको भी बढ़ाया गया है। सभापति महोदय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय ने शिक्षा की तरफ भी विशेष ध्यान दिया है। समाज के कमजोर वर्गों विशेषतः अनुसूचित जातियों के लिये सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने तथा उनका सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने अनुसूचित जाति शिक्षा प्रोत्साहन स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों के सभी छात्रों को 100 रुपये से 300 रुपये प्रतिमास तक तथा सभी छात्राओं को 150 रुपये से 400 रुपये प्रतिमास तक छात्रवृत्तियां दी जायेंगी। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति के सभी विद्यार्थियों को यूनिफार्म, लेखन सामग्री तथा स्कूल बैग आदि के खर्च के लिए भी 740 रुपये से 1450 रुपये तक एक बारगी भत्ता दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त चाहे प्रदेश में महिला यूनिवर्सिटी खोलने की बात हो, चाहे जींद में टैक्नीकल एजुकेशन देने की बात हो, हर काम के लिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय पैसा मुहैया करवा रहे हैं। इसी के साथ-साथ सरकार कृषि पम्प सैटों को सस्ती बिजली सप्लाई करने के लिए बिजली निगमों को सब्सिडी प्रदान करेगी। सभापति महोदय, इस बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि किसानों को जो ट्यूबवैल्स के कनैक्शन दिए जायें उनके लिए समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। जिस प्रकार से उद्योगों के लिए बिजली के कनैक्शन देने के लिए समय सीमा रखी गई है उसी प्रकार से ट्यूबवैलों के कनैक्शन के लिए भी समय सीमा निर्धारित की जाये। किसानों को ट्यूबवैल के कनैक्शन देने में दो-दो साल की देरी हो जाती है इसलिए मैं चाहूंगा कि बिजली के कनैक्शन के लिए पैसे जमा करवाने के बाद जब डिमांड नोटिस कट जाये, उसके बाद एक समय सीमा निर्धारित हो जाये कि इतने समय में कनैक्शन दे दिया जायेगा। मेरा अनुरोध है कि इस बारे में सरकार जरूर कोई पॉलिसी बनाये। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पुनः मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मैंने अपने हल्के कि जिन सड़कों का जिक्र किया है उनको अवश्य बनवाया जाये और जहां पर पानी की व्यवस्था की बात की है वह भी करवाई जाये तथा पैसा मुहैया किया जाये। सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त मैं मुख्यमंत्री जी को प्रदेश में बहुत सारे स्कूल और कॉलेज बनवाने के लिये धन्यवाद करूंगा और मांग करूंगा कि मेरे हल्के के बरवाला शहर में 40 कि०मी० की दूरी तक कोई सरकारी कॉलेज नहीं है इसलिए वहां पर एक सरकारी कॉलेज अवश्य बनवायें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, मैं आपका भी आभारी हूं। धन्यवाद!

श्री नरेश यादव (अटेली) : सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने की इजाजत दी इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, 18 मार्च को वित्त मंत्री जी ने सदन में जो बजट पेश किया उसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने संगठन 'हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति' की तरफ से अनुमोदन करता हूं। पिछले कई दिनों से सदन में बजट पर विस्तार से चर्चा हो रही है।

इस वर्ष के बजट में 6650 करोड़ रुपये का आबंटन प्रस्तावित है जिससे पता चलता है कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बजट पेश किया है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, इस बजट में कृषि क्षेत्र और बिजली क्षेत्र की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। बिजली के लिए 867 करोड़ रुपये और सिंचाई के लिए लगभग 800 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, जहां तक मैं पानी का जिक्र करूं विशेषकर जो अहीरवाल का एरिया है, वहां पर ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है। मैंने इस ओर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाया था जब वे हमारे इलाके में हकीकत रैली में गये थे कि हर साल 20-25 फीट पानी नीचे जा रहा है। खासतौर से मांगल चौधरी, अटेली, गोदबलावा और इसके अलावा महेन्द्रगढ़ जिले में 40-50 गांवों की एक बैल्ट है वहां पर भी यह समस्या बहुत चिंतनीय है। वहां पानी इतनी स्पीड से नीचे जा रहा है कि वहां के लोग पहले गांवों से पलायन करके खेतों में गये और फिर खेतों से पलायन करके पुनः गांवों में आये और अब बहुत से लोगों को पीने का पानी न होने की वजह से गांवों को भी छोड़ना पड़ रहा है। मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी इस बारे में बजट में कोई स्पैशल प्रावधान करें जिससे इन 150-200 गांव में ग्राऊण्ड वाटर रिचार्जिंग की इस तरह की कोई स्कीम बनाई जाये जिससे ग्राऊण्ड वाटर लैवल ऊपर आ सके और वे लोग वहां से पलायन न करके वहीं रह सकें। सभापति महोदय, इस सदन में हांसी बुटाना लिंक नहर पर भी खूब विस्तार से चर्चा हो चुकी है और निश्चित रूप से सरकार ईमानदारी से हांसी बुटाना लिंक नहर का निर्माण कर रही है। जिन राजनीतिक पार्टियों के पास इस नहर के मामले में कोई जवाब नहीं है उन राजनीतिक पार्टियों के बारे में विशेष तौर से मैं श्री चौटाला जी के बारे में बताना चाहूंगा कि चुनाव से पहले उनका नारा पूरा प्रदेश होता है और जब वे चुनाव जीत जाते हैं तो फिर वे केवल अपने जिले तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। चाहे वह नहर का पानी हो, चाहे वह युनिवर्सिटीज़ खोलने की बात हो और चाहे दूसरे कोई विकास के कार्य करने की बात हो। जब वे सत्ता से बाहर होते हैं तो उनको एस०वाई०एल० नहर भी याद आती है और पानी का मुद्दा भी याद होता है। लेकिन हांसी बुटाना लिंक नहर पर तो इस हाउस के अन्दर बड़ी क्लीयर बहस हो चुकी है और बहस के दौरान उन लोगों ने विशेष तौर पर माननीय चौटाला जी ने एक बार भी अपने मुखारविंद से यह नहीं कहा कि हांसी बुटाना लिंक नहर बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। इसका मतलब यह है कि वे इसके निर्माण के विरोधी हैं। जहां तक एस०वाई०एल० नहर की बात थी, पिछले दिनों सदन में चौटाला जी खड़े होकर एस०वाई०एल० नहर के निर्माण के बारे में बोलने लगे लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 18 लाख एकड़ फीट नहरी पानी पहले से ही हिसार और सिरसा बैल्ट में जाता रहा है। वहां पर इससे जो वाटर लॉगिंग हुई उससे वहां का किसान भी बर्बाद हुआ और दूसरी तरफ दक्षिणी हरियाणा का किसान भी पानी की कमी की वजह से बर्बाद हो गया क्योंकि नहरी पानी की कमी की वजह से

[श्री नरेश यादव]

ग्राऊण्ड वाटर लैवल 1400 फीट से भी नीचे चला गया। उन लोगों ने कभी भी एस०वाई०एल० नहर के लिए आंदोलन नहीं किया। कभी भी किसी प्रकार का आंदोलन नहीं किया और कभी भी संघर्ष नहीं किया। इसके विपरीत जब इसके लिए संघर्ष हुए, आंदोलन हुए तो उनकी खिलाफत करके उनको दबाया गया और लोगों पर लाठियां चलाई गई, गोलियां चलाई गई। खुद मैं उनके दमनकारी षड्यन्त्र का शिकार हुआ हूं। मैं खुद 10 दिन तक आमरण अनशन पर बैठा रहा। श्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ भी मैंने आन्दोलन चलाया। हमने नारनौल में भी आन्दोलन किया जिसमें 14 किसानों को जेल में डाला गया। हम अनशन पर बैठे रहे। जेल के अन्दर किसी से मिलने नहीं दिया गया। अब वे लोग एस०वाई०एल० नहर की बात करते हैं। माननीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी एस०वाई०एल० नहर के निर्माण के लिए पैदल चले। हमने भी पैदल यात्रायें की, पार्लियामैंट का घेराव किया और संघर्ष किया। इस मुद्दे पर जिन लोगों ने संघर्ष नहीं किया बल्कि जिन्होंने संघर्ष को दबाने का प्रयास किया वे केवल झूठी वाहवाही लूटने और मगरमच्छी आंसू बहाने का कार्य करते हैं। यह उनके लिए शर्म की बात है। जहां तक पीने के पानी की बात है पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट ने हमारे यहां काफी बोर करवाये हैं। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हांसी बुटाना लिंक नहर के निर्माण में देरी होने के कारण हमको पानी पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। जो वहां पर नहर की स्कीम के अंतर्गत हम पम्प लगाना चाहते थे और उनके माध्यम से पानी पहुंचाना चाहते थे यह काम अभी नहीं हो पाया है और वहां पर हमारे उन गांवों में बोर भी बंद हो गये हैं इसलिए हम चाहते हैं कि उन 30-40 गांवों में जो बोर बंद पड़े हैं उनको चालू करवाया जाये। सम्बंधित गांवों की लिस्ट मैं अलग से माननीय मंत्री महोदय को दे दूंगा। जहां तक स्वास्थ्य विभाग का सम्बन्ध है, इस बारे में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अटेली में एक 50 बैड का हॉस्पिटल बनाने की मंजूरी दी है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इसके अतिरिक्त हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे यहां डॉक्टर नहीं रुकते। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहूँगा कि ये जो मेवात और महेन्द्रगढ़ जैसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो भी अधिकारी या कर्मचारी चाहे वह किसी भी विभाग का हो, वहां पर बदली होकर जाता है तो वह यह समझता है कि मैं तो सज़ा याफ्ता हूं। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इस समस्या का कोई ऐसा हल निकाला जाये, कोई ऐसा तोड़ बनाया जाये कि जिससे वहां पर नियुक्त कर्मचारी और अधिकारी वहां से ट्रांसफर न करवा सकें वे एक निर्धारित समय सीमा तक या जब तक उनकी जगह कोई दूसरा कर्मचारी या अधिकारी वहां पर नहीं आ जाये तब तक तो वहां रहें ही। वहां पर दूसरे जो भी डिपार्टमैंट हैं उनके अन्दर भी बहुत से पद खाली पड़े हैं और वे ज्यादातर खाली ही रहते हैं। इसके लिए भी कोई कारगर पॉलिसी सरकार के स्तर पर बनाई जानी चाहिए। इस बारे में अगर सरकार के स्तर पर कोई कारगर कदम उठाये जायेंगे तो इससे वहां की जनता को

काफी सहूलियतें होंगी। इसके लिए सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को स्पैशल प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए। हमारा एक गाँव कांटी खेड़ी है जोकि निमराणा से सटा हुआ है। जब मुख्यमंत्री जी यहां पर आये थे, उस समय भी मैंने जिक्र किया था कि निमराणा में कोई बड़ा उद्योग लगाया जा सकता है या इसको औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जा सकता है।

श्री सभापति : नरेश यादव जी, आप वाईंड-अप करें। आपका समय समाप्त हो रहा है। बाकी आप जो कहना चाहते हैं वह लिखकर भिजवा दें।

श्री नरेश यादव : सभापति महोदय, हमारे इलाके की तीन-चार मुख्य सड़कें हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कई बार उन पर चर्चा हो चुकी है लेकिन ध्यान नहीं दिया गया, उनको जरूर बनवाया जाये। हमारी नहरों पर 4-5 आऊट ऑफ नार्म पुल हैं जिनकी सुराणी में मंत्री जी घोषणा भी करके आये थे लेकिन उन पर कार्यवाही नहीं हुई। यह मैं लिस्ट आपको दे दूंगा इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार ने जो हाऊसिंग बोर्ड की स्कीम बनाई है यह बहुत ही अच्छी स्कीम है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जमीन एक्वायर करने में और मकान बनाने में बहुत लम्बा समय लगता है। शहरों में प्राईवेट कोलोनाईजर्स ने जमीन खरीद रखी है। हाऊसिंग बोर्ड अगर जमीन एक्वायर करके मकान बनाना भी चाहे तो उनके पास जमीन नहीं है। मेरा इस बारे में सुझाव है कि उन प्राईवेट लोगों के साथ कोलैबोरेशन करके हाऊसिंग बोर्ड के मकान जल्दी बनाकर गरीब आदमियों को दिये जा सकते हैं। गांव कटकई में 33 के०वी० का सब-स्टेशन लगाने की बहुत जरूरत है। इस बारे में मैंने मुख्यमंत्री जी के अटेली आगमन पर बात भी की थी क्योंकि हमारे 40-50 गाँव इससे जुड़े हुए हैं।

श्री सभापति : नरेश जी, आपका समय समाप्त हुआ अब आप बैठ जाईये। श्रीमती गीता भुक्कल जी अब आप बोलिए।

श्रीमती गीता भुक्कल (कलायत, अनु०जा०) : सभापति महोदय, बजट पर बोलने के लिए आपने मुझे जो समय दिया है सबसे पहले मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहूंगी जिन्होंने हरियाणा को देश का नम्बर एक राज्य बनाने का जो स्वप्न देखा, विकास का जो नक्शा उन्होंने अपने दिमाग में बनाया हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत ही कुशलता से उसका एक रोड़ मैप तैयार किया है जो कि आर्थिक विकास की सुदृढ़ नींव है। यह टैक्स फ्री बजट है। संविधान में जिस वैल्फेयर स्टेट का जिक्र है और वैल्फेयर स्टेट में जो कुछ होना चाहिए उसी के अनुरूप वित्त मंत्री महोदय ने अपना बजट पेश किया है इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहती हूं। जिस प्रकार से तीन साल से हमारी सरकार कार्य कर रही है, आज बहुत से राज्य हमारी पॉलिसियों का अनुसरण कर रहे हैं। कल ही छठे वेतन आयोग ने अपनी सिफारिश पेश की है। हमारे वित्त मंत्री ने उस काम के लिए अपने इस बजट में 1550 करोड़ रुपये का प्रावधान पहले से ही किया हुआ है। मैं समझती हूं कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से सरकारी कर्मचारियों को भी सभी सुविधाएं

[श्रीमती गीता भुक्कल]

देनी चाहिएं। महंगाई के हिसाब से उनकी तनख्वाह भी बढ़ाई जानी चाहिए। चाहे उनके लिए कार लोन की बात हो, हाऊसिंग लोन की बात हो, इन सब बातों का प्रावधान इस बजट में किया गया है। जब वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन दिया जा रहा है तो मैं एक बात जरूर करना चाहूंगी कि सिर्फ अच्छा वेतन देना ही हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए बल्कि कार्य में ऐफीशिएंसी भी जरूर होनी चाहिए। जो सरकारी कार्य प्रणाली में फाईलों को सरकाये जाने का सिस्टम है उसको हटा कर हाईटैक जमाने के हिसाब से जल्दी से जल्दी कार्य को निपटाना चाहिए, उनको पैंडिंग नहीं रखना चाहिए। 365 दिनों में अगर छुट्टियां काऊंट की जाएं तो यह छुट्टियां 200 से ऊपर बनती हैं और केवल मात्र 164 या 165 दिन हमारे पास बचते हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। मैं समझती हूं कि कर्मचारियों के वर्किंग आवर्ज को बढ़ाया जाना चाहिए और जो छुट्टियां हैं उनकी संख्या कम करनी चाहिए ताकि जो लटकता हुआ सिस्टम है उसको खत्म कर सकें और हम जो नई-नई परियोजनाएं लेकर यहां पर आ रहे हैं उनको लागू करके न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि पूरा देश तरक्की की राह पर चल सके। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने एस०सीज० के लिए जो प्रावधान बजट में किये है मैं उन पर चर्चा करूंगी। एस०सीज० के लिए सबसे पहले कम्पोनैंट प्लान में जो घोषणा की गई है मैं उस पर बात करूंगी। हरियाणा प्रदेश में हमारी पॉपुलेशन करीबन 19.35% है लेकिन इस पॉपुलेशन के लिए बजट में 21.55% राशि का प्रावधान अनुसूचित जातियों के लिए किया गया है। सभापति महोदय, इन लोगों को 100-100 गज के प्लॉट दिये जा रहे हैं, मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी तथा सरकार को बधाई देती हूं। दलित और मलिन बस्तियों के उत्थान के लिए सरकार की यह अनूठी योजना है कि जिस गांव की जनसंख्या में 50% एस०सीज होंगे उस गांव के विकास और उत्थान के लिए 50 लाख रुपये की राशि का विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। जैंडर बजटिंग का सिस्टम स्टार्ट किया गया है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि इन्दिरा गांधी पेयजल योजना के तहत हमारे आठ लाख परिवारों को टूटियां और पानी की टंकियां दी जाएंगी। इस योजना के तहत ज्यादातर गलियों में विभाग ने ईंटें उखाड़ कर पाईपलाईन के कनैक्शन्ज दिये हैं। एल०ए०डी०टी० के तहत 10-10 लाख रुपये जिस तरह से हमारे गांवों की गलियां बनाने के लिये दिये गये हैं इस बजट में इस चीज का भी प्रावधान किया जाए कि जो गलियां टूट गई हैं उनको बनवाया जाए। हमारी अनुसूचित जातियों की बस्तियों में जहां पर पाईपलाईन बिछाई गई हैं वहां की सारी गलियां टूट चुकी हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूं कि वहां पर हर गांव की गलियों को पक्का करने के लिए 10-10 लाख रुपये का प्रावधान विशेषरूप से करने की कृपा करें। सभापति महोदय, इसके अलावा हैल्थ चैकअप कैम्पस जो हमारे स्कूलों में और दूसरी जगहों पर लगाए जा रहे हैं उसके लिए भी मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार का धन्यवाद करती हूं। इसी तरह से एस०ई०जैड० की अगर मैं बात करूं तो एस०ई०जैड० की 92 परपोजल्ज हमारे पास है और उनमें से कई पर काम शुरू हो चुका है। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगी कि हमारे कैथल-जीन्द के बीच कलायत,

उचाना, नरवाना आदि क्षेत्र पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उन के विकास के लिए वहां पर एस०ई०जैड० बनाए जाने चाहिएं। जो इण्डस्ट्रियल मॉडल टाउन्ज बनाए जा रहे हैं वैसे ही इण्डस्ट्रियल मॉडल टाउन्ज हमारे पिछड़े हुए इलाकों में भी बनाए जाने चाहिएं। चेयरमैन सर, स्पोर्ट्स के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि स्पोर्ट्स को लेकर हमारी सरकार ने बजट में बहुत से प्रावधान किये हैं। हमारे जो खिलाड़ी हैं उनका मान-सम्मान हमारी सरकार ने किया है। हमारे कुछ अर्जुन अवार्डीज़ और द्रोणाचार्य अवार्डीज़ हैं, उनकी पैंशन का मामला काफी समय से पैंडिंग पड़ा है। इस बजट में हमारे जो अर्जुन और द्रोणाचार्य अवार्डीज़ हैं उनकी पैंशन की ओर भी ध्यान देना चाहिए। चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करूंगी कि इसके लिए बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान किया जाए तथा हमारे जो नेशनल अवार्डीज़ हैं उनको कम से कम एक-एक हजार गज के प्लॉट दिये जाने चाहिएं। चेयरमैन सर, डिस्ट्रिक्ट लैवल पर हमारी सरकार ने प्रियदर्शनी शगुन योजना स्टार्ट की है इसके लिए मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूं कि डिस्ट्रिक्ट लैवल पर पहले से ही इसके फण्ड्ज हमारी कमेटीज के पास होने चाहिएं। सभापति महोदय, वर्ष 2008 को हमारी सरकार ने शिक्षा वर्ष घोषित किया है। इसके बारे में मैं विशेष रूप से कहूंगी कि पढ़ना केवल नौकरी के लिए ही जरूरी नहीं होना चाहिए बल्कि अच्छा इन्सान बनने के लिए भी पढ़ाई-लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी है। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर व्यक्ति शिक्षित हो।

श्री अध्यक्ष : भुक्कल जी, अब आप कन्क्लूड करें।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the House be extended for 15 Minutes ?

Voices : Yes Sir.

Mr. Speaker : The time of the House is extended for 15 Minutes.

वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में ही कन्क्लूड कर दूंगी। 60 साल की आजादी के बाद भी आज हम स्कूलों से बच्चों के ड्रॉप आउट की बात करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ड्रॉप आउट की चिन्ता को सामने रखते हुए दलितों के लिए शिक्षा की जो योजना शुरू की है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं और उनका आभार प्रकट करती हूं। क्या ऐसे कारण हैं कि हमारे बच्चे स्कूल छोड़ कर जा रहे हैं? क्या उनको ऐसा माहौल नहीं मिल रहा है जिससे वे शिक्षा में रुचि दिखाएं? मैं यह कहना चाहती हूं कि बच्चों को माहौल के अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए।

[श्रीमती गीता भुक्कल]

हमारी सरकार ने इसके लिए जो प्रावधान किया है कि हम बच्चों को बस्ते और किताबें देंगे, इसमें हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समय पर सभी किताबें बस्तों में भर कर फर्स्ट समैस्टर में ही दे देनी चाहिएं ताकि माहौल के अनुरूप बच्चे शिक्षा के लिए अपनी तैयारी कर सकें। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो हमारे यहां कम्प्यूटर ट्रेनिंग के लिए जो कम्प्यूटरर्ज भिजवा रहे हैं, इनके साथ ही वहां पर कम्प्यूटर टीचर्ज भी होने चाहिएं। टीचर्ज में जो छुट्टियों का ट्रैंड चल गया है उसके लिए टीचर्ज ऐबसैंटलिज्म पर हमें पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में मैं अपनी हल्के की कुछ मांगों के बारे में कहना चाहती हूं। वर्ष 2008 को शिक्षा वर्ष घोषित किया गया है। कलायत जैसे पिछड़े हुए क्षेत्र में हम बरसों से कॉलेज की मांग कर रहे हैं। कलायत में कपिल मुनि कॉलेज के नाम से साढ़े नौ एकड़ क्षेत्र में कॉलेज चल रहा है। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगी कि सरकार इस कॉलेज का अधिग्रहण करे ताकि पिछड़े हुए क्षेत्र में शिक्षा के स्तर में सुधार किया जा सके। वहां पर आई०टी०आई० का निर्माण करने की घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, उसको भी अतिशीघ्र अमली जामा पहना कर आई०टी०आई० का निर्माण कार्य शुरू किया जाए। कलायत क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिडल स्कूल बाता की घोषणा की थी। सरकार से मेरी यह प्रार्थना है कि इस मिडल स्कूल का कार्य भी अतिशीघ्र शुरू किया जाए। अध्यक्ष महोदय, कलायत के चारों तरफ से बरसात के पानी में डूबने का खतरा रहता है। वहां पर स्टोर्म वाटर की जो परियोजना हमने भेजी हुई है उसको भी मन्जूर करने की कृपा करें। डॉक्टर भीम राव अम्बेदकर मेधावी छात्र योजना में 10+1, 10+2 के अलावा टैक्नीकल एजूकेशन को भी जोड़ा जाए। धन्यवाद।

विधान कार्य

दी पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्किट्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2008

Mr. Speaker : Hon'ble Members now, the Agriculture Minister will introduce the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill, 2008 and will also move the motion for its consideration.

Agriculture Minister (Sardar H.S. Chatha) : Sir, I beg to introduce the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill, 2008.

Sir, I also beg to move—

> That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clauses 2 to 14

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 14 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Agriculture Minister will move that the Bill be passed.

Agricultural Minister (Sardar H.S. Chatha) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दी हरियाणा कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजिज बिल, 2008

Mr. Speaker : Hon'ble Members now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Compulsory Registration of Marriages Bill, 2008 and will also move the motion for its consideration.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Compulsory Registration of Marriages Bill, 2008 and will also move the motion for its consideration.

Sir, I also beg to move—

> That the Haryana Compulsory Registration of Marriages Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Haryana Compulsory Registration of Marriages Bill be taken into consideration at once.

डॉ० सुशील इन्दौरा (ऐलनाबाद, अनु०जा०) : माननीय अध्यक्ष जी, विवाह अनिवार्य पंजीकरण बिल आज सदन में लाया गया है। विवाह एक सामाजिक धर्म है। इस सामाजिक धर्म पर एक सामाजिक ढांचे का निर्माण होता है, जोकि भावी पीढ़ी के उद्देश्यों को पूरा करता है। अध्यक्ष महोदय, बिल किसलिए लाया जाता है, इसके कारणों का मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, एक केस सीमा बनाम अश्वनी सर्वोच्च न्यायालय में गया है। वह इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में गया है, क्योंकि कहीं न कहीं पर उनमें विवाद पैदा हो गया था। अध्यक्ष महोदय, विवाह हमारी एक परम्परा है। परम्पराओं और रीति-रिवाजों के लिए लोग इकट्ठे होते हैं। वधू पक्ष और वर पक्ष के लोग इकट्ठे होते हैं। वहां पर फैसले होते हैं और एक दूसरे के बारे में जांच पड़ताल भी करते हैं।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, जांच-पड़ताल और फैसले तो इकट्ठे होने से पहले होते हैं।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सर, आपकी बात ठीक है। यह परम्परा सदियों से एक समाजिक ढांचे के निर्माण के लिए और भावी पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए चलती आ रही है। लेकिन ऐसे क्या कारण बने कि यह बिल सदन में लाना पड़ा। स्पीकर साहब, यह अच्छी बात है कि शादी की रजिस्ट्रेशन हो जाए लेकिन क्या विवाद पैदा हो गये, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। स्पीकर साहब, मैं विशेषकर

हरियाणा प्रदेश की बात करूंगा। जिस तरह से आजकल खापों के फैसले आते हैं तो कहीं पर कोई बंदिश नहीं है कि वे अन्तर्जातीय शादी न करें। हमारे प्रदेश में भी तो गांव के गांव में ही शादियां हो जाती हैं।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, ऐसा कौन सा गांव है?

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, बहुत से ऐसे गांव या शहर हैं जिनमें शादियां हो जाती हैं।

श्री नरेश मलिक : स्पीकर साहब, चौटाला गांव के अंदर ऐसा हो जाता है। चौधरी रणजीत सिंह की ससुराल का गांव है मैंने उनसे वहां के बारे में पूछा था कि क्या वहां पर गांव के गांव में रिश्ते हो जाते हैं तो उन्होंने कहा हाँ जी, वहां गांव के गांव में रिश्ते हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, दहलीज तो छोड़ते होंगे।

श्री नरेश मलिक : स्पीकर साहब, दहलीज क्या वे फर्श भी नहीं छोड़ते हैं।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है इसलिए इसको मजाक में न लिया जाए। इसकी महत्ता पर गौर करना जरूरी है। ऐसी परम्पराएं भी हैं कि शहर के शहर में भी शादियां हो जाती हैं। किसी-किसी धर्म में तो कुछ नज़दीकी रिश्तेदारी को छोड़कर शादी हो जाती हैं। हमारे यहां हरियाणा में यह परम्परा है कि हम तीन-तीन गोत्र यानी खुद का गोत्र, दादी का गोत्र और माँ का गोत्र छोड़कर रिश्ते कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों आपने भी देखा होगा कि खापों के फैसले आ रहे हैं इसलिए मेरा कहना यह है कि इनको हमें कानून की परिधि में लाना चाहिए। जो इस तरह से खापों के फैसले आ रहे हैं वह गलत हैं क्योंकि इस से गांव के गांव में आपस में दुश्मनी होगी और कोर्ट में भी इस तरह के मामले गए हैं। स्पीकर साहब, मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं कहना चाहता हूं लेकिन मेरा इस बारे में एक सुझाव है। जिस तरह से ये विवाद हुए हैं, दुश्मनी बढ़ी है, जिस तरह से 302 और 307 तक के मुकदमें बने हैं यहां तक कि मर्डर्ज भी हुए हैं, उसके बाद इस मामले में गौर करना और भी जरूरी है और सामाजिक ढांचे को मजबूत करने के लिए एक सामाजिक अध्ययन की भी जरूरत है। समाज के लोग इकट्ठे होकर इसकी स्टडी करें और सरकार भी लोगों से पूछें कि बताओ कि कौन-कौन से गोत्र छोड़कर कानून की परिधि में लाएं ताकि इस तरह के विवाद खत्म हों। स्पीकर साहब, आने वाले वक्त में हमने समाज को आगे बढ़ाना है, समाज की नींव रखनी है। यह भाई चारे का सिम्बल भी है। (विघ्न) क्या यह सुझाव नहीं है कि आज इस बारे में एक सामाजिक अध्ययन की जरूरत है? स्पीकर साहब, या तो सरकार समझ नहीं पा रही है या फिर मैं समझा नहीं पा रहा हूं। समाजसेवी लोगों को इकट्ठे होकर बताना चाहिए कि हमें कितने गोत्र छोड़ने चाहिएं, हमें नानी, दादी या माँ के गोत्र छोड़ने चाहिएं। स्पीकर साहब, कहीं पर दो गोत्र भी छोड़ते हैं और कहीं

[डॉ० सुशील इन्दौरा]

पर तीन गोत्र भी छोड़ते हैं तो गोत्र के आजकल विवाद सामने आ रहे हैं। स्पीकर साहब, कई बार तो मौहल्ले के मौहल्ले में ही विवाह हो जाते हैं। प्रेम विवाह भी होते रहे हैं जिनको माननीय न्यायालय ने भी ठीक माना है। लेकिन जब प्रेम विवाह का विवाद गांवों में छिड़ जाता है तो इससे दुश्मनी पैदा हो जाती है इसलिए अच्छे विवाह का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जरूरी यह भी है कि सामाजिक अध्ययन के साथ-साथ सरकार सारे ज्ञानी-ध्यानी लोगों से सुझाव भी ले। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे गरीब तबकों में खासकर विवाह के नियमानुसार 18 और 19 साल की उम्र शादी की होनी चाहिए। लेकिन गरीब तबके के लोग छोटी उम्र में ही अपने बच्चों की शादी कर लेते हैं क्योंकि उनमें सामाजिक सुरक्षा का भय रहता है। वे इस भय के कारण ही यह सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके बच्चे अपना घर-बार बसा लें। अध्यक्ष महोदय, इसलिए विवाह का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। सरकार को कोई ऐसी स्कीम, ऐसे इन्सैंटिव लेकर आने चाहिएं जिससे गरीब तबके के लोगों में, अनुसूचित जातियों के लोगों में एक सामाजिक सुरक्षा की भावना पैदा हो और वे अपने बेटे एवं बेटियों को पढ़ाने का काम करें न कि उनको मजदूरी पर लगाने का काम करें। अगर सरकार ऐसा करती है तो इससे हमारे देश के नौजवानों में अनपढ़ता भी कम होगी, बेरोजगारी भी नहीं बढ़ेगी और सामाजिक सुरक्षा भी बढ़ेगी। (विघ्न) मंत्री जी, ब्याह होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा या पहले ही कर लोगे। हमें इसके लिए कुछ न कुछ तो कदम उठाने ही पड़ेंगे। आप भले आदमी हैं, समझदार आदमी हैं इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अगर बच्चे पहले शादी करेंगे तभी तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर उनको सरकार की तरफ से पहले से ही इन्सैंटिव नहीं मिलेंगे तो फिर वे क्या करेंगे? इसलिए मेरा सरकार से कहना है कि वह ऐसी स्कीम्ज बनाएं ताकि उम्र के हिसाब से भी ठीक हो और उनका रजिस्ट्रेशन भी हो।

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : स्पीकर सर, क्या ये चाईल्ड मैरिज को एनकरेज कर रहे हैं?

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, या तो ये मेरी भावना को नहीं समझ पा रहे हैं या मैं इनको अपनी बात समझा नहीं पा रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि गरीब आदमी में सामाजिक सुरक्षा की भावना पैदा हो, इसलिए यह रजिस्ट्रेशन एक्ट सरकार लेकर आई है इसमें रजिस्ट्रेशन तो हो लेकिन जो लोग वक्त से पहले अपने बच्चों की शादियां कर देते हैं। वह न हो सके, ऐसा प्रावधान इसमें किया जाना चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अंडर एज मैरिजेज के लिए अलग से कानून है। आपने इस बारे में यही सुझाव दिया है कि बुद्धिजीवियों से सुझाव इस बारे में ले लें। आप हमें बुद्धिजीवियों की लिस्ट दे देना फिर हम सुझाव ले लेंगे।

श्री नरेश मलिक (हसनपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में केवल एक सुझाव देना चाहूंगा कि आजकल 18 वर्ष के नौजवान साथियों को वोट डालने का अधिकार

है। कई बार पारिवारिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि किसी का एक बेटा है तो वे 18 साल की उम्र में ही उसकी शादी कर देते हैं और इस एक्ट के तहत उसकी आयु 21 वर्ष रखी गई है। इस बारे में मैं अपना ही उदाहरण बताता हूं। मैं अपने पिता का जेठा बेटा हूं। मेरी शादी साढ़े अठारह साल की उम्र में हो गई थी। क्योंकि मेरी दादी का ऑपरेशन होना था और वह कहने लगी कि ऑपरेशन से पहले इसकी शादी कराऊंगी। मेरा निवेदन है कि इसको 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया जाए। जब आप वोट का राइट दे रहे हैं तो इसमें भी कर सकते हैं।

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : भारत सरकार के स्तर पर इस मुद्दे पर बड़ी गंभीरता से विचार हो रहा है। उसका रिजल्ट क्या आएगा यह तो नहीं पता लेकिन भारत सरकार के स्तर पर इस बारे में विचार हो रहा है।

श्री नरेश मलिक : केन्द्र सरकार में तो ज्यादा समय लगेगा। आप कानून बना दोगे और महामहिम राज्यपाल महोदय के दस्तखत उस पर हो जाएंगे तो वह प्रदेश के लिए कानून बन जाएगा। मेरा सुझाव है कि प्रदेश सरकार 18 साल की आयु करे अन्यथा समाज में बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। वैसे ही बच्चे ब्याहे नहीं जाते, फिर यह रजिस्ट्रेशन अड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। एकाध रिश्ता हो जाता है वह भी नहीं होगा।

श्री राधे श्याम शर्मा अमर (नारनौल) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिल तो अच्छा है। विवाह का रजिस्ट्रेशन तो होना चाहिए। मेरे एरिया में तो 6-6 महीने के बच्चों की शादी हो जाती है इससे उन पर रोक लगेगी। लेकिन मैं इस बारे में सुझाव देना चाहता हूं कि विवाह की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाए।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय पांच मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : जी हां।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। हाउस का समय पांच मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

दी हरियाणा कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजिज बिल, 2008
(पुनरारम्भ)

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, विवाह के पंजीकरण कानून का बिल सरकार लेकर आई है। इस पर माननीय इन्दौरा साहब, नरेश मलिक और

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
राधे श्याम शर्मा जी ने अपने-अपने सुझाव दिये हैं। इन्दौरा साहब ने एक चिन्ता बड़ी वाजिब फरमाई कि पूरे प्रदेश के अंदर चाइल्ड मैरिज रुकनी चाहिएं। इस बारे में मुझे नहीं लगता कि पूरे सदन के किसी सदस्य के लिए यह विवाद का विषय हो। इससे हम सब सहमत हैं। दूसरा मुद्दा जो उन्होंने उठाया है वह यह है कि हमारे समाज के धरातल से जो समस्याएं हैं वह उससे जुड़ी हुई हैं। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की जरूरत क्यों पड़ी। जो बात माननीय सदस्यों ने कही है पहले मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा और फिर अपनी बात कहना चाहूंगा। उन्होंने एक तो यह कहा है कि हमारे समाज के अंदर कई भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। अंतर्जातीय विवाह है उसके अंदर बहुत सारे विवाद होते हैं। कई बार जब अन्तर्जातीय विवाह के विवाद होते हैं अगर दोनों पक्षों में से एक पक्ष के अभिभावकों को, उनके परिवार के अन्य सदस्यों को मन्जूर न हो तो कई बार क्रिमिनल वारदातें भी होती हैं। जिसमें 307 और 302 की वारदातें भी हुई हैं। दूसरे इस बिल का एक पहलू और भी है जिसकी चर्चा इन्होंने की है कि सामाजिक समरसता किस प्रकार की हो। सामाजिक समरसता ऐसी हो कि समाज के जो अपने नियम हैं उनमें और कानून की जो परिधि है इन दोनों में समन्वय बन सके, इस प्रकार का चिन्तन करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से सदन को और माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि इन तीनों बातें और चाईल्ड मैरिज को लेकर सरकार सजग है। ऐसी बुराईयां जिससे पूरे समाज का अहित होता है, उसको लेकर सरकार पूरी तरह से सजग है और अन्तर्जातीय विवाह के बारे में इन्होंने कहा कि किस प्रकार से गरीब समाज के लोग और उनके बच्चे बच्चियां अन्तर्जातीय विवाह करते हैं। उनको सरकार कैसे एनक्रेज करके प्रोत्साहन दे यह भी सरकार को सोचना चाहिए। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार ने जो इन्टर कास्ट मैरिज करेंगे उनके लिए विशेष प्रोत्साहन की राशि रखी हुई है। इससे पहले मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जब श्रीमती सोनिया गांधी पहली बार हरियाणा में आई उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीन्द में इन्दिरा प्रियदर्शनी विवाह शगुन नामक योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत खासतौर से हमारे एस०सी० भाईयों की हमारी बहनें और बच्चियां हैं, जो इन्टर कास्ट मैरिज करेंगी उनको विवाह के शगुन का तोहफा 15 हजार रुपये की राशि सरकार की तरफ से देकर उनको एन्क्रेज किया जायेगा। इसी प्रकार से लाडली स्कीम है। इसी प्रकार से हमारी सरकार का लक्ष्य है कि लिंग अनुपात ठीक रहे। लिंग अनुपात जैसी विषमता न हो जैसा कि मलिक साहब ने चर्चा की कि लड़कियां उपलब्ध नहीं हैं। लड़कों की संख्या ज्यादा है और लड़कियों की संख्या कम है। इस विषमता को पाटने में भी इससे मदद मिलेगी। हरियाणा में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने लाडली को एक अनोखी स्कीम बनाया है। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई इन्टर कास्ट मैरिज करता है तो सरकार उसे 50 हजार रुपये की राशि इन्टर कास्ट मैरिज करने के लिए देती है ताकि वह प्रोत्साहित हो। हम नहीं चाहते कि लड़के लड़कियां जाति के दायरे में पूरी जिन्दगी इतने संकीर्ण रहें और अपनी जाति के बाहर निकलकर शादी न कर पायें। सरकार की नीयत और नीति है कि इन्टर कास्ट विवाह के लिए सरकार ने 50 हजार रुपये की

राशि जो ग्रान्ट के तौर पर रखी है इसमें से 20 हजार रुपये की राशि कैश दी जायेगी और 30 हजार रुपये की राशि छः साल की फिक्स डिपोजिट के तौर पर दी जायेगी। यह सरकार ने स्कीम बनाई है। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री महोदय सजग हैं। जहां तक सामाजिक समरसता का प्रश्न है कानून की अपनी प्रक्रिया होगी। एक जगह ऐसा हुआ कि लड़की के अभिभावकों ने बच्चे को ले लिया और वापिस नहीं दे रहे थे। इसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने इन्टरवीन किया और पुलिस ने भी इन्टरवीन किया और हमने बच्चे को वापिस दिलवाया और उनको प्रोटैक्शन दिलवाया। इसलिये सामाजिक समरसता और कानून की परिधि दोनों का समन्वय बनाने की जरूरत है। इस बात से हम पूर्णतया सहमत हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट के अनुरूप ही इस रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरीज बिल को लाये हैं। सुप्रीम कोर्ट का यही लक्ष्य था कि जो भ्रान्तियां फैलती हैं कि बच्चे अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं, वह शादी बाकायदा कानून के अनुसार हो इसलिए यह बिल लाये हैं।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय 5 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

दी हरियाणा कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजिज बिल, 2008
(पुनरारम्भ)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि राधेश्याम शर्मा जी ने और मलिक साहब ने कहा है, इसके बारे में चौधरी बीरेन्द्र सिंह पहले ही जवाब दे चुके हैं कि भारत सरकार इस बारे में विचार कर रही है क्योंकि यह नई पॉलिसी का विषय है। अब प्रान्त टू प्रान्त तो यह नहीं बदल सकते हैं। यह तो कोहिसीव नेचूरल पॉलिसी रही है और हमेशा रहेगी। इसके लिए आगे भी गम्भीर चिन्तन चल रहा है। मुझे लगता है कि लड़के और लड़की की आयु में कोई फर्क नहीं है। भारत सरकार इस बारे में जल्दी ही वैसा ही निर्णय लेगी जैसा राधेश्याम शर्मा जी ने कहा है। हमारी राय भी यही है कि लड़की की आयु मैरिजेबल 18 साल है तो लड़के की आयु भी वही हो सकती है। परन्तु सरकार यह चाहेगी कि इस बारे में नेशनल लैवल पर एक कोहिसीव पॉलिसी बने। We will also follow that, अदरवाइज पंजाब में कुछ और है, हिमाचल में कुछ और है, चण्डीगढ़ में कुछ और है और हरियाणा में कुछ और है।

जब भी वह निर्णय लिया जाएगा इससे कंट्राडिक्शन ऑफ टर्म्स आएगी। We can always bring amendments. इसके साथ-साथ मेरा अनुरोध है कि इस कानून को पारित कर दिया जाए।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Compulsory Registration of Marriages Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause 2 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause 2 of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 3 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause 3 of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 21

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 21 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 1 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause 1 of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House is adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 26th March, 2008.

*13.52 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Wednesday, the 26th March, 2008).

44537-H.V.S.—H.G.P., Chd.